राष्ट्रीय संस्करण

डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी बनीं कमला हैरिस

>> 11

वर्ष 8 अंक 76

दैनिक जागरण

मूल्य ₹8.00 नई दिल्ली, शनिवार, 24 अगस्त, 2024

www.jagran.com

पृष्ठ 14

तटस्थ नहीं भारत, हमेशा शांति के साथ : मोदी

- ऐतिहासिक यात्रा पर यूक्रेन पहुंचे मोदी, राष्ट्रपति जेलेंस्की से हुई वार्ता,
- कीव में युद्ध में मारे गए बच्चों की स्मृति में बने संग्रहालय में भावुक हुए पीएम
- कहा–शांति के लिए भारत हरसंभव मदद को तैयार, व्यक्तिगत प्रयास भी करूंगा

जयप्रकाश रंजन • जागरण

नई दिल्ली: यूक्रेन की यात्रा पर शुक्रवार सुबह कीव पहुंचे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक बार फिर युद्धरत रूस और यूक्रेन को शांति का संदेश दिया है। रूस की यात्रा के ठीक छह हफ्ते बाद यूक्रेन पहुंचे मोदी ने वैश्विक समुदाय को संदेश दिया कि भारत दो वर्षों से चल रहे रूस-यूक्रेन युद्ध में तटस्थ नहीं है। भारत हमेशा शांति के साथ रहा है। राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ मुलाकात के दौरान भी मोदी ने रूस-यूक्रेन के बीच सीधी बातचीत का आह्वान किया, ताकि युद्ध समाप्त किया जा सके। मोदी-जेलेंस्की के बीच वार्ता के बाद संयुक्त बयान जारी किया गया। इसमें भारत ने यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता व संप्रभुता के आदर की बात कही। दोनों देशों में सैन्य-तकनीक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की बैठक फिर से शुरू करने पर सहमति बनी है।

मोदी ने स्वयं इस यात्रा को ऐतिहासिक करार दिया। पहला कारण तो यह है कि वर्ष 1991 में यूक्रेन के स्वतंत्र देश बनने के बाद पहली बार किसी भारतीय पीएम ने वहां का दौरा किया है। दूसरा, मोदी ऐसे पहले वैश्विक नेता हैं, जिन्होंने कुछ ही दिनों के अंतर में रूस के साथ यूक्रेन की यात्रा की है। उन्होंने दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के साथ न सिर्फ द्विपक्षीय वार्ता की, बल्कि उन्हें शांति का संदेश भी दिया है। पोलैंड से रेल मार्ग से कीव पहुंचे पीएम मोदी का राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मौजूदा तनाव भरे माहौल के बावजूद शानदार स्वागत किया। दोनों नेताओं ने युद्ध में मारे गए बच्चों की स्मृति में निर्मित संग्रहालय का दौरा किया। वहां प्रदर्शित फिल्म को देख कर मोदी भावुक हो गए। उन्होंने कहा,बच्चों की स्मृति में बने म्यूजियम को देखा। मेरा मन भरा हुआ है। दिल को गहरी चोट लगी है। मुझे लगता है कि युद्ध का पहला शिकार बालक बनते हैं। यह बहुत दर्दनाक है। किसी भी सभ्य समाज में ऐसी घटनाएं स्वीकार नहीं की जा सकतीं।

शनिवार (24 अगस्त) को यूक्रेन का राष्ट्रीय दिवस है, जिस पर मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति और वहां की जनता को 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से शुभकामना दी। मोदी की जेलेंस्की से पहली भेंट नवंबर, 2021 में हुई थी और तभी उन्हें यूक्रेन आने का निमंत्रण मिला था। फरवरी, 2022 से रूस-यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। मोदी ने कहा,तब मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि ऐसे हालात में यूक्रेन की यात्रा करनी होगी। तनावपूर्ण माहौल के बावजूद दोनों देशों के रिश्तों में प्रगति हो रही है जो बताता है कि हम परिपक्वता से रिश्तों पर काम कर रहे हैं। मोदी ने जेलेंस्की को भारत आने का निमंत्रण दिया और कहा, इस संकट की घड़ी में भारत ने जितना हो सका है, उतनी मदद का प्रयास किया है। आपको विश्वास दिलाता हूं कि मानवीय दृष्टिकोण से जिस तरह की भी जरूरत यूक्रेन को होगी,भारत साथ खड़ा होगा और दो कदम आगे चलेगा। हम युद्ध से दूर रहे हैं, पर इसका अर्थ यह नहीं कि हम तटस्थ रहे हैं। हम पहले दिन से ही पक्षकार रहे हैं। हमारा पक्ष शांति का है। शांति के लिए भारत हरसंभव मदद को तैयार है। इसके लिए मैं व्यक्तिगत प्रयास भी करूंगा।

(संबंधित खबरें पेज-11 पर)

कीव में मृत बच्चों को समर्पित स्मारक पर शुक्रवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ पीएम नरेन्द्र मोदी। प्रेट्र

यात्रा

प्रकृति दर्शन संग पुण्यार्जन को पधारिए अमरकंटक

शहडोल: पर्वत, वन, सरिता और हरियाली के अदभुत संगम को निहारने की उत्कंठा है तो अमरकंटक पहुंच जाएं। इसे स्थान को तीर्थराज भी कहा जाता है। ऐसे में प्रकृति दर्शन संग पुण्यार्जन को पधारिए अमरकंटक। (पेज-7)

संपादकीय

राजनीतिक विमर्श में गिरावट: गिरते राजनीतिक विमर्श का एक कारण यह भी है कि सत्तापक्ष एवं विपक्ष में संवादहीनता आ गई है। **डा. एके वर्मा** का दृष्टिकोण।

खुद कठिनाई में संकट का साथी: यह विचित्र है कि आज तक हम पुलिसकर्मियों की सेवा शर्तों को मानवीय नहीं बना पाए हैं। **डा. ब्रजेश कुमार तिवारी** का सुझाव। • पेज 8

विमर्श

प्रशासनिक सेवाओं में लेटरल एंट्री के मायने: संघ लोक सेवा आयोग ने केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 45 पदों पर नियुक्ति के लिए लेटरल एंट्री के माध्यम से भर्ती की प्रक्रिया शुरू की थी। परंतु विवाद उत्पन्न होने पर सरकार ने फिलहाल अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। ऐसे में लेटरल एंट्री के निहितार्थ को रेखांकित कर रहे हैं, **कैलाश बिश्नोई**।

सही हाथों तक लाभ पहुंचाने की योजना: सरकारी सेवा और योजना का लाभ सही तरीके से सही लोगों तक पहुंचे, इसके लिए बिहार सरकार ने नागरिकों का परिवार आधारित सोशल रजिस्टर बनाने की बड़ी पहल की है। **सुनील राज** की डायरी। • पेज-9

सीमा पार कर पाकिस्तान में गिरा भारतीय सेना का मिनी ड्रोन

नई दिल्ली: भारतीय सेना का एक मिनी ड्रोन शुक्रवार को तकनीकी खराबी के कारण दिशा बदलकर पाकिस्तान के निकियाल सेक्टर में चला गया। पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय यूएवी को कब्जे में ले लिया। भारत ने तत्काल हाटलाइन पर पाकिस्तान को सूचना देते हुए इसे वापस लौटाने को कहा है, लेकिन अभी तक पाकिस्तानी सेना ने यूएवी लौटाने का कोई संकेत नहीं दिया है। (पेज-6)

बांग्लादेश में शेख हसीना का डिप्लोमैटिक पासपोर्ट रद

ढाका: बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शुक्रवार को अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना का डिप्लोमैटिक पासपोर्ट रद कर दिया। हसीना मंत्रिमंडल में शामिल रहे अन्य लोगों के पासपोर्ट भी सरकार ने रद कर दिए हैं। पांच अगस्त को पद और देश छोड़ने के बाद से हसीना भारत में हैं। (पेज-11)

आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले की जांच भी सीबीआइ करेगी

कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया आदेश, अभी बंगाल सरकार की बनाई एसआइटी कर रही जांच

- अदालत ने कहा-कई एजेंसियों की जांच जटिल व लंबी हो सकती है

राज्य ब्यूरो, जागरण • कोलकाता

महिला डाक्टर से दुष्कर्म व हत्या के मामले की जांच कर रही सीबीआइ अब आरजी कर मेडिकल कालेज एवं अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डा. संदीप घोष के खिलाफ वित्तीय भ्रष्टाचार मामले की परतें भी खोलेगी। अभी बंगाल सरकार द्वारा बनाई गई एसआइटी मामले की जांच कर रही है। कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज ने शुक्रवार को भ्रष्टाचार मामले की जांच भी सीबीआइ से कराए जाने का आदेश दिया।

पूर्व प्रिंसिपल संदीप ने आदेश के खिलाफ खंडपीठ में लगाई गुहार

डा. संदीप घोष ने आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी है।

वित्तीय भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की गई हैं। मामले की जांच के लिए ममता सरकार ने अचानक 20 अगस्त को एसआइटी का गठन किया था, जबकि शिकायत एक वर्ष पहले की गई थी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एसआइटी के गठन में इतनी देरी को लेकर भी सवाल उठाए। जस्टिस भारद्वाज ने कहा, सीबीआइ महिला चिकित्सक हत्याकांड की जांच कर रही है। उसे वित्तीय भ्रष्टाचार की भी जांच करनी चाहिए। कई एजेंसियों द्वारा जांच जटिल व लंबी हो सकती है। याचिकाएं संदीप घोष के पूर्व सहकर्मी अख्तर अली व वकील सुष्मिता साहा दत्ता ने दायर की हैं। अख्तर ने टेंडर में पक्षपात, बायोमेडिकल कचरे की अवैध बिक्री, कमीशन लेने और पैसे लेकर मेडिकल छात्रों को पास करने के आरोप लगाए हैं।

आरोपित के साथ दोस्त का भी होगा पालीग्राफ टेस्ट पेज>>5

आरोपित की वकील बोलीं- ...तो नहीं करती पैरवी : पेज>>5

'एससी-एसटी एक्ट तभी लागू होगा जब अपमानित करने की मंशा हो'

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि एससी-एसटी एक्ट के तहत अपराध सिर्फ इस आधार पर स्थापित नहीं होता कि शिकायतकर्ता अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) का सदस्य है, अपराध तब तक नहीं जब तक कि उसे अपमानित करने का इरादा न हो। जस्टिस जेबी पार्डीवाला व मनोज मिश्रा की पीठ ने यह टिप्पणी यू-ट्यूबर शाजन स्कारिया को अग्रिम जमानत देते हुए की जो 'मरुनंदन मलयाली' नामक चैनल संचालित करते हैं। (पेज-7)

दैनिक जागरण सप्तरंग

जोश नई राहों का

सकारात्मक दृष्टिकोण का सुफल

करें करियर की प्लानिंग • पेज-13

नेपाल में महाराष्ट्र के श्रद्धालुओं से भरी बस नदी में गिरी, 27 की मृत्यु

- पोखरा से काठमांडू जाते समय मुग्लिंग मार्ग पर तनहुं जिले में हुआ हादसा
- गंभीर रूप से घायल 12 यात्री उपचार के लिए हेलीकाप्टर से काठमांडू भेज गए

जागरण टीम, गोरखपुर

तीर्थ यात्रा पर निकले महाराष्ट्र के श्रद्धालुओं की एक बस शुक्रवार को नेपाल में मर्स्यांगदी नदी के किनारे 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। बस में 43 लोग सवार थे, जिनमें 27 की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल 12 यात्रियों को हेलीकाप्टर से काठमांडू ले जाया गया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक सभी यात्री जलगांव जिले के रहने वाले हैं।

गोरखपुर की ट्रेवल एजेंसी केसरवानी परिवहन से बुक कराई गई बस यूपी 53 एफटी 7623 शुक्रवार सुबह नेपाल के पोखरा से काठमांडू के लिए रवाना हुई। मुग्लिंग मार्ग पर करीब 11.30 बजे तनहुं जिले के आंबूखैरेनी में ऐनपहारा के पास हाईवे से फिसलकर मर्स्यांगदी नदी में गिर गई। चट्टान में बीच में आने के कारण बस नदी के तेज बहाव में जाने से बच गई।

नेपाल के तनहुं जिले में शुक्रवार को नदी में गिरी बस के परखच्चे उड़ गए। रायटर

यात्रियों की चीख-पुकार के बीच शुरू हआ राहत व बचाव का कार्य पेज>>6

****

3 माह में राजधानी में करंट लगने से 13 लोगों की मौत हुई तो विभिन्न स्थानों पर जलभराव के कारण डूबने से 10 लोगों की मौत हुई।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 24 अगस्त, 2024

आज का मौसम

शनिवार को आकाश में बादल छाए रहेंगे। कई इलाकों में हो सकती है हल्की वर्षा। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री पहुंचने के आसार हैं।

पूर्वानुमान	अधिकतम	न्यूनतम
दिल्ली		
24 अगस्त	34.0	27.0
25 अगस्त	33.0	27.0
नोएडा		
24 अगस्त	31.0	26.0
25 अगस्त	33.0	27.0
गुरुग्राम		
24 अगस्त	33.0	26.0
25 अगस्त	33.0	26.0

डिग्री सेल्सियस में

न्यूज गैलरी

छात्रों ने दोबारा व्यवस्थित कीं वरीयताएं, दूसरी सूची 25 को

नई दिल्ली : दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश के पहले चरण में शुक्रवार शाम पांच बजे तक छात्रों ने वरीयताएं दोबारा व्यवस्थित कीं। अब सीट आवंटन की दूसरी सूची 25 अगस्त को जारी की जाएगी। 27 अगस्त तक छात्र सीट आवंटन स्वीकार करेंगे। 30 अगस्त तक फीस जमा की जा सकेगी। 29 अगस्त से स्नातक की कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। पहले चरण में 65843 विद्यार्थियों के प्रवेश पूरे हो चुके हैं। 65843 छात्रों ने फीस जमा कर प्रवेश पक्का कर लिया है। (जासं)

रंजीत नगर में करंट लगने से महिला की मौत

नई दिल्ली : राजधानी में वर्षा के कारण जलभराव होने से पानी में डूबने और करंट लगने से मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब मध्य जिले के रंजीत नगर में शुक्रवार सुबह वर्षा के दौरान गली नंबर आठ में सड़क पर जमा पानी में करंट दौड़ने से सीमा की मौत हो गई। गली में आठ से दस इंच पानी जमा था, जिसमें पास स्थित एक मकान में लगी पानी की मोटर की अर्थिंग से करंट आ गया। महिला सीमा कपड़ों में प्रेस करने का काम करती थी। घटना के समय वह घरों से प्रेस के कपड़े लेकर अपने घर जा रही थी। (जासं)

स्थायी समिति के गठन का खुला रास्ता, दिए आदेश

नई दिल्ली : एल्डरमैन (मनोनीत पार्षद) की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर के बाद 18 दिन बाद महापौर ने वार्ड कमेटियों के चुनाव कराने के आदेश जारी कर दिए हैं। वार्ड कमेटियों के चुनाव के बाद ही स्थायी समिति के चुनाव होंगे। ऐसे में करीब डेढ़ वर्ष से लंबित वार्ड कमेटियों और स्थायी समिति के गठन का रास्ता अब खुल गया है। (जासं)

'केजरीवाल केस को सनसनीखेज बनाने की कर रहे कोशिश'

दिल्ली आबकारी नीति घोटाला

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में सीबीआइ ने केजरीवाल को जमानत देने का किया विरोध
- दूसरे मामले में जवाब देने के लिए मांग लिया समय, सुनवाई पांच सितंबर तक टली
- सीबीआइ ने कहा, गिरफ्तारी की जरूरत रिकार्ड में सामग्रियों के आधार पर पैदा हुई

अरविंद केजरीवाल। फाइल

सीबीआइ ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने का विरोध करते हुए उनकी याचिका खारिज करने का अनुरोध किया है। सीबीआइ ने कहा कि केजरीवाल केस को राजनीतिक रूप से सनसनीखेज बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वह दिल्ली आबकारी नीति, 2021-22 तैयार करने व लागू करने की साजिश में शामिल थे। दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी में सारे निर्णय उनके निर्देश पर लिए गए थे। यह बात सीबीआइ ने केजरीवाल की एक याचिका का विरोध करते हुए दाखिल ताजा हलफनामे में कही है, जबकि दूसरे मामले में जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांग लिया जिसके चलते सुनवाई पांच सितंबर तक टाल गई। यानी केजरीवाल को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने केजरीवाल को तत्काल अंतरिम जमानत देने से मना कर दिया था।

केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल की हैं। एक में दिल्ली हाई कोर्ट के सीबीआइ गिरफ्तारी को वैध ठहराने वाले आदेश को चुनौती दी है, जबकि दूसरी में जमानत मांगी है। दोनों में कोर्ट ने सीबीआइ को जवाब के लिए नोटिस जारी किया था। केजरीवाल को मनीलांड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है, अगर उन्हें सीबीआइ के केस में भी जमानत मिल गई तो वह जेल से बाहर आ जाएंगे। सीबीआइ ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था।

शुक्रवार को केजरीवाल की याचिकाएं जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई पर लगी थीं। सीबीआइ की ओर एडिशनल सालिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि उन्होंने एक मामले में जवाब दाखिल कर दिया है, लेकिन दूसरे मामले में दाखिल करना है इसके लिए कुछ और समय दे दिया जाए।

केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इन्होंने एक मामले में हलफनामा दाखिल किया है जिसकी प्रति उन्हें गुरुवार शाम आठ बजे मिली और दूसरे में नहीं किया। अब समय मांग रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने सीबीआइ का अनुरोध स्वीकार करके एक सप्ताह का समय दे दिया और केजरीवाल को प्रतिउत्तर दाखिल करने के लिए उसके बाद दो दिन का समय दिया।

सीबीआइ ने कहा कि केजरीवाल को किसी भी तरह की रिहाई या जमानत देने से केस के ट्रायल पर बुरा प्रभाव पड़ेगा जो अभी शुरुआती स्तर पर है और जिसमें अभी गवाहियां होनी हैं। सीबीआइ ने कहा कि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं। उनके पास कोई विभाग नहीं है, लेकिन उनके निर्देश और सहमति पर ही दिल्ली सरकार व पार्टी के सारे निर्णय लिए गए। वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। सीबीआइ ने कहा कि ईडी के केस में मिली जमानत का सीबीआइ के विशिष्ट केस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सीबीआइ ने केजरीवाल को चिकित्सीय आधार पर भी जमानत देने का विरोध किया।

मुख्यमंत्री व दुर्गेश पाठक के खिलाफ मुकदमा चलाने की मिली मंजूरी, सीबीआइ ने बताया

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआइ ने शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप विधायक दुर्गेश पाठक के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी ले ली गई है। सीबीआइ ने यह जानकारी विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष दी और अदालत ने मामले को 27 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया। इसी दिन केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त हो रही है। पिछली सुनवाई पर अदालत ने जांच एजेंसी को 15 दिन के अंदर मुकदमा चलाने की मंजूरी प्राप्त करने का समय दिया था। साथ ही सीबीआइ के आरोप पत्र के संज्ञान पर सुनवाई 27 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी थी।

अदालत ने यह आदेश तब दिया था जब जब जांच एजेंसी ने सूचित किया कि अभी तक संबंधित अधिकारियों से मंजूरी नहीं मिली है। सीबीआइ ने 28 जुलाई को मामले में अपना अंतिम और पांचवां आरोपपत्र दाखिल किया था। आरोप पत्र में सीबीआइ ने केजरीवाल, दुर्गेश पाठक, सरथ चंद्र रेड्डी, विनोद चौहान, आशीष माथुर और अमित अरोड़ा सहित छह आरोपितों को नामित किया है। सीबीआइ ने संकेत दिया है कि उसकी जांच पूरी हो गई है। केजरीवाल को आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था, जबकि भ्रष्टाचार मामले में सीबीआइ ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था। ईडी के मनी लांड्रिंग मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है, लेकिन सीबीआइ में केजरीवाल की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के कारण उनकी रिहाई नहीं हो सकी।

नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य के लिए सीएम ने दिए सात करोड़ रुपये

राज्य ब्यूरो, जागरण.नई दिल्ली: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने क्षेत्र में विकास कार्य कराने के लिए तिहाड़ जेल से सात करोड़ रुपये का फंड जारी किया है। केजरीवाल ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में फंड जारी करने की राउज एवेन्यू कोर्ट से अनुमति मांगी थी और कोर्ट ने अनुमति दे दी। अब इस फंड से नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में लाइब्रेरी, सीसीटीवी कैमरे, इंडोर-आउट डोर जिम के उपकरण, स्ट्रीट लाइटें, मोबाइल वैन, ड्रेनेज, आरसीसी रोड, सड़कों की मरम्मत समेत करीब 50 तरह के विकास कार्य किए जाएंगे। केजरीवाल ने अपनी टीम से अपील की है कि सारे विकास कार्य समय से पूरा करा लिए जाएं, ताकि क्षेत्र की जनता को कोई दिक्कत न हो गौरतलब है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल न्यायिक हिरासत में हैं। कई महीने से न्यायिक हिरासत में होने से सीएम केजरीवाल के निर्वाचन क्षेत्र नई दिल्ली में विकास कार्य बाधित हो रहे थे। जबकि जनता विभिन्न विकास कार्यों को लेकर लगातार आवेदन कर रही थी। इस फंड से गोल मार्केट, लोधी रोड, सरोजनी नगर इलाके में पोर्टा केबिन, लाइब्रेरी बनाई जाएंगी। कई जगहों पर सीसीटीवी, स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। ईस्ट किदवई नगर में नाला और बाउंड्री के कार्य होंगे। सार्वजनिक लाइब्रेरी के लिए मोबाइल वैन, खेल के उपकरण खरीदे जाएंगे।

पांच माह बाद फिर मिलनी शुरू हुई एक लाख बुजुर्गों को पेंशन

राज्य ब्यूरो, जागरण • नई दिल्ली

- वित्त मंत्री आतिशी का दावा केंद्र द्वारा अपने हिस्से का पैसा न देने से रुक गई थी पेंशन

आतिशी। सौजन्य दिल्ली सरकार

दिल्ली में पांच माह बाद एक लाख बुजुर्गों को पेंशन फिर मिलनी शुरू हो गई है। वित्त मंत्री आतिशी ने दावा किया है कि केंद्र द्वारा अपने हिस्से का पैसा न देने से ये पेंशन रुक गई थी। वित्त मंत्री ने कहा कि दिल्ली के चार लाख बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन मिलती है। इनमें से एक लाख बुजुर्गों को मिलने वाली ऐसी पेंशन है, जिसका कुछ हिस्सा दिल्ली सरकार से और कुछ हिस्सा केंद्र सरकार से आता है।

आतिशी ने शुक्रवार को प्रेसवार्ता कर कहा कि बुजुर्गों को अब पेंशन मिलनी शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि अब शहर के एक लाख लाभार्थियों में से 90,000 को गुरुवार को ही उनका पिछला बकाया मिल गया है। बाकी लोगों को भी आज या कल में पेंशन मिल जाएगी। मंत्री ने दावा किया कि योजना के तहत दिल्ली सरकार लाभार्थियों को प्रति माह 2,200 रुपये और केंद्र 300 रुपये का भुगतान करती है। पेंशन पिछले पांच महीनों से लंबित थी क्योंकि भाजपा के नेतृत्व वाला केंद्र अपना योगदान नहीं दे रहा था। उन्होंने कहा कि योजना के नियम और शर्तें ऐसी हैं कि केंद्र द्वारा छोटे ही सही लंबित भुगतान के कारण दिल्ली सरकार पेंशन जारी नहीं कर सकती है। कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अपने हिस्से का फंड न देने की वजह से दिल्ली के एक लाख बुजुर्गों को पांच महीने तक पेंशन का इंतजार करना पड़ा है। आतिशी ने कहा कि चाहे अरविंद केजरीवाल जेल में हों लेकिन वो बुजुर्गों के हक में लड़ना बंद नहीं करेंगे। केजरीवाल सरकार दिल्लीवालों के काम नहीं रुकने देगी।

अस्पतालों में ड्यूटी पर लौटे रेजिडेंट डाक्टर

ओपीडी सेवा हुई सामान्य

राज्य ब्यूरो, जागरण • नई दिल्ली

- ओपीडी में बढ़े मरीज लेकिन सामान्य दिनों के मुकाबले कम पहुंचे मरीज
- एम्स के आइआरसीएच में 12 कैंसर मरीजों की हुई सर्जरी

आरएमएल अस्पताल में ओपीडी की पर्ची पंजीकरण के लिए लगी मरीजों की कतार। ध्रुव कुमार

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कालेज में जूनियर महिला रेजिडेंट डाक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना के विरोध में लगातार 11 दिन हड़ताल रखने के बाद शुक्रवार को एम्स, सफदरजंग, आरएमएल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज (एलएचएमसी), लोकनायक, जीबी पंत सहित अस्पतालों में रेजिडेंट डाक्टर ड्यूटी पर लौट आए। इससे अस्पतालों में ओपीडी सेवा सामान्य हो गई और नियमित सर्जरी भी शुरू हो गई।

हड़ताल के दौरान अस्पतालों की ओपीडी में 55 से 70 प्रतिशत मरीज कम हो गए थे। रेजिडेंट डाक्टरों की हड़ताल खत्म होने के कारण अस्पतालों की ओपीडी में मरीज भी बढ़े, अस्पतालों में मरीजों की लाइन भी दिखी लेकिन हड़ताल से पहले की तुलना में मरीजों भीड़ कम रही। एम्स की ओपीडी में प्रतिदिन 13,000-14,009 मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। हड़ताल के दौरान ओपीडी में पांच हजार से भी कम मरीज देखे जा रहे थे। क्योंकि सिर्फ आनलाइन अप्वाइंटमेंट वाले मरीज ही देखे जा रहे थे। बगैर अप्वाइंटमेंट के ओपीडी में पहुंचने वाले मरीज नहीं देखे जा रहे थे। एम्स की चिकित्सा अधीक्षक डा. निरुपम मदान ने बताया कि ओपीडी में मरीज बढ़े हैं लेकिन सामान्य दिनों की तुलना में मरीजों की कुल संख्या कम रही है।

जिनकी टली सर्जरी, उनकी सर्जरी का अभी तैयार नहीं एक्शन प्लान

ड़ताल के कारण दिल्ली के अस्पतालों में करीब 15 हजार मरीजों की सर्जरी टली है। अकेले एम्स में छह हजार से अधिक मरीजों की सर्जरी व प्रोसीजर टले हैं। इन मरीजों की सर्जरी के लिए अभी कोई एक्शन प्लान तैयार नहीं है। एम्स प्रशासन का कहना है कि सर्जरी से संबंधित सभी विभाग अपना-अपना एक्शन प्लान तैयार करेंगे। ताकि हड़ताल के कारण जिन मरीजों की सर्जरी नहीं हो पाई उनकी सर्जरी भी जल्दी हो सके।

घर में भरा पानी निकालने के दौरान मोटर से लगा करंट, मौत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: किराड़ी के अगर नगर में गुरुवार शाम मोटर से घर में भरा पानी निकालने के दौरान करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। अगर नगर में एक पखवाड़े के भीतर करंट लगने से यह दूसरी मौत है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि घर में घुसे वर्षा के पानी में सर्किट से करंट आ गया, जिसकी चपेट में आने से मौत हो गई। वहीं मृतक संजय के छोटे भाई सुनील का कहना है कि घर में वर्षा का पानी जमा हो गया था। मोटर लगाकर पानी निकालने के दौरान करंट लगने से मौत हुई है।

प्रेमनगर थाना पुलिस को एक व्यक्ति को करंट लगने के बारे में गुरुवार शाम सात बजे पीसीआर काल मिली। पुलिस मौके पर पहुंची तो एक व्यक्ति बेहोशी की हालत में मिला। व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसकी पहचान अगर नगर निवासी संजय के रूप में हुई। संजय जूते बनाने की फैक्ट्री में नौकरी करते थे। पत्नी के अलावा दो बच्चे हैं।

दिल्ली की राजनीतिक नब्ज टटोलेंगे दूसरे राज्यों के भाजपा नेता

संतोष कुमार सिंह • जागरण

नई दिल्ली: राजनीतिक पार्टियों ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा झुग्गी बस्तियों व अनुसूचित जाति से संबंधित क्षेत्रों में अभियान चला रही है और अब चुनावी तैयारी को धार देने के लिए दूसरे राज्यों के नेताओं को मैदान में उतारने का निर्णय लिया है।

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड के नेताओं को विस्तारक बनाकर दिल्ली के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में तैनात किया जाएगा। बाहर से आने वाले विस्तारकों के लिए अगले सप्ताह प्रशिक्षण शिविर आयोजित होगा। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें विधानसभा क्षेत्र आवंटित करने के साथ ही वहां के बारे में जरूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। उसके कुछ दिनों के बाद विधानसभा क्षेत्र में उनका प्रवास शुरू हो जाएगा। वह क्षेत्र में रहकर वहां के राजनीतिक वातावरण, संगठन की स्थिति, क्षेत्र में सक्रिय नेताओं को लेकर आम नागरिकों की राय, विरोधी पार्टियों की स्थिति व सक्रियता आदि के बारे में रिपोर्ट तैयार करेंगे। उनकी रिपोर्ट के आधार पर पार्टी नेतृत्व चुनाव की रणनीति बनाएगी। प्रत्याशियों के चयन में भी इसे आधार बनाया जाएगा। चुनाव प्रचार व बूथ प्रबंधन में भी विस्तारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

भाजपा नेताओं का कहना है कि दूसरे राज्य से विस्तारक आने से जमीनी सच्चाई प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इन चारों राज्यों में विधानसभा चुनाव में भाजपा को जीत मिली है। इससे उनके अनुभव का लाभ दिल्ली के नेताओं व कार्यकर्ताओं को मिलेगा।

झुग्गियों में चल रहा विस्तारक अभियान

भाजपा ने 19 जुलाई को झुग्गी बस्ती विस्तारक अभियान की शुरुआत की है। लगभग 1100 बूथों की पहचान कर वहां विस्तारक तैनात किए गए हैं। वह उस बूथ में संगठन को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं।

यलो अलर्ट के बीच कई इलाकों में तेज वर्षा

राज्य ब्यूरो, जागरण • नई दिल्ली

- पीतमपुरा में सबसे अधिक 70.5 मिलीमीटर वर्षा हुई दर्ज, कल से तीन दिन तक यलो अलर्ट
- पिछले दिन के मुकाबले तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस हुआ कम, उमस भरी गर्मी से राहत

वर्षा के कारण धौला कुआं में हुए जलभराव में से कुछ इस तरह से गुजरते वाहन चालक। जागरण

राजधानी में यलो अलर्ट के बीच शुक्रवार को कुछ इलाकों में तेज वर्षा हुई। पीतमपुरा में सबसे अधिक 70.5 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। इसके अलावा धौला कुआं के आसपास भी तेज वर्षा हुई। वर्षा होने के कारण पिछले दिन के मुकाबले तापमान में 5.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई। इससे उमस भरी गर्मी से राहत रही। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को बादल छाए रहेंगे। कई इलाकों में हल्की वर्षा हो सकती है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

मौसम विभाग ने रविवार से मंगलवार तक तीन दिन के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। इस वजह से रविवार से मंगलवार तक हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा हो सकती है। सोमवार व मंगलवार को गरज के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। गुरुवार की रात दिल्ली में 4.3 मिलीमीटर वर्षा हुई थी। इसके बाद सुबह साढ़े आठ बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक पीतमपुरा में 70.5 मिलीमीटर, रिज एरिया में 37.6 मिलीमीटर, दिल्ली विश्वविद्यालय में 37 मिलीमीटर, मयूर विहार में 3.5 मिलीमीटर व आया नगर में 0.4 मिलीमीटर वर्षा हुई। सुबह साढ़े आठ बजे से 11.30 बजे के बीच ज्यादा वर्षा हुई। इस दौरान ही पीतमपुरा में सबसे अधिक 70 मिलीमीटर वर्षा हुई।

राजधानी में 27वें दिन भी संतोषजनक श्रेणी में रही हवा की गुणवत्ता

दिल्ली में 27वें दिन भी हवा की गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार अगले तीन दिन भी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में बनी रहेगी। सीपीसीबी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली का एयर इंडेक्स 76, फरीदाबाद का 68, गाजियाबाद का 77, ग्रेटर नोएडा का 91, गुरुग्राम का 63 व नोएडा का 84 रहा। एनसीआर के सभी शहरों में हवा की गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में रही।

चाणक्यपुरी में जलभराव में खेलते किशोर की कार के नीचे मौत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- पुलिस ने लापरवाही का मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू की
- मां ने कहा, सिस्टम की लापरवाही से हुई उनके बेटे की मौत

चाणक्यपुरी में शुक्रवार सुबह से हो रही वर्षा से सड़क पर भरे पानी में नहा रहे 15 वर्षीय सौरभ की कार के नीचे फंसने से मौत हो गई। वह अपने सात से आठ दोस्तों के साथ बापूधाम रोड पर ब्रिटिश स्कूल के पास भरे पानी में खेल रहा था। इस दौरान जलभराव में सड़क किनारे खड़ी आधी डूबी एक कार के नीचे फंस गया। वह खुद को छुड़ा नहीं सका और शरीर में पानी जाने से दम तोड़ दिया। सौरभ को कार से नीचे से निकालकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

चाणक्यपुरी थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ लापरवाही से मौत का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एनडीएमसी के जनसंपर्क विभाग ने घटनास्थल पर जलभराव की स्थिति को खारिज किया। हालांकि, मौत के कारणों पर विभाग ने कोई जवाब नहीं दिया। सौरभ की मां कौशल्या ने कहा कि बेटे की मौत सिस्टम की लापरवाही से हुई है।

मूलरूप से मध्य प्रदेश के छतरपुर के रहने वाले राज मिस्त्री कल्लू परिवार के साथ चाणक्यपुरी के विवेकानंद कैंप में रहते हैं। उनका बेटा सौरभ अकसर वर्षा से सड़क पर भरने वाले पानी में दोस्तों के साथ खेलने जाता था। शुक्रवार सुबह भी वर्षा की वजह से सड़क भी जलभराव हो गया था। जिसके बाद सौरभ कालोनी के पंकज, अमूल्य सहित पांच अन्य दोस्तों के साथ पानी में खेलने के लिए निकल गया। ब्रिटिश स्कूल के बाहर सड़क पर करीब ढाई से तीन फीट पानी भरा था। पानी में खेलते समय सौरभ बहाव से आगे बढ़ता हुआ सड़क किनारे खड़ी कार के नीचे फंस गया। जलभराव में कार आधी डूबी हुई थी। ऐसे में खुद को छुड़ाने की कोशिश में सौरभ के मुंह और नाक के जरिये पानी शरीर में चला गया।

संक्रामक बीमारियों से लड़ने की तैयारी अधूरी

सवाल

एम्स में 150 बेड के क्रिटिकल केयर व संक्रामक रोग केंद्र के निर्माण के लिए टेंडर आवंटित होने के 10 माह बाद भी शुरू नहीं हुआ काम, निर्माणाधीन स्थल से पेड़ हटाने की वन विभाग से नहीं मिली है स्वीकृति, परियोजना का बजट 180 करोड़ से बढ़कर हुआ 215 करोड़ रुपये

रणविजय सिंह • जागरण

नई दिल्ली: कोरोना महामारी खत्म होने के करीब ढाई वर्ष बाद भी संक्रामक बीमारियों के लड़ने की तैयारी अधूरी है। यही वजह है कि अब जब कई देशों में मंकीपाक्स का संक्रमण बढ़ने के कारण यहां भी अलर्ट है, तो अस्पतालों में कोरोना काल की तरह आइसोलेशन वार्ड व बेड आरक्षित करने की पहल शुरू कर दी गई है। इसका कारण यह है कि कोरोना से सबक लेकर संक्रामक बीमारियों के इलाज के लिए जो परियोजनाएं शुरू हुईं, उसका अमल ठीक से नहीं हुआ। एम्स में 150 बेड के क्रिटिकल केयर व संक्रामक रोग केंद्र बनाने की परियोजना भी उसमें से एक है।

स्थिति यह है कि इस क्रिटिकल केयर व संक्रामक रोग केंद्र के निर्माण के लिए करीब 10 माह पहले टेंडर आवंटित होने के बावजूद अब तक इसका निर्माण शुरू नहीं हो पाया। एम्स ट्रामा सेंटर के परिसर में हर्बल गार्डन के नजदीक खाली जमीन में इस क्रिटिकल केयर व संक्रामक रोग केंद्र का निर्माण होना है। निर्माणाधीन स्थल से 75 पेड़ हटाकर दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाना है। दिल्ली सरकार के वन विभाग से इसकी अब तक स्वीकृति नहीं मिल पाने के कारण निर्माण शुरू नहीं हो पा रहा है, जबकि परियोजना की लागत भी 180 करोड़ रुपये से बढ़कर 215 करोड़ हो चुकी है।

संक्रामक बीमारियों से पीड़ित मरीजों को अस्पताल के अन्य मरीजों से अलग रखना पड़ता है। कोरोना के मद्देनजर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआइएम) के तहत एम्स के ट्रामा सेंटर में 150 बेड के क्रिटिकल केयर व संक्रामक रोग केंद्र का निर्माण होना है। एम्स ने इसके निर्माण की जिम्मेदारी केंद्रीय लोग निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) को दी है। सीपीडब्ल्यूडी ने करीब 180 करोड़ की लागत से इसके निर्माण के लिए पिछले वर्ष अगस्त में टेंडर प्रक्रिया शुरू की। एम्स के अनुसार, पिछले वर्ष 16 अक्टूबर को इसका टेंडर हुआ था।

एम्स प्रशासन का कहना है कि अब परियोजना का खर्च 215 करोड़ है, जिसमें 120 करोड़ बजट पीएम-एबीएचआइएम से मिलना है। इसके अलावा 95 करोड़ रुपये का बजट एम्स देगा। पीएम-एबीएचआइएम के तहत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एम्स को अब तक 36 करोड़ रुपये की राशि भुगतान कर चुका है, जिसे एम्स ने सीपीडब्ल्यूडी को भुगतान कर दिया है।

एम्स प्रशासन का कहना है कि 75 पेड़ को दूसरी जगह प्रत्यारोपित करने का आवेदन वन विभाग के पास लंबित है। पर्यावरण से संबंधित स्वीकृति के लिए भी राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआइएए) के पास आवेदन किया गया है। स्वीकृति मिलने पर निर्माण जल्दी शुरू हो जाएगा। निर्माण शुरू होने के बाद 20 माह (एक वर्ष आठ माह) में यह बनकर तैयार होगा।

अब रविवार सुबह से फेज तीन के कारिडोर पर भी चलेगी मेट्रो

राज्य ब्यूरो, जागरण • नई दिल्ली

फेज तीन में बने दिल्ली मेट्रो के कारिडोर पर भी रविवार सुबह से मेट्रो चलने लगेगी। चार पुरानी मेट्रो लाइन के विस्तार कारिडोर पर सुबह छह बजे से मेट्रो का परिचालन शुरू हो जाएगा। वहीं फेज तीन में बने पिंक, मजेंटा व ग्रे लाइन पर सुबह सात बजे से रविवार को मेट्रो सेवा उपलब्ध होगी। इससे यात्रियों को आवागमन में सुविधा होगी।

असल में मेट्रो के पुराने कारिडोर पर सुबह करीब छह बजे से मेट्रो का परिचालन होता है। वहीं, फेज तीन में बने कारिडोर पर रविवार को सुबह आठ बजे से मेट्रो का परिचालन होता था। इसमें पिंक लाइन (शिव विहार-मजलिस पार्क), मजेंटा लाइन (जनकपुरी पश्चिम-बोटेनिकल गार्डन) व ग्रे लाइन (द्वारका-ढांसा बस स्टैंड) के अलावा चार पुरानी मेट्रो लाइन के विस्तार कारिडोर भी शामिल हैं। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) का कहना है कि फेज तीन के कारिडोर पर रविवार को सुबह आठ बजे से परिचालन शुरू होने से यात्रियों को परेशानी हो रही थी।

फेज तीन के मेट्रो कारिडोर और परिचालन का समय

- रेड लाइन का दिलशाद गार्डन-शहीद स्थल कारिडोर-सुबह छह बजे
- ब्लू लाइन का नोएडा सिटी सेंटर-इलेक्ट्रानिक सिटी कारिडोर-सुबह छह बजे
- ग्रीन लाइन का मुंडका-बहादुरगढ़ कारिडोर- सुबह छह बजे
- वायलेट लाइन का बदरपुर-बल्लभगढ़ कारिडोर-सुबह छह बजे
- पिंक लाइन-सुबह आठ बजे
- मजेंटा लाइन-सुबह आठ बजे
- ग्रे लाइन-सुबह आठ बजे

युवती के शरीर को कुत्तों की तरह युवक ने दांतों से काटकर कर दिया नीला

जासं, गाजियाबाद : कोलकाता में प्रशिक्षु महिला चिकित्सक से दरिंदगी और हत्या की घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल और मेडिकल कालेजों में बेशक महिला सुरक्षा के लिए टास्क फोर्स गठित के आदेश जारी कर दिए हैं लेकिन महिलाएं घर में भी सुरक्षित नहीं है। गाजियाबाद में एक ऐसा मामला प्रकाश में आया है कि जिसमें एक युवक ने अपनी 22 वर्षीय दोस्त युवती को दांतों से काट काटकर बुरी तरह से जख्मी कर दिया है। युवती के शरीर के विभिन्न हिस्सों में 50 से अधिक घाव पड़ गए हैं। सूत्रों से पता चला है कि युवती के पैर, दोनों हाथ, चेस्ट, गर्दन, दोनों गाल, होठ, हिप, माथे और आंख पर दांत से काटने के गंभीर घाव हैं। मामला कविनगर क्षेत्र की चिरंजीव विहार कालोनी का है। इस संबंध में शुक्रवार को युवती का पुलिस द्वारा संजयनगर स्थित संयुक्त अस्पताल में मेडिकल कराया गया है। सबसे अधिक काटने के घाव गाल पर है।

****

बढ़ता अंतरिक्ष कचरा चिंता की बात, इसरो से सीखे दुनिया : मुर्मु

- पहले अंतरिक्ष दिवस पर राष्ट्रपति ने कहा, इसरो की उपलब्धियां असाधारण
- कहा, अंतरिक्ष को निजी क्षेत्र के लिए खोलने के फैसले से नई क्रांति आई

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को असाधारण बताते हुए कहा है कि इससे एक देश के रूप में हमारी क्षमताएं बढ़ी हैं। साथ ही मुर्मु ने अंतरिक्ष में बढ़ते कचरे पर चिंता जताई और कहा, इस मामले में दुनिया को इसरो से सीखने की जरूरत है, जिसने कचरा मुक्त अभियानों का संकल्प जताया है। ज्ञात हो, इसरो ने 2030 तक अपने सभी अंतरिक्ष अभियानों को कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

राष्ट्रपति चंद्रयान-3 की पिछले साल 23 अगस्त को चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की पहली वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। चंद्रयान-3 की अद्भुत उपलब्धि को सदैव याद रखने के लिए इस तिथि को अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने के सिलसिले की शुरुआत हुई है। भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, इसरो प्रमुख एस. सोमनाथ, अनेक इंजीनियर और इसरो विज्ञानी तथा अंतरिक्ष उद्योग के प्रतिनिधि शामिल हुए।

नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुक्रवार को प्रथम अंतरिक्ष दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में इसरो के राकेट का प्रारूप देखतीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, मंत्री जितेंद्र सिंह और इसरो प्रमुख एस सोमनाथ। प्रेट्र

पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर सभी को बधाई। अंतरिक्ष क्षेत्र में अपने देश की उपलब्धियों को हम बहुत गर्व के साथ याद करते हैं। यह हमारे अंतरिक्ष विज्ञानियों के योगदान की सराहना करने का भी दिन है। सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। हमारी सरकार ने इस क्षेत्र से संबंधित कई निर्णय लिए हैं और आने वाले समय में हम और भी अधिक कदम उठाएंगे। **-नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री**

राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर सभी नागरिकों को शुभकामना देता हूं। मैं उन प्रतिभाशाली लोगों को बधाई देता हूं, जिन्होंने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान की सफल लैंडिंग के माध्यम से अंतरिक्ष में भारत के प्रभुत्व को साबित किया। यह शानदार उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के युवाओं के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र में अनंत अवसर खोलने के दृष्टिकोण का प्रमाण है, जो असंभव प्रतीत होने वाली चीजों को वास्तविकता में बदलने का साहस रखते हैं। **-अमित शाह, गृह मंत्री**

मुर्मु ने कहा, अंतरिक्ष कचरा भविष्य के अभियानों के लिए समस्या पैदा कर सकता है। सभी देशों को इस पर सोचना चाहिए। उन्होंने इसरो की तारीफ करते हुए कहा, इस एजेंसी ने देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर रोबोटिक चैलेंज के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया। उन्होंने कहा कि आज अगर हमारा अंतरिक्ष अभियान दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अभियानों में शामिल है तो इसका श्रेय इन विज्ञानियों को ही जाता है।

चंद्रयान अभियान की सफलता का जिक्र करते हुए मुर्मु ने कहा कि यह दुनिया के लिए एक नजीर है। इसरो ने एक साथ सौ सेटेलाइट लांच कर इतिहास रचा है। इसरो के प्रयासों से स्वास्थ्य, परिवहन, सुरक्षा, ऊर्जा, पर्यावरण, सूचना तकनीक जैसे क्षेत्रों को असीमित लाभ हुआ है। निजी क्षेत्र के लिए अंतरिक्ष को खोलने के सरकार के फैसले से नई क्रांति आई है। अनगिनत स्टार्ट-अप उभरे हैं, जो बड़ी छलांग लगाने को तैयार हैं। इस अवसर पर केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री डा. जितेंद्र सिंह ने कहा, आज भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था आठ अरब डालर है, पर अगले 10 साल में यह 44-45 अरब डालर तक पहुंच सकती है।

दुनियाभर के शोधकर्ताओं के लिए चंद्रयान-3 का डाटा जारी किया

नई दिल्ली, प्रेट्र: इसरो ने चंद्रयान-3 मिशन से पांच पेलोड द्वारा जुटाए गए 55 गीगाबाइट से अधिक डाटा को दुनियाभर के शोधकर्ताओं के लिए जारी कर दिया है, ताकि वे इनका विश्लेषण कर सकें। यह डाटा भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान डाटा केंद्र के पोर्टल www.pradan.issdc.gov.in पर जारी किया गया है।

दीक्षा समारोहों के लिए भारतीय ड्रेस डिजाइन करें संस्थान : स्वास्थ्य मंत्रालय

- काला गाउन औपनिवेशिक विरासत की झलक दिखलाता है
- मंत्रालय ने इस बारे में सभी संस्थानों से प्रस्ताव देने को कहा

नई दिल्ली, प्रेट्र : दीक्षा समारोह के दौरान काला गाउन और टोपी पहनने की परंपरा रही है। यह औपनिवेशिक विरासत की झलक दिखलाती है। अब स्वास्थ्य मंत्रालय इसे अपने संस्थानों में बदलने की तैयारी कर रहा है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने सभी संस्थानों से दीक्षा समारोहों के लिए उस राज्य की परंपराओं के आधार पर भारतीय ड्रेस कोड डिजाइन करने कहा है, जहां वे स्थित हैं। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि वर्तमान ड्रेस एक औपनिवेशिक विरासत है, जिसमें बदलाव की जरूरत है। अभी मंत्रालय के विभिन्न संस्थानों द्वारा दीक्षा समारोह के दौरान काला गाउन और टोपी का उपयोग किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि इस पोशाक की शुरुआत यूरोप में मध्य युग में हुई थी और इसे अंग्रेजों ने अपने सभी उपनिवेशों में पेश किया था।

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्णय लिया गया है कि चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने में लगे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) सहित विभिन्न संस्थान जिस राज्य में स्थित हैं, वहां की स्थानीय परंपराओं के आधार पर दीक्षा समारोह के लिए भारतीय ड्रेस कोड डिजाइन करेंगे।

प्रतीकात्मक

मंत्रालय ने स्वास्थ्य शिक्षा के काम में लगे सभी संस्थानों से इस संबंध में प्रस्ताव सौंपने को कहा है, जिसे केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव मंजूरी देंगे।

रक्षा उद्योग को मजबूती देने को भारत और अमेरिका में अहम समझौता

दोनों देशों ने एसओएसए के साथ संपर्क अधिकारियों की तैनाती पर किए हस्ताक्षर

राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताएं पूरा करने को एक-दूसरे से औद्योगिक संसाधन लेंगे

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

भारत और अमेरिका ने रक्षा सहयोग को अधिक मजबूती देने के लिए अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें रणनीतिक साझेदारी के लिहाज से रक्षा जरूरतों की आपूर्ति व्यवस्था की सुरक्षा (एसओएसए) का समझौता बेहद अहम है। दोनों देशों के बीच संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति का समझौता वैश्विक रणनीतिक सहयोग के दायरे को विस्तार देगा। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अमेरिका यात्रा के पहले दिन गुरुवार को इन समझौतों को मूर्त रूप दिया गया।

भारत-अमेरिका के रक्षा मंत्रालयों की ओर से जारी बयान में कहा गया कि एसओएसए बाध्यकारी नहीं, मगर आपसी सहयोग को इससे मजबूती मिलेगी। इसके जरिये दोनों देश अपने राष्ट्रीय रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने वाली वस्तुओं व सेवाओं के लिए पारस्परिक प्राथमिकता समर्थन प्रदान करने पर सहमत हैं। इस व्यवस्था में दोनों देश अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधनों की अप्रत्याशित आपूर्ति श्रृंखला में आने वाली रुकावटों को हल कर आवश्यक औद्योगिक संसाधन प्राप्त करने में सक्षम होंगे। एसओएसए पर भारत की ओर से रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक अधिग्रहण समीर कुमार सिन्हा व अमेरिका की ओर से उसके रक्षा मंत्रालय में औद्योगिक आधार नीति के प्रधान उप सहायक सचिव डा.विक रामदास ने हस्ताक्षर किए।

दौरे की खास बातें

- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका में भारतीय समुदाय को संबोधित किया
- 'वसुधैव कुटुंबकम' की दिशा में काम करें अमेरिका में भारतीय समुदाय के लोग
- भारत का वैश्विक परिदृश्य पूरा बदला, पहले गरीब देश के आलसी लोग कहते थे
- कहा-भारत और अमेरिका एकजुट वैश्विक शांति, समृद्धि, स्थिरता सुनिश्चित करेंगे
- हमारी सरकार आई तो रक्षा निर्यात 600 करोड़ था, अब 23,000 करोड़ रुपये है

वाशिंगटन में शुक्रवार को आयोजित बैठक के दौरान भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा मंत्री लायड आस्टिन। प्रेट्र

एसओएसए के जरिये अमेरिका और भारत के बीच रक्षा उद्योग सहयोग को और अधिक मजबूत किया जा सकेगा। जबकि संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति समझौते के तहत भारत इंडो-पैसिफिक कमांड (इंडोपैकोम) फ्लोरिडा में विशेष आपरेशन कमांड व बहरीन में अमेरिकी नेतृत्व वाली बहुराष्ट्रीय संयुक्त समुद्री सेना (सीएमएफ) में तीन कर्नल स्तर के अधिकारियों को तैनात करेगा। वैसे समझौते की औपचारिकता से पहले ही इन अधिकारियों की तैनाती हो गई है। अमेरिकी अधिकारी रामदास ने कहा, आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था अमेरिका-भारत प्रमुख रक्षा साझेदार संबंधों में महत्वपूर्ण पल का प्रतिनिधित्व करती है। यह रक्षा प्रौद्योगिकी तथा व्यापार पहल को मजबूत करने में अहम कदम है। इससे दोनों देश अहम राष्ट्रीय रक्षा संसाधनों की खरीद के लिए एक-दूसरे के प्राथमिकता वितरण अनुरोधों का समर्थन करने को प्रतिबद्ध हैं।

भारत बदले में अपने औद्योगिक आधार के साथ एक सरकारी-उद्योग आचार संहिता स्थापित करेगा जहां भारतीय फर्म स्वेच्छा से अमेरिका को प्राथमिकता सहयोग देने के लिए हर उचित प्रयास पर सहमत होंगे। अमेरिका ने अपने नाटो सहयोगियों समेत 17 देशों से एसओएसए समझौते किए हैं और भारत उसका 18वां साझीदार है। अमेरिका ने जिन अन्य देशों से यह समझौता किया उसमें आस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, इजरायल, इटली, जापान, लातविया, लिथुआनिया, नीदरलैंड, नार्वे, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, स्पेन, स्वीडन व ब्रिटेन आदि शामिल हैं।

दसवीं और बारहवीं के लिए राज्य बनाएं एक ही शिक्षा बोर्ड : केंद्र

- अभी आठ राज्यों में 10वीं-12वीं के हैं अलग-अलग बोर्ड
- कर्नाटक ने मानी सलाह, दोनों बोर्डों का एक में किया विलय

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

राज्यों के साथ मिलकर स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को मजूबती देने में जुटे केंद्र ने अब सभी राज्यों को 10वीं और 12वीं के लिए एक ही स्कूली शिक्षा बोर्ड बनाने की सलाह दी है। केंद्र ने राज्यों को यह सलाह तब दी है, जब अभी भी बंगाल, ओडिशा, असम सहित आठ राज्यों में 10वीं व 12 वीं के लिए अलग-अलग शिक्षा बोर्ड है।, इनके परीक्षा व मूल्यांकन का तरीका भी भिन्न है। कर्नाटक ने केंद्र की सलाह को मानते हुए पिछले वर्ष ही अपने 10वीं और 12वीं के बोर्डों का विलय कर एक बोर्ड बना दिया है।

शिक्षा मंत्रालय का मानना है कि राज्यों में एक शिक्षा बोर्ड होने से वह नौवीं से 12वीं कक्षा तक पढ़ाई करने वाले छात्रों के विकास के लिए साझा रणनीति तैयार कर सकेंगे। अभी इन सभी राज्यों में 10वीं और 2वीं के शिक्षा बोर्डों के काम-काज का तरीका अलग है। इसके चलते इन राज्यों में छात्रों के प्रदर्शन में भारी अंतर भी देखने को मिलता है।

देश के जिन आठ राज्यों में 10वीं और 12वीं के लिए अलग-अलग शिक्षा बोर्ड है, उनमें बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, असम, केरल, मणिपुर, तेलंगाना और बिहार शामिल है। बिहार में दसवीं के लिए अलग से संस्कृत बोर्ड है। केरल में 12वीं के लिए दो बोर्ड है। ऐसे में कुल 18 बोर्ड ऐसे है, जो 10वीं और 12वीं के लिए अलग-अलग संचालित होते है।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शिक्षा मंत्रालय भले ही स्कूलों के लिए नई पाठ्यपुस्तकें तैयार करने में जुटा है, पर देश के छह शिक्षा बोर्ड ऐसे भी हैं, जो अपने यहां एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाते हैं। वह अपना खुद का पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं। इन बोर्डों में आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, बिहार, तमिलनाडु व बंगाल के बोर्ड शामिल हैं।

जयंत बोले, आइटीआइ और एनएसटीआइ को उन्नत करने की तैयारी

मुंबई, प्रेट्र: केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने शुक्रवार को कहा कि सरकार 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और पांच राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआइ) के आधुनिकीकरण के बारे में राज्य सरकारों और उद्योग संगठनों के साथ बातचीत कर रही है। एक कार्यक्रम के उन्होंने कहा कि हम इस सिलसिले में राज्य सरकारों और विभिन्न उद्योग संघों के सुझावों को लेकर आइटीआइ और एनएसटीआइ को उन्नत करेंगे। देश में अभी लगभग 15,000 आइटीआइ हैं, जिनमें से 12,000 निजी क्षेत्र के हैं।

भारत ने कतर के समक्ष गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियों की जब्ती का मुद्दा उठाया

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत ने शुक्रवार को कहा कि उसने गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियों की जब्ती के मामले को कतर के समक्ष उठाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हमने कतर के अफसरों द्वारा जब्त की गई गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियों व सिख समुदाय द्वारा उन्हें वापस करने की मांग के संबंध में रिपोर्ट देखी है।'' सरकार पहले ही इस मामले को कतर पक्ष के साथ उठा चुकी है और दोहा में भारतीय दूतावास ने कतर की राजधानी में सिख समुदाय को घटनाक्रम से अवगत कराया है।

जायसवाल ने कहा, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि गुरु ग्रंथ साहिब के दो स्वरूपों को कतर के अधिकारियों ने दो व्यक्तियों/समूहों से ले लिया गया था, जिन पर कतर सरकार की मंजूरी के बिना धार्मिक प्रतिष्ठान चलाने का आरोप लगाया गया था। उन्होंने कहा कि दूतावास ने स्थानीय कानूनों और नियमों के दायरे में हर संभव सहायता प्रदान की है।

जयसवाल ने कहा, पवित्र पुस्तक का एक स्वरूप कतर के अधिकारियों द्वारा लौटा दिया गया है और यह आश्वासन दिया गया कि दूसरे स्वरूप को भी सम्मान के साथ रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि हम उच्च प्राथमिकता के साथ कतर अधिकारियों के साथ मामले पर बातचीत जारी रखेंगे और शीघ्र समाधान की उम्मीद करते हैं।

गोविंद मोहन ने गृह सचिव का पदभार संभाला

नई दिल्ली, प्रेट्र: सिक्किम कैडर के 1989 बैच के आइएएस अधिकारी गोविंद मोहन ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह सचिव का पदभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने अजय कुमार भल्ला की जगह ली है, जिनका पांच वर्ष का कार्यकाल बीते दिन ही समाप्त हुआ है।

14 अगस्त को केंद्र सरकार ने संस्कृति मंत्रालय के सचिव गोविंद मोहन को नया गृह सचिव नियुक्त किया था। संस्कृति सचिव के रूप में मोहन ने मोदी सरकार के दो प्रमुख कार्यक्रमों आजादी का अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा आंदोलन को सफलतापूर्वक लांच किया है।

गोविंद मोहन मूलतः उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और 2017 से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। बताया जाता है कि गोविंद मई से सितंबर 2018 तक गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव और सितंबर 2018 से सितंबर 2021 तक अतिरिक्त सचिव रहे हैं। आइआइटी बीएचयू से इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग कर चुके मोहन अक्टूबर 2021 से संस्कृति मंत्रालय में सचिव के तौर पर तैनात थे।

कर्नाटक के राज्यपाल से सीएम सिद्दरमैया की एक और शिकायत

बेंगलुरु, आइएएनएस: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मैसुरु शहरी विकास प्राधिकरण भूखंड घोटाले में जांच का सामना कर रहे सिद्दरमैया के विरुद्ध शुक्रवार को राज्यपाल थावरचंद गहलोत से एक और शिकायत की गई है। भाजपा एमएलसी डीएस अरुण ने सीएम पर राज्य के समेकित कोष के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। ज्ञात हो, सिद्दरमैया के पास वित्त विभाग भी है।

एमएलसी ने वित्तीय अनियमितता, कोष के दुरुपयोग और संवैधानिक दायित्व के उल्लंघन की जांच की मांग की है। उन्हें पद से हटाने की भी मांग की है। डीएस अरुण ने कहा, मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने झूठ और मनगढ़ंत दस्तावेज तैयार किए और विधानसभा में प्रस्तुत किया। इससे पता चलता है कि उन्हें हमारे संविधान के लिए कोई सम्मान और विश्वास नहीं है। मुख्यमंत्री ने कई हजार करोड़ रुपये का दुरुपयोग किया है। वित्त मंत्री संवैधानिक प्रविधानों का उल्लंघन कर रहे हैं।

कर्नाटक के सीएम पर राज्य के समेकित कोष के दुरुपयोग का आरोप

ज्ञात हो, मैसुरु शहरी विकास प्राधिकरण भूखंड घोटाले में सिद्दरमैया पहले से ही घिरे हैं। राज्यपाल इस मामले में सीएम के विरुद्ध मुकदमा चलाने को मंजूरी भी दे चुके हैं। मुख्यमंत्री पर अपनी पत्नी पार्वती को नियमों का उल्लंघन कर भूखंड आवंटित करने का आरोप है।

दिल्ली में सिद्दरमैया, शिवकुमार : कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे। उनकी कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक होने वाली है। सूत्रों के अनुसार, मैसुरु शहरी विकास प्राधिकरण भूखंड घोटाले को लेकर चर्चा हो सकती है। इस मामले की अगले सप्ताह हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है।

कमजोर जनजातीय समूहों तक पहुंचने का सरकार ने शुरू किया अभियान

नई दिल्ली, प्रेट्र: सरकार ने पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) के तहत 194 जिलों में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) को लाभ पहुंचाने के लिए शुक्रवार को राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया। अभियान 10 सितंबर तक चलेगा। भारत में 10.45 करोड़ अनुसूचित जनजाति (एसटी) आबादी है, जिसमें 18 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 75 समुदायों को पीवीटीजी के रूप में पहचाना गया है। पीवीटीजी को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

पिछले साल इसी तरह का अभियान 100 जिलों तक पहुंचा था, जिसमें 500 ब्लाक और 15,000 पीवीटीजी बस्तियां शामिल थीं। इस वर्ष का अभियान अधिक व्यापक होगा और इसका लक्ष्य 17 राज्यों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 194 जिलों की 28,700 बस्तियों में 44.6 लाख पीवीटीजी व्यक्तियों तक पहुंचना है।

अयोग्य पायलटों से विमान उड़वाने पर एअर इंडिया पर 90 लाख रुपये जुर्माना

- डीजीसीए की कार्रवाई, संचालन निदेशक पर छह व प्रशिक्षण निदेशक पर तीन लाख जुर्माना
- संबंधित पायलट को भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए सावधानी बरतने की चेतावनी

नई दिल्ली, प्रेट्र : विमानन नियामक एजेंसी डीजीसीए ने टाटा समूह के स्वामित्व वाली एअर इंडिया पर अयोग्य पायलटों के साथ उड़ान संचालित करने के लिए 90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। एअर इंडिया के संचालन निदेशक पंकुल माथुर और प्रशिक्षण निदेशक मनीष वासवदा पर छह लाख रुपये और तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कहा कि संबंधित पायलट को भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सावधानी बरतने की चेतावनी दी गई है। डीजीसीए की ओर से शुक्रवार को जारी विज्ञप्ति में कहा गया, ''एअर इंडिया लिमिटेड ने एक गैर-प्रशिक्षित लाइन कैप्टन द्वारा संचालित एक उड़ान का संचालन किया। उसके साथ एक गैर प्रशिक्षित प्रथम अधिकारी भी भेजा गया। नियामक ने इसे सुरक्षा की दृष्टि से एक गंभीर चूक के रूप में देखा है।'' उल्लंघन के लिए, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने एअर इंडिया पर 90 लाख रुपये, संचालन निदेशक पर छह लाख रुपये और प्रशिक्षण निदेशक पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

प्रतीकात्मक

10 जुलाई को एयरलाइन की ओर से प्रस्तुत स्वैच्छिक रिपोर्ट के जरिये घटना के संज्ञान में आने के बाद नियामक ने दस्तावेजों की जांच व शेड्यूलिंग सुविधा की मौके पर जांच के साथ एयरलाइन के संचालन की भी जांच की।

डीजीसीए के अनुसार जांच में प्रथम दृष्टया पता चला है कि कई पदधारकों और कर्मचारियों द्वारा विनियामक प्रविधानों का उल्लंघन किया गया, जो सुरक्षा को काफी हद तक प्रभावित कर सकते हैं।'' डीजीसीए ने यह भी कहा कि फ्लाइट के कमांडर और एयरलाइन के पदधारकों को 22 जुलाई को जारी कारण बताओ नोटिस के जरिये अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया गया था। डीजीसीए ने एक नोट में बताया संबंधित व्यक्तियों की ओर से दिए गए उत्तर संतोषजनक नहीं थे। डीजीसीए ने मौजूदा नियमों के प्रविधानों के संदर्भ में प्रवर्तन कार्रवाई शुरू की और यह जुर्माना लगाया।

जेलों में भीड़ का मामला

केंद्र ने स्पष्ट की स्थिति, सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के जेल अधीक्षकों को दिए अमल के आदेश, धारा-479 में है पहली बार के आरोपित को एक तिहाई सजा भुगतने पर जमानत का प्रविधान

सभी विचाराधीन कैदियों को मिलेगा नए कानून का लाभ

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में साफ किया कि नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा-479 का लाभ सभी विचाराधीन कैदियों को मिलेगा चाहे उनके मामले एक जुलाई से पहले ही क्यों न दर्ज हुए हों। यानी एक तिहाई सजा भुगतने पर जमानत पाने का लाभ नए व पुराने सभी विचाराधीन कैदियों को मिलेगा।

सीआरपीसी की जगह एक जुलाई से लागू हुई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा-479 विचाराधीन कैदियों को जेल में रखने की अधिकतम अवधि के बारे में प्रविधान करती है। इसने सीआरपीसी की धारा-436ए की जगह ली है। धारा-479 कहती है कि पहली बार के अपराधी विचाराधीन कैदी अगर संबंधित कानून में आरोपित अपराध में दी गई अधिकतम सजा की एक तिहाई जेल काट लेता है तो कोर्ट उसे जमानत पर रिहा कर देगा। इसके अलावा उम्रकैद और मृत्युदंड की सजा के अलावा किसी अन्य अपराध में आरोपित विचाराधीन कैदी अगर कुल सजा की आधी सजा काट लेता है तो कोर्ट उसे जमानत पर रिहा कर देगा। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने केंद्र से एक तिहाई सजा काटने पर जमानत के प्रविधान को पूर्व प्रभाव से लागू करने पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा था।

एक जुलाई से पहले दर्ज मामलों में भी मिलेगा बीएनएसएस की धारा-479 का लाभ

शुक्रवार को जस्टिस हिमा कोहली और संदीप मेहता की पीठ ने सुनवाई की। केंद्र की ओर से पेश एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा, बीएनएसएस की धारा-479(1) के प्रविधान देशभर में सभी विचाराधीन कैदियों पर समान रूप से लागू होंगे चाहे उनका अपराध एक जुलाई, 2024 के पहले ही क्यों न दर्ज हुआ हो। इसके बाद कोर्ट ने देशभर के जेल अधीक्षकों को इसे लागू करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि इस प्रविधान के मुताबिक विचाराधीन कैदियों की अर्जियों को जल्द से जल्द निपटाया जाए और दो महीने में प्रक्रिया पूरी करके कोर्ट में रिपोर्ट दी जाए। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे भी हलफनामा दाखिल कर बताएं कि कितने विचाराधीन कैदी ऐसे हैं जिन पर यह प्रविधान लागू होते हैं और कितनी अर्जियां इस संबंध में आई हैं तथा कितनों की रिहाई हुई है।

सुप्रीम कोर्ट जेलों में अत्यधिक भीड़ के मामले में सुनवाई कर रहा है। पिछली सुनवाई पर न्यायमित्र वरिष्ठ वकील गौरव अग्रवाल ने बीएनएसएस की धारा-479 का हवाला देते हुए कहा था कि पहली बार के अपराधी विचाराधीन कैदियों के लिए इसमें एक छूट है कि अगर उन्होंने आरोपित अपराध में निर्धारित अधिकतम सजा की एक तिहाई जेल काट ली है तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन तभी सवाल उठा था कि क्या यह कानून पूर्व प्रभाव से लागू होगा। इस पर पीठ ने केंद्र को स्थिति स्पष्ट करने को कहा था।

****

खरगे ने मनरेगा को लेकर मोदी सरकार को घेरा

नई दिल्ली, प्रेट्र: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शुक्रवार को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को लेकर मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने सरकार पर मनरेगा के प्रति उदासीन रवैया अपनाने का आरोप लगाया और कहा, मनरेगा की मौजूदा स्थिति ग्रामीण भारत के प्रति पीएम मोदी के विश्वासघात का जीता जागता स्मारक है।

खरगे ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 2005 में इसी दिन कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार ने ग्रामीण भारत के करोड़ों लोगों के लिए काम का अधिकार देने के लिए मनरेगा लागू किया था। वर्तमान में 13.3 करोड़ सक्रिय श्रमिक हैं, जो कम मजदूरी, बेहद कम कार्य दिवस और जाब कार्ड से हटाए जाने की समस्या के बावजूद मनरेगा पर निर्भर हैं। आरोप लगाया कि सरकार ने सात करोड़ से ज्यादा श्रमिकों को जाब कार्ड से हटा दिया। मनरेगा के लिए इस वर्ष का बजट कुल बजटीय आवटन का 1.78 प्रतिशत है, जो दस वर्ष में सबसे निचला स्तर है।

कह कर रहेंगे — माधव जोशी

बं. कानून व्यवस्था

अतीत से वर्तमान तक

47 साल में पहली बार जम्मू-कश्मीर में पांच साल की विस

देशभर में जम्मू-कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य था जहां छह वर्ष का था विधानसभा का कार्यकाल था। वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के साथ ही समाप्त हो गई यह व्यवस्था। देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू करने के साथ ही लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल छह वर्ष कर दिया था। उस समय नेशनल कान्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार थी। मुख्यमंत्री शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे।

47 वर्ष बाद पहली बार पांच वर्ष के लिए होगा जम्मू-कश्मीर विधानसभा का गठन

6 नहीं, पांच पांच वर्ष के लिए चुने जाएंगे विधायक, विधानपरिषद भी नहीं होगी

1972 में अंतिम बार पांच वर्ष के लिए अपने विधायकों को चुना था जम्मू-कश्मीर की जनता ने

1977 में विस चुनाव के बाद छह वर्ष के कार्यकाल वाली विधानसभा की परंपरा शुरू हो गई थी

36 सदस्य होते थे जम्मू-कश्मीर में विधानपरिषद में

1977, 1983, 1987, 1996, 2002, 2008 व 2014 में छह वर्ष के लिए ही विधायक चुने गए। पूर्व विधायक हर्ष देव सिंह ने निजि विधेयक लाकर इसे पांच वर्ष कराने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे

सरकारी खजाने पर बोझ था छह वर्ष का कार्यकाल

जम्मू-कश्मीर मामलों के जानकार प्रो. हरि ओम ने कहा कि छह वर्ष की विधानसभा कांग्रेस की देन थी। कांग्रेस और नेशनल कान्फ्रेंस ने सिर्फ यहां सत्ता को देखा है। यहां विधानपरिषद की भी जरूरत नहीं थी। उसे सिर्फ सत्ताधारी दल ने अपने चहेतों को सरकारी खर्च पर पुनर्वासित करने के लिए बनाए रखा था। यह खजाने पर बोझ है।

प्रस्तुति : नवीन नवाज

कांग्रेस-नेकां गठबंधन पर शाह के दस सवाल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- पृथक झंडे के एनसी के वादे पर रुख साफ करें राहुल गांधी
- अनुच्छेद-370 की बहाली की बात करती है नेशनल कान्फ्रेंस

जम्मू-कश्मीर के विधानसभा चुनाव के लिए नेशनल कान्फ्रेंस (एनसी) के साथ गठबंधन करने वाली कांग्रेस से गृह मंत्री अमित शाह ने तीखे सवाल पूछे हैं। साथ ही शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सत्ता के लोभ में बार-बार देश की एकता और सुरक्षा को खतरे में डालने का काम कर रही है। गृह मंत्री ने एक्स पर अपनी पोस्ट के जरिये कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी से दस सवाल किए हैं।

शाह ने पूछा, क्या कांग्रेस जम्मू-कश्मीर के लिए पृथक झंडे के नेशनल कान्फ्रेंस के वादे का समर्थन करती है, क्या राहुल गांधी व उनकी कांग्रेस अनुच्छेद-370 और 35ए बहाल करने के नेशनल कान्फ्रेंस के वादे का समर्थन करते हैं और ऐसा करते हुए क्या वे जम्मू-कश्मीर को फिर से अशांति एवं आतंकवाद के दौर में धकेलना चाहते हैं। गौरतलब है कि दो दिन पहले ही कांग्रेस और नेशनल कान्फ्रेंस ने जम्मू-कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए सभी 90 सीटों पर गठबंधन करने का एलान किया है और ये दोनों वादे नेशनल कान्फ्रेंस के चुनावी घोषणापत्र का हिस्सा हैं। शाह ने कहा कि कांग्रेस ने अब्दुल्ला परिवार की पार्टी के साथ गठजोड़ कर एक बार फिर अपना असली चेहरा उजागर कर दिया है। गृह मंत्री ने कांग्रेस से सवाल किया कि क्या वह कश्मीर के युवाओं के बजाय पाकिस्तान के साथ बातचीत में शामिल होकर फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देना चाहती है। नेशनल कान्फ्रेंस बार-बार पाकिस्तान के साथ सीमा पार व्यापार को फिर से स्थापित करने की वकालत कर रही है।

शाह के कांग्रेस से सवालों में यह भी शामिल है कि क्या वह आतंकवाद और पत्थरबाजी में शामिल लोगों के स्वजन को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करके आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को फिर लाने का समर्थन करती है। क्या कांग्रेस दलितों, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त कर फिर से उनके साथ अन्याय करने के नेशनल कान्फ्रेंस के वादे के साथ है। दरअसल दलितों, पिछड़ों को आरक्षण समेत कई योजनाएं जम्मू-कश्मीर में सिर्फ इसलिए बहाल हो पाई हैं क्योंकि वहां से विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो गया और अब पूरी तरह भारतीय संविधान लागू है। शाह ने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत तख्त-ए-सुलेमान और हरि पर्वत कोह-ए-मारन के नाम से जाने जाएं। अमित शाह ने कांग्रेस से यह भी पूछा कि क्या वह जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर भ्रष्टाचार की आग में झोंककर पाकिस्तान समर्थित गिने-चुने परिवारों के हाथों में सौंपने का समर्थन करती है। साथ ही गृह मंत्री ने कांग्रेस और राहुल गांधी से यह भी जानना चाहा कि क्या वे नेशनल कान्फ्रेंस की विभाजनकारी सोच व नीतियों का समर्थन करते हैं?

गठबंधन के बावजूद कुछ सीटों पर फंसा है पेच

राज्य ब्यूरो, जागरण • श्रीनगर

- उमर बोले, जिन सीटों पर गतिरोध बना है उसे जल्द दूर कर लिया जाएगा, 27 तक जारी कर देंगे सभी प्रत्याशियों की सूची

नामांकन दाखिल करने के लिए प्रत्याशी सकीना इट्टू के साथ उमर अब्दुल्ला। फाइल

नेशनल कान्फ्रेंस (नेकां) और कांग्रेस के बीच चुनाव पूर्व गठबंधन के बावजूद कुछ सीटों को लेकर गतिरोध बना हुआ है। इसकी पुष्टि शुक्रवार को खुद नेशनल कान्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने की। उन्होंने कहा कि कुछ सीटों पर हम अपना दावा जता रहे हैं और कुछ पर कांग्रेस। यह विवाद कुछ एक सीटों तक ही सीमित है।

नेशनल कान्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच गुरुवार को ही गठबंधन हुआ है। नेशनल कान्फ्रेंस के अध्यक्ष डा. फारूक अब्दुल्ला व उमर अब्दुल्ला की श्रीनगर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मलिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी के साथ बैठक में गठबंधन पर सहमति बनी थी। सीटों के तालमेल को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं हो पाने के कारण दोनों दलों ने अभी तक अपने प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की है। कांग्रेस अपनी सूची शनिवार को जारी कर सकती है। शुक्रवार को जिला कुलगाम के अंतर्गत दम्हाल हांजीपोरा विधानसभा सीट के लिए पार्टी प्रत्याशी सकीना इट्टू का नामांकन पत्र जमा कराने के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि प्रदेश में 90 सीटों में से अधिकांश पर दोनों दलों के बीच सहमति बन चुकी है। कुछ एक सीटों पर गतिरोध बना हुआ है, उसे भी जल्द हल कर लिया जाएगा। इसके लिए दोनों दलों के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता जारी है। हालांकि उमर ने यह नहीं बताया कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, लेकिन संबंधित सूत्रों की मानें तो कांग्रेस 40 और नेकां 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा अगर इनके गठजोड़ में कोई और दल भी शामिल होता है तो दोनों अपने-अपने कोटे से उसके लिए सीट छोड़ेंगे। माकपा के लिए कुलगाम सीट को नेकां ने अपने कोटे से छोड़ा है। उमर ने कहा कि जिन सीटों पर गतिरोध बना हुआ है, उन पर दोनों दल अपना-अपना दावा जता रहे हैं। उमर ने पहले चरण के लिए प्रत्याशियों की सूची में देरी पर कहा कि हमें कोई जल्दी नहीं है। हम अपने प्रत्याशियों को लेकर पूरी तरह स्पष्ट हैं। हम अपने सभी प्रत्याशियों की सूची अगले तीन चार दिन में संभवतः 27 अगस्त तक सार्वजनिक कर देंगे। उन्होंने कि हमारा यहां मुकाबला पीडीपी से ही है।

भाजपा के बेफिक्र रवैये से विपक्ष हुआ आक्रामक

बिछी बिसात ▸ प्राइवेट सेक्टर में बढ़ती जा रही बेरोजगारी दर, सीएम ने भत्ता 500 रुपये बढ़ाया

अनुराग अग्रवाल • जागरण

चंडीगढ़ : विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। प्रदेश की भाजपा सरकार ने 10 साल के कार्यकाल में करीब डेढ़ लाख युवाओं को योग्यता व मैरिट के आधार पर सरकारी नौकरियां प्रदान की हैं, लेकिन सिर्फ नौकरियों से राज्य की बेरोजगारी दर को कम करने में मदद नहीं मिल पाई है। प्रदेश में इस समय 37.4 प्रतिशत के साथ भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई है, जो कि राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है। हरियाणा सरकार सेंटर फार मानीटरिंग इंडियन इकोनामी (सीएमआइआइ) के इन आंकड़ों को मानने के लिए तैयार नहीं है।

मुद्दा बेरोजगारी

भाजपा सरकार की अपनी दलील है। न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश में बेरोजगारी दर कभी स्थिर नहीं रहती। यह हर माह घटती-बढ़ती रहती है। सरकार की नजर में प्रदेश में लगभग छह प्रतिशत बेरोजगारी दर है, जो कि सामान्य स्तर पर है। ऐसे में राज्य में बढ़ती बेरोजगारी के दावों को लेकर भाजपा बिल्कुल भी चिंतित दिखाई नहीं दे रही है, जबकि कांग्रेस इस मुद्दे पर बड़े ही आक्रामक ढंग से विधानसभा के चुनावी समर में ताल ठोंकती दिखाई पड़ रही है। बेरोजगारी के मुद्दे पर जननायक जनता पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल और आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस के सुर में सुर मिलाते नजर आ रहे हैं। जननायक जनता पार्टी तो करीब साढ़े चार साल तक भाजपा के साथ सरकार में रही है, लेकिन सत्ता से हटते ही बेरोजगारी के मुद्दे पर उसके तेवर बदल गए हैं। करीब ढ़ाई करोड़ की आबादी वाले हरियाणा में 2.1 करोड़ मतदाता हैं। सरकारी कर्मचारियों की संख्या चार लाख के आसपास है। इनमें पौने तीन लाख कर्मचारी नियमित व करीब सवा लाख कर्मचारी अनुबंध पर काम कर रहे हैं। हर साल 10 हजार कर्मचारी रिटायर होते हैं, लेकिन नये भर्ती होने वाले नियमित कर्मचारियों की संख्या काफी कम है।

भाजपा सरकार का दावा

10 साल के कार्यकाल में 1.50 लाख सरकारी नौकरियां दी

विपक्ष का दावा

- तीन गुना बेरोजगारी दर बढ़ी भाजपा के कार्यकाल में, 10 हजार कर्मी हर साल रिटायर हो रहे नियमित भर्तियां कम

10 साल में नौकरियां अधिक दी, पेपर लीक की घटनाएं भी ज्यादा हुई

पिछली कांग्रेस और इनेलो की सरकारों के कार्यकाल से अगर सरकारी भर्तियों की तुलना की जाए तो भाजपा ने सबसे अधिक भर्तियां अपनी सरकार में की हैं, लेकिन यह भी सच है कि पेपर लीक की घटनाएं भी इसी कार्यकाल में सबसे ज्यादा सामने आई है। भाजपा पेपर लीक की घटनाओं को माफिया पर शिकंजा कसने के रूप में देखती है। उसकी दलील है कि यदि हम शिकंजा नहीं कसते तो कांग्रेस और इनेलो के राज की तरह माफिया दबा रह जाता और कभी सामने नहीं आ पाता। हमने कम से कम माफिया को उखाड़कर फेंकने का काम तो किया है। भाजपा ने अपने राज में डेढ़ लाख सरकारी भर्तियों के अलावा करीब 35 लाख लोगों को रोजगार देने का दावा किया है, लेकिन कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोस व रास में सवाल उठाए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बेरोजगारी भत्ता बढ़ा दिया है। मगर बड़ा सवाल यह है कि जब तक राज्य में बेरोजगारी दूर करने की सर्व स्वीकार्य पालिसी नहीं बनेगी, तब तक यूथ रोजगार के लिए लाइनों में खड़ा नजर आता रहेगा।

बेरोजगारी के आंकड़ों में बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने राज्य में सेंटर फार मानीटरिंग इंडियन इकोनामी (सीएमआइआइ) के आंकड़ों को कभी स्वीकार नहीं किया। उनका कहना है कि यह एजेंसी कांग्रेस नेता की है और वह गफलत पैदा करने के लिए ऐसे आंकड़े जारी करते हैं। 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग में हरियाणा की बेरोजगारी दर 17.5 प्रतिशत है, जबकि 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग में यह दर 6.4 प्रतिशत तथा 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में यह दर 6.1 प्रतिशत है। सीएमआइआइ राज्य में बेरोजगारी के आंकड़े जारी करते हुए उसमें बच्चों, बुजुर्ग लोगों व महिलाओं को भी शामिल कर लेते हैं, जो कि तथ्यात्मक रूप से बिल्कुल भी सही नहीं है। मनोहर लाल की दलील है कि राज्य में बेरोजगारी दर पूरी तरह से नियंत्रण में हैं। पांच से छह प्रतिशत बेरोजगारी दर सामान्य बात होती है और हरियाणा में इतने ही आंकड़े हैं।

राहुल गांधी के दौरे के 24 घंटे के भीतर कांग्रेस को पुंछ से झटका

जागरण संवाददाता • राजौरी

- दिग्गज नेता अब्दुल गनी ने कांग्रेस छोड़ी, अमित शाह से मुलाकात
- भाजपा में होंगे शामिल, पुंछ-हवेली से मिल सकती है टिकट
- नेकां और कांग्रेस से गठबंधन और सीट बंटवारे से से खफा थे

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के जम्मू-कश्मीर दौरे के 24 घंटे के भीतर पुंछ से कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। नेशनल कान्फ्रेंस से गठबंधन और सीट बंटवारे से नाराज कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे चौधरी अब्दुल गनी ने शुक्रवार को दिल्ली पहुंच कर गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। टिकट न मिलने की स्थिति साफ होने के बाद उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। उम्मीद है कि वह एक-दो दिन में भाजपा में शामिल जाएंगे।

अब्दुल गनी कांग्रेस की टिकट से पुंछ-हवेली क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए पूरी तैयारी में थे, लेकिन कांग्रेस व नेकां के बीच गठबंधन तय होने के बाद नेकां के उम्मीदवार एजाज जान का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। इसके बाद अब्दुल गनी ने कांग्रेस से अलग होकर भाजपा में शामिल होने का फैसला किया। वीरवार को गनी ने समर्थकों के साथ बैठक की और उसके बाद वह दिल्ली रवाना हो गए। वहां गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर कई मुद्दों पर बातचीत की। लगभग यह तय हो चुका है कि अब्दुल गनी अब भाजपा में शामिल होंगे। वह पार्टी के उम्मीदवार भी पुंछ-हवेली विधानसभा से क्षेत्र हो सकते हैं।

पुंछ में काफी जनाधार : बता दें कि अब्दुल गनी का पुंछ में काफी जनाधार माना जाता है। 2014 में उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और वह दूसरे स्थान पर रहे थे। इसके बाद वह कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस की तरफ पुंछ से जिला विकास परिषद (डीडीसी) सदस्य चुने गए और उनकी बेटी ताजीम अख्तर नंगाली साहब से। मौजूदा समय में उनकी बेटी जिला विकास परिषद की पुंछ से चेयरमैन है। इनके वोट बैंक को देखते हुए भाजपा इन्हें टिकट देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पुंछ से अगर अब्दुल गनी को भाजपा अपना उम्मीदवार बना देती है तो नेकां व भाजपा में कांटे की टक्कर हो सकती है।

दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से भेंट करते चौधरी अब्दुलगनी। इंटरनेट

हरियाणा का चुनावी दंगल लड़ेंगे ओलिंपियन विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया!

राज्य ब्यूरो, जागरण • चंडीगढ़

- चचेरी बहन बबीता फोगाट के विरुद्ध चरखी दादरी से विनेश के चुनाव लड़ने की संभावना
- सोनीपत के बरौदा में योगेश्वर दत्त के विरुद्ध मोर्चा खोल सकते हैं बजरंग पुनिया

विनेश फोगाट। फाइल

बबीत फोगाट। फाइल

हरियाणा की राजनीति में ओलिंपियन खिलाड़ी विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। विनेश फोगाट अपनी चचेरी बहन बबीता फोगाट के विरुद्ध चरखी दादरी में ताल ठोंक सकती हैं तो बजरंग पुनिया बरौदा में पहलवान योगेश्वर दत्त के विरुद्ध ताल ठोंकते नजर आ सकते हैं।

तय मानकों से अधिक भार होने के कारण पेरिस ओलिंपिक से बाहर हुई हरियाणा की महिला पहलवान विनेश फोगाट ने शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नई दिल्ली में मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उनकी माता आशा हुड्डा और धर्मपत्नी श्वेता मिर्धा हुड्डा भी मौजूद रहे। ओलिंपिक खेलों से बाहर हो जाने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विनेश फोगाट का हौसला बढ़ाते हुए बयान दिया था कि हरियाणा की भाजपा सरकार को उन्हें राज्यसभा में भेजना चाहिए। हुड्डा के इस बयान पर राजनीतिक गलियारों में खूब बहस हुई थी। अब चर्चा चल रही है कि कांग्रेस विनेश फोगाट को विधानसभा चुनाव लड़वा सकती है। विनेश फोगाट की चचेरी बहन बबीता फोगाट भाजपा के टिकट पर चरखी दादरी से टिकट की दावेदार हैं। बबीता राष्ट्रमंडल खेलों की कुश्ती पदक विजेता रही हैं। उन्होंने साल 2019 का विधानसभा चुनाव चरखी दादरी से ही भाजपा के टिकट पर लड़ा था, लेकिन निर्दलीय सोमवीर सांगवान से हार गई थी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा के मुताबिक यदि विनेश फोगाट विधानसभा चुनाव लड़ी तो उन्हें चरखी दादरी से ही बबीता फोगाट के सामने उतारा जा सकता है। इसी तरह सोनीपत के बरौदा में भाजपा के संभावित उम्मीदवार पहलवान योगेश्वर दत्त के मुकाबले में कांग्रेस पहलवान बजरंग पुनिया को चुनावी दंगल में उतार सकती है। जानकारी मिल रही है कि दोनों को कांग्रेस की ओर से मनाने की कोशिश की जा रही है। विनेश और पूनिया को राजनीतिक चेहरों के तौर पर तभी से देखा जाने लगा था, जब दोनों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृज भूषण के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाते हुए दिल्ली के जंतर-मंतर मैदान में मोर्चा खोला था।

दिग्गजों के अपनों को टिकट देने की चुनौती से जूझ रही भाजपा

अनुराग अग्रवाल • जागरण

चंडीगढ़: हरियाणा में एक अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा 'एक परिवार-एक टिकट' की अपनी नीति पर कायम रहने के साथ-साथ राज्य के असरदार राजनीतिक परिवारों को खुश करने की चुनौती से जूझ रही है। भाजपा में करीब एक दर्जन ऐसे रसूखदार नेता हैं, जो देश और प्रदेश की राजनीति में अपना अच्छा हस्तक्षेप रखते हैं। वे स्वयं भी पार्टी में महत्वपूर्ण पदों पर हैं और अब विधानसभा चुनाव में अपने परिवार के सदस्यों के लिए टिकट मांग रहे हैं।

भाजपा के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसने हरियाणा में हमेशा परिवारवाद की राजनीति पर कड़े प्रहार किए हैं। प्रदेश की राजनीति में देवीलाल (दिवंगत), चौधरी बंसीलाल और भजनलाल (दिवंगत) के परिवारों का पूरा वर्चस्व तथा हस्तक्षेप है। राजनीति के सार्वजनिक मंचों से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तक इन लाल परिवारों के परिवारवाद पर जमकर हमला बोल चुके हैं। मोदी और शाह के निशाने पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा तक रहे हैं। अगर भाजपा हरियाणा के चुनाव में अपनी पार्टी के प्रमुख नेताओं के परिजनों को टिकट देती है तो उसे विपक्ष के सवालों का जबरदस्त तरीके से सामना करना पड़ेगा। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के नतीजे भाजपा की अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहे हैं। साल 2019 में राज्य की सभी 10 लोकसभा सीटें जीतने वाली भाजपा साल 2024 में सिर्फ पांच लोकसभा सीटों तक सिमट गई है। ऐसे में भाजपा के समक्ष राज्य में येन-केन-प्रकारेण तीसरी बार सरकार बनाने की बहुत बड़ी चुनौती है। पिछले दिनों फरीदाबाद में हुई आरएसएस और भाजपा की समन्वय बैठक में भाजपा नेताओं द्वारा परिवार के सदस्यों के लिए मांगे जा रहे टिकटों को लेकर चर्चा हुई थी। आरएसएस इस हक में नहीं था कि भाजपा में परिवारवाद की राजनीति को हवा दी जाए, लेकिन रणनीतिकारों का मानना है कि इस चुनाव में एक-एक सीट पर जीत हासिल करना बहुत जरूरी है।

देवीलाल। फाइल

बंसीलाल। फाइल भजनलाल।

कृष्णपाल गुर्जर। फाइल

किरण चौधरी। फाइल

कृष्णपाल गुर्जर और किरण चौधरी के परिजनों की दावेदारी, धनखड़ भी बेटे के लिए हैं प्रयासरत

केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर अपने बेटे देवेंद्र चौधरी के लिए तिगांव और बड़खल से टिकट मांग रहे हैं। देवेंद्र चौधरी की पहली दावेदारी तिगांव को लेकर है। बड़खल से कृष्णपाल गुर्जर के समर्थक धनेश अदलखा भी टिकट की दौड़ में शामिल हैं। भिवानी-महेंद्रगढ़ के भाजपा सांसद चौधरी धर्मबीर सिंह अपने बेटे मोहित चौधरी के लिए सोहना और चरखी दादरी से टिकट मांग रहे हैं। भाजपा की राज्यसभा सदस्य बनने को तैयार किरण चौधरी अपनी बेटी पूर्व सांसद श्रुति चौधरी के लिए तोशाम से टिकट की दावेदारी कर रही हैं। तोशाम से किरण चौधरी विधायक रही हैं और भाजपा में अपनी बेटी का राजनीतिक भविष्य सुरक्षित करने का इरादा रखती हैं। भाजपा के नेशनल सेक्रेटरी ओमप्रकाश धनखड़ अपने बेटे आदित्य धनखड़ को राजनीतिक में स्थापित करने के लिए प्रयासरत हैं।

विश्लेषण

हरियाणा विधानसभा चुनाव में हाट सीट अंबाला छावनी से इस बार छह बार के विधायक रहे अनिल विज चुनाव लड़ेंगे या नहीं, यह तो अभी पता नहीं लेकिन उनके सामने साख बचाने की चिंता है

विज के लिए साख बचाने की चुनौती, कांग्रेस में घमासान

दीपक बहल • जागरण

अंबाला : अंबाला छावनी विधानसभा सीट प्रदेश की हाट सीटों में गिनी जाती है। प्रदेश के पूर्व गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री यहां से छह बार विधायक रहे हैं। लगातार पिछले तीन चुनाव जीतकर वह हैट-ट्रिक बना चुके हैं। सातवीं बार उनके सामने साख बचाने की बड़ी चुनौती है। इस बार भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। इनेलो-बसपा भी इस बार प्रत्याशी उतारेगी।

कांग्रेस में टिकटों को लेकर अभी घमासान मचा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा के नजदीकियों में टिकट लेने की होड़ लगी है। इसमें पूर्व मंत्री चौधरी निर्मल सिंह की बेटी चित्रा सरवारा भी लाइन में हैं। निर्मल सिंह परिवार हुड्डा के नजदीक माना जाता है। दूसरी ओर, कुमारी सैलजा के नजदीकी परविंद्र सिंह परी और उनकी पत्नी निमृत कौर भी टिकट के लिए जोर लगा रहे हैं। अब किसकी नजदीकियों का किसे फायदा मिलेगा, यह टिकट मिलने के बाद पता चलेगा। हालांकि इन तीनों के अलावा भी 11 लोग और टिकट के लिए लाइन में हैं।

सुषमा स्वराज के राज्यसभा जाने के बाद अनिल विज की हुई एंट्री

पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की परवरिश और पढ़ाई अंबाला छावनी में ही हुई। वर्ष 1990 में सुषमा स्वराज को राज्यसभा में भेज दिया गया था। इसके बाद उपचुनाव में अनिल विज की एंट्री हो गई। विज विधायक बन गए। सभी भाजपा के दिग्गज नेता भगवानदास सहगल की पैरवी कर रहे थे, लेकिन सुषमा स्वराज ने विज का समर्थन किया था।

तमाम विरोधों के बावजूद विज पर एक बार फिर भाजपा खेल सकती दांव

अनिल विज विधायक बनने के बाद मनोहर सरकार में पहले स्वास्थ्य एवं खेल मंत्री बने और फिर बाद में निकाय जैसा महत्वपूर्ण महकमा भी उनके पास आ गया। बाद में हालांकि विभागों में बदलाव होता रहा। खेल और निकाय उनके हाथ से चला गया और उसके अलावा दूसरे विभाग उनके पास आ गए। इसी बीच गृह विभाग भी उनके पास आ गया, लेकिन बीच में ही सीएम नायब सिंह सैनी को बना दिया गया, लेकिन इसमें विज को कोई मंत्री पद नहीं मिल पाया। विस चुनावों को लेकर भाजपा ने बीस नेताओं की लिस्ट जारी की थी, जिसमें विज का नाम नहीं था। बाद में विज का नाम जोड़ा गया।

अंबाला छावनी में विस चुनाव परिणाम

वर्ष	विजेता दल
1967	डी.आर. आनंद कांग्रेस
1968	भगवान दास भारतीय जन संघ
1972	हंस राज सूरी कांग्रेस
1977	सुषमा स्वराज जनता पार्टी
1982	राम दास धमीजा कांग्रेस
1987	सुषमा स्वराज भाजपा
1990	अनिल विज भाजपा
1991	बृज आनंद कांग्रेस
1996	अनिल विज निर्दलीय
2000	अनिल विज निर्दलीय
2005	देवेंद्र कुमार बंसल कांग्रेस
2009	अनिल विज भाजपा
2014	अनिल विज, भाजपा
2019	अनिल विज भाजपा

हरियाणा में कुमारी सैलजा ने पेश की मुख्यमंत्री पद की दावेदारी

राज्य ब्यूरो, जागरण • चंडीगढ़

कांग्रेस नेता ने केंद्र की बजाय अब हरियाणा में काम करने की इच्छा जताई

कांग्रेस महासचिव एवं सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने हरियाणा में पार्टी की सरकार बनने की स्थिति में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पेश की है। उन्होंने कहा कि ''व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर'' किसी की भी महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं। लेकिन यह पार्टी और हाईकमान को तय करना है कि वह किसे मुख्यमंत्री बनाता है। सैलजा ने विधायक के तौर पर हरियाणा में काम करने की इच्छा भी जाहिर की है।

नई दिल्ली में प्रेट्र को दिए एक इंटरव्यू में सैलजा ने कहा कि मैं विधानसभा चुनाव भी लड़ना चाहती हूं, लेकिन इसका फैसला भी पार्टी हाईकमान को करना है। कांग्रेस की जीत की संभावना में गुटबाजी के भारी पड़ने से जुड़े सवाल पर सैलजा ने कहा कि जब चुनाव आते हैं तो हर कोई ''एक कांग्रेस शिविर'' के रूप में मिलकर काम करता है। किसी भी संगठन में अपनी जगह बनाने के लिए धक्का-मुक्की हमेशा होती रहती है और आगे भी होती रहेगी। लेकिन कांग्रेस में यह सिर्फ टिकटों की घोषणा होने तक है। आखिरकार सभी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। इसे गुटबाजी से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। चुनाव के बाद गठबंधन की संभावना से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलने वाला है। हम जमीनी स्तर पर लोगों के संपर्क में हैं और वे पूरी तरह से भाजपा के खिलाफ हैं। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी के काम करने के कुछ तरीके हैं।

****

27 अगस्त को भी जारी रहेगी भाजपा के राज्यसभा सदस्य हर्ष महाजन के चुनाव को चुनौती देने वाली अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका पर सुनवाई। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में हर्ष महाजन की ओर से याचिका को गुणवत्ताहीन ठहराते हुए खारिज करने की मांग वाले आवेदन पर बहस शुरू हुई थी।

हाई कोर्ट के आदेश के बाद आघाड़ी ने वापस लिया महाराष्ट्र बंद का आह्वान

राज्य ब्यूरो, जागरण ● मुंबई

बांबे हाई कोर्ट द्वारा राजनीतिक दलों या व्यक्तियों को महाराष्ट्र बंद का आह्वान करने से रोकने के बाद विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी (मविआ) ने 24 अगस्त को आहूत प्रदेशव्यापी बंद वापस ले लिया है। मविआ ने ठाणे के बदलापुर में एक स्कूल में दो बच्चियों के कथित यौन उत्पीड़न के विरोध में बंद का आह्वान किया था। पहले राकांपा (शप) के अध्यक्ष शरद पवार ने बंद वापस लेने की घोषणा की। बाद में शिवसेना (यूबीटी) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा कि अब मविआ के नेता और कार्यकर्ता पूरे राज्य में जगह-जगह मुंह पर काली पट्टी बांधकर एवं हाथों में काला झंडा लेकर प्रदर्शन करेंगे। यह प्रदर्शन एक घंटे का होगा।

शुक्रवार को बांबे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार बंद को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। न्यायाधीशों ने कहा कि वे बंद के आह्वान को चुनौती देने वाली अधिवक्ता सुभाष झा और गुणरत्न सदावर्ते के माध्यम से दायर दो याचिकाओं पर शीघ्र ही विस्तृत आदेश पारित करेंगे। उन्होंने कहा कि हम किसी भी राजनीतिक दल और/या किसी भी व्यक्ति को बंद का आह्वान करने से रोक रहे हैं क्योंकि इससे राज्य में सामान्य जनजीवन अस्तव्यस्त हो जाएगा। राज्य को इस संबंध में सभी निवारक कदम उठाने होंगे। हाई कोर्ट ने जुलाई, 2004 में हाई कोर्ट के ही एक फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि बंद या हड़ताल (कामकाज और कारोबार को रोकना) असंवैधानिक कृत्य माना जाएगा। इसमें कहा गया था कि अगर बंद किया जाता है, तो आह्वान करने वाले राजनीतिक दल पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उससे जान, संपत्ति या आजीविका के किसी भी नुकसान की भरपाई की जाएगी। सुनवाई के दौरान राज्य के महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने बताया कि बंद का आह्वान अवैध है। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाएगी कि मानव जीवन या संपत्ति को कोई नुकसान या विनाश न हो। राज्य अपना कर्तव्य निभाएगा। लेकिन यह सभी की संवैधानिक जिम्मेदारी है, जिनका उन्हें पालन करना चाहिए। अधिवक्ता झा और सदावर्ते ने केरल हाई कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए याचिका में कहा कि कोई भी राजनीतिक दल राज्यव्यापी बंद का आह्वान नहीं कर सकता, और हाई कोर्ट के पास ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने की पर्याप्त शक्तियां हैं। उन्होंने मराठा आरक्षण आंदोलन का भी उदाहरण दिया, जिस दौरान बड़ी मात्रा में सार्वजनिक संपत्ति नष्ट कर दी गई थी।

बाम्बे हाई कोर्ट। फाइल

- बदलापुर में दो स्कूली बच्चियों के यौन उत्पीड़न के विरोध में किया था आह्वान
- शरद पवार ने की घोषणा, उद्धव बोले- मुंह पर काली पट्टी बांधकर करेंगे प्रदर्शन
- हाई कोर्ट ने बंद पर रोक लगाते हुए कहा, अस्तव्यस्त हो जाएगा सामान्य जनजीवन

उम्मीद है इसी तेजी से फैसले करेगी अदालत : उद्धव

हाई कोर्ट का फैसला आने से पहले उद्धव ने कहा था कि महाविकास आघाड़ी द्वारा बुलाया गया 'महाराष्ट्र बंद' राजनीतिक नहीं है, बल्कि एक 'विकृति' के विरुद्ध है। उन्होंने जाति-धर्म से ऊपर उठकर लोगों से इसमें भाग लेने का आग्रह किया था। उद्धव का कहना था कि बंद का उद्देश्य सरकार को यह अहसास दिलाना है कि व्यवस्था को अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी लगन से करना चाहिए। जबकि हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद उद्धव ने कहा, 'हम फैसले से सहमत नहीं हैं। हम इसे चुनौती दे सकते हैं, लेकिन अब हमने बंद का आह्वान करने के बजाय राज्यव्यापी प्रदर्शन करने का निर्णय किया है। हमें उम्मीद है कि अदालत इसी तेजी से उन मामलों पर फैसला करेगी जिनके लिए बंद का आह्वान किया गया था।'

अपील के लिए समय नहीं: शरद पवार: राकांपा (शप) प्रमुख शरद पवार ने कहा, 'बंद का उद्देश्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना था। यह संविधान प्रदत्त मूल अधिकारों के तहत था, लेकिन बांबे हाई कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया है। समय की कमी के कारण सुप्रीम कोर्ट में तत्काल अपील संभव नहीं है। भारतीय न्याय व्यवस्था का हम सम्मान करते हैं, इसलिए हम बंद का आह्वान वापस लेने की अपील करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में बच्चियों और महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार बढ़ रहे हैं।'

राजनीति कर रहा विपक्ष : शिंदे

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नासिक में लाड़की बहन योजना से संबंधित समारोह में उद्धव ठाकरे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कुछ लोग मुख्यमंत्री पद पाने के लिए इतने उत्सुक हैं कि वे इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। यह गलत है। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इसी समारोह में बंद का आह्वान करने के लिए विपक्ष की आलोचना की। गृह मंत्रालय के प्रभारी फडणवीस ने कहा कि यह बंद राजनीति के लिए है। उन्होंने कहा कि उसने कोलकाता में महिला डाक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या पर ममता बनर्जी सरकार के विरुद्ध कोई स्टैंड नहीं लिया, लेकिन यहां अपने स्वार्थ के लिए बंद का आह्वान कर रहा है।

एकनाथ शिंदे।

बदलापुर मामले में स्कूल प्रबंधन के खिलाफ एफआइआर दर्ज

मिड-डे, मुंबई: महाराष्ट्र के बदलापुर में बच्चियों के यौन उत्पीड़न के मामले में स्कूल प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज कर ली गई है। मामले में विशेष जांच दल (एसआइटी) ने बताया कि पाक्सो अधिनियम की धारा 19 के प्रविधानों का पालन न करने के लिए यह एफआइआर दर्ज की गई है। एसआइटी अब यह पता लगाने के लिए जांच करेगी कि स्कूल की ओर से इसके लिए कौन जिम्मेदार है। अधिकारी अब स्कूल के कर्मचारियों के बयान ले रहे हैं। घटना के बाद बच्चियों के माता-पिता की सूचना पर कार्रवाई करने में देरी क्यों हुई? एसआइटी सभी पहलुओं की जांच कर रही है। प्राथमिकी में कहा गया है कि जब भी किसी अधिकारी को नाबालिगों के खिलाफ इस तरह के यौन उत्पीड़न के बारे में पता चलता है तो उसे आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस अधिकारियों को इसकी सूचना देना अनिवार्य है। मामले में दोनों पीड़ितों और उनके माता-पिता के बयान भी दर्ज किए गए हैं।

असम में नाबालिग हिंदू से सामूहिक दुष्कर्म

थम नहीं रही दरिंदगी ▶ धींग इलाके में ट्यूशन से घर लौट रही नाबालिग पर हमला

एक आरोपित गिरफ्तार, एक हिरासत में, औरों की तलाश जारी

गुवाहाटी, प्रेट्र: असम के नागांव जिले में 14 साल की हिंदू लड़की से बर्बरता की गई है। धींग इलाके में ट्यूशन से घर लौट रही नाबालिग को बीच रास्ते में घेर कर तीन लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया है। इस घटना से गुस्साए क्षेत्रीय लोग सड़कों पर विरोध करने आ गए और उन्होंने बंद का भी आह्वान किया है। पुलिस इस बीच इस मामले में एक आरोपित को गिरफ्तार कर दूसरे को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पोक्सो और संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।

मुख्यमंत्री हिमंत सरमा ने हैलाकांडी में शुक्रवार को इस घटना पर रोष जताते हुए कहा कि दुष्कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस का कहना है कि दसवीं कक्षा की छात्रा धींग क्षेत्र में जब रात आठ बजे अपनी साइकिल से घर वापस लौट रही थी तो वहां मोटरसाइकिल सवार तीन लोगों ने उसे घेरकर उस पर हमला किया और उससे सामूहिक दुष्कर्म किया। बाद में उसे राहगीरों ने सड़क किनारे एक तालाब के पास अचेतावस्था में देखा और पुलिस को सूचना दी। पहले नाबालिग लड़की को धींग स्थित स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, फिर इसके इलाज और चिकित्सकीय जांच के लिए नागांव स्थित अस्पताल में शिफ्ट किया गया। डाक्टरों के अनुसार अब लड़की की हालत स्थिर है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और दूसरे को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। डीजीपी जीपी सिंह धींग ने कहा कि अगर कुछ ही दिनों में जियो-टैगिंग हो जाएगी तो क्षेत्र में ऐसा सुरक्षा प्लान लागू किया जा सकेगा, जिससे भविष्य में फिर कोई ऐसी वारदात न हो। स्थानीय दुकानदारों ने सड़कों पर उतर कर विरोध-प्रदर्शन करते हुए कार्रवाई की मांग की।

असम महिला कांग्रेस मीरा बोरठाकुर गोस्वामी और अन्य सदस्यों ने राजीव भवन में नागांव में एक नाबालिग लड़की के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। एएनआइ

> 'लोकसभा चुनाव के बाद राज्य में समुदाय विशेष के लोग बहुत सक्रिय हो गए हैं और उन्हें घृणित अपराधों को अंजाम देने का बढ़ावा दिया जा रहा है। पिछले दो महीनों में महिलाओं के खिलाफ ऐसे 22 अपराध हो चुके हैं और यह 23वीं वारदात है।'
> –हिमंत बिस्व सरमा, मुख्यमंत्री, असम

'जिन इलाकों में देशी लोग अल्पसंख्यक, भय में जी रहे'

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने आरोप लगाया, 'लोकसभा चुनाव के बाद यह देखा जा रहा है कि समुदाय विशेष के लोग बहुत सक्रिय हो गए हैं और उन्हें ऐसे घृणित अपराधों को अंजाम देने का बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य में पिछले दो महीनों में महिलाओं के खिलाफ ऐसे 22 अपराध हो चुके हैं और यह 23वीं वारदात है। हम अपराधियों को सबक सिखाएंगे और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।' उन्होंने कहा कि जिन भी अपराधियों ने धींग की नाबालिग हिंदू लड़की से यह जघन्य अपराध किया है, उन्हें कानून छोड़ेगा नहीं। उन्होंने डीजीपी और जल संसाधन मंत्री पिजूष हजारिका को तत्काल धींग पहुंचकर सख्त से सख्त कार्रवाई करने को कहा है। सरमा ने कहा कि निचले और मध्य असम और बराक घाटी जिलों में जहां देशी लोग अल्पसंख्यक हो गए हैं, वह यहां लगातार भय में जीते आ रहे हैं। लेकिन इन इलाकों से बाहर के लोग ऐसी क्रूर वास्तविकता की कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं। सरमा ने कहा, 'मैं इन घृणित अपराधों को अंजाम देने वाले असली बदमाशों को ढूंढ निकालूंगा। मैं हिंदू समाज के ही अलग-अलग समुदाय के लोगों पर इसका दोषारोपण नहीं करूंगा।'

मुरादाबाद में नर्स से दुष्कर्म के आरोपित के पिता के तीनों मदरसे सील

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में नर्स से दुष्कर्म के आरोपित शाहनवाज पर शिकंजा कसता जा रहा है। शुक्रवार को उसके पिता कारी सगीर के तीनों मदरसों को सील कर दिया गया। इनमें न बच्चे मिले न ही स्टाफ। दो मदरसों के भवन अवैध कब्जा कर बनवाए गए हैं। इनमें से एक में आवास भी है। माना जा रहा है कि मान्यता कराकर मदरसों के नाम पर फंडिंग ली जा रही होगी। तीनों मदरसों को ध्वस्त करने की भी तैयारी की जा रही है। अवैध भवन में मान्यता देने से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भी संदेह के दायरे में आ गया है।

ठाकुरद्वारा के एपेक्स हास्पिटल में 17 अगस्त को नर्स के साथ दुष्कर्म किया गया था। इसके मुख्य आरोपित हास्पिटल संचालक शाहनवाज, नर्स मेहनाज और वार्ड ब्वाय जुनैद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वारदात के वक्त शाहनवाज के पिता कारी सगीर भी हास्पिटल में भर्ती था। सगीर पैतृक गांव राजपुर केसरिया में दो और जटपुरा में एक मदरसे का संचालन करता है। गुरुवार को पुलिस व प्रशासनिक टीम ने गांव में जाकर पता किया तो जानकारी हुई कि गांव के बाहरी ओर खाद के गड्ढे के नाम दर्ज करीब ढाई बीघा जमीन पर कब्जा कर दो मदरसे, उनमें एक में आवास बना रखा था।

शुक्रवार को एसडीएम मणि अरोड़ा, सीओ राजेश कुमार, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के साथ लेकर फिर गांव गई। वहां बच्चे और स्टाफ नहीं मिले। दोनों मदरसों में ताला लगा था। ग्रामीणों ने भी उनमें पढ़ाई होने की पुष्टि नहीं की। लिहाजा दोनों मदरसों को सील कर दिया गया। जटपुरा में आबादी में मदरसा है। उसमें ताला लटका था। लिहाजा उसे भी सील कर दिया गया।

10 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म का आरोपित गिरफ्तार

अकोला, प्रेट्र: महाराष्ट्र के अकोला में 10 वर्षीय बच्ची के साथ एक साल तक कई बार दुष्कर्म करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आरोपित पीड़िता का रिश्तेदार है। बच्ची पढ़ाई के लिए अपने रिश्तेदार के यहां रह रही थी, जहां आरोपित ने कई बार घर में अकेली होने पर उसका यौन उत्पीड़न किया। वहीं, ठाणे जिले में पुलिस ने एक प्राइवेट आश्रम के निदेशक के खिलाफ ढाई साल की बच्ची के शरीर को जलाने के आरोप में मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने बताया कि बच्ची के माता-पिता भिखारी हैं।

आदिवासी लड़की ने की आत्महत्या: पालघर जिले में एक सरकारी आश्रम स्कूल के छात्रावास में 18 वर्षीय आदिवासी छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। जौहर पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि छात्रावास के कमरे में कक्षा 10 की छात्रा शुभांगी रामदास पागी का शव फंदे से लटका हुआ मिला था। घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। आत्महत्या के कारण का पता लगाने के लिए जांच जारी है।

फर्जी एनसीसी कैंप में दुष्कर्म का आरोपित ने की आत्महत्या: तमिलनाडु में फर्जी एनसीसी शिविर में स्कूल की छात्रा का यौन उत्पीड़न करने के मामले के मुख्य आरोपित ने शुक्रवार को आत्महत्या कर ली है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शिवरमन ने 19 अगस्त को गिरफ्तारी से पहले चूहा मारने की दवा खाया था।

आरोपित व दोस्त समेत सात का होगा पालीग्राफ टेस्ट

दुष्कर्म-हत्या कांड

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता

महिला डाक्टर से दुष्कर्म व हत्या के मामले में गिरफ्तार संजय राय के साथ उसके एक दोस्त का भी पालीग्राफ टेस्ट होगा। सियालदह कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने टेस्ट की अनुमति दे दी है। आरजी कर मेडिकल कालेज एवं अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, चार जूनियर डाक्टर समेत कुल सात लोगों का पालीग्राफ टेस्ट किया जाएगा। सीबीआइ का कहना है आरोपित संजय वारदात के बाद अस्पताल और सेमिनार हाल में जाने को लेकर भ्रामक जानकारी दे रहा है। इसी कारण पालीग्राफ टेस्ट जरूरी है। आरोपित के दोस्त के बारे में सूत्र बताते हैं कि वह टाला थाने का एएसआइ अनूप दत्त है। सीबीआइ ने पिछले दिनों उससे पूछताछ की थी। अनूप की सहायता से ही संजय को पुलिस बैरक में आसानी से प्रवेश की अनुमति मिलती थी।

आरोपित की वकील बोलीं-...तो नहीं करती पैरवी: आरोपित संजय राय को शुक्रवार को सियालदह कोर्ट में पेश किया गया, जहां न्यायाधीश ने उसे न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। आरोपित की ओर से सरकारी वकील कविता सरकार ने जमानत के लिए अर्जी भी दी। इस मामले में संजय की तरफ से कोई वकील पैरवी को तैयार नहीं हो रहा था तो नियमानुसार कोर्ट के आदेश पर कविता को यह जिम्मेदारी दी गई है। कविता ने कहा कि अगर वह लीगल एड की सदस्य नहीं होतीं तो इस केस में पैरवी नहीं करतीं। उन्होंने बताया कि संजय ने कहा है कि वह बेकसूर है व पालीग्राफ टेस्ट के लिए तैयार है। इसके पहले पुलिस ने कहा था कि संजय राय ने जुर्म कबूल कर लिया है। संजय को प्रेसिडेंसी जेल में रखा गया है। पास ही बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी व राशन घोटाले में गिरफ्तार पूर्व खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक बंद हैं।

जांच के घेरे में दरवाजे की टूटी कुंडी: सीबीआइ इस बात की जांच कर रही है कि सेमिनार हाल में बिना किसी बाधा के वारदात को कैसे अंजाम दिया गया। हाल के दरवाजे की कुंडी टूटी थी। सीबीआइ अधिकारी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कोई व्यक्ति सेमिनार हाल के बाहर निगरानी के लिए तैनात था।

संजय राय।

87 प्रतिशत ने छोड़ा हास्टल

वारदात के बाद से अस्पताल के करीब 87 प्रतिशत रेजिडेंट डाक्टरों ने हास्टल छोड़ दिया है। करीब 700 रेजिडेंट डाक्टर परिसर में स्थित हास्टल में रहते हैं। इनमें 450 पुरुष डाक्टर व 250 महिला डाक्टर हैं। डाक्टरों के स्वजन का कहना है कि वे अपनी संतानों को हास्टल में रहने से मना कर रहे हैं। अस्पताल प्रशासन ने कुछ बोलने से इन्कार कर दिया है।

मिमी चक्रवर्ती के बाद राजन्या को मिलीं दुष्कर्म की धमकियां

राज्य, कोलकाता: कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में महिला डाक्टर से दुष्कर्म व हत्या की वारदात के खिलाफ आवाज उठाने पर अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती के बाद अब तृणमूल कांग्रेस की महिला नेता व अभिनेत्री राजन्या हल्दर को भी इंटरनेट मीडिया पर दुष्कर्म की धमकियां मिली हैं। उन्होंने इसको लेकर गुरुवार रात दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। इसके बाद बारुईपुर पुलिस की साइबर अपराध इकाई की टीम ने जांच शुरू कर दी है। सत्तारूढ़ दल की नेता ने आरोप लगाया कि इंटरनेट मीडिया पर उनके बारे में भद्दे पोस्ट किए जा रहे हैं। उन्हें खुलेआम दुष्कर्म की धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी तस्वीर का भी इस्तेमाल कर अभद्र पोस्ट किए गए हैं। जो न्याय मांग रहे हैं, उन्हें मैं से कुछ लोग दूसरी महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं।

बैरिकेड तोड़ थानों में घुसे प्रदर्शनकारी बंगाल भाजपा के कार्यकर्ता, पुलिस से हुई झड़प

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता

कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में प्रशिक्षु महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना के विरोध में विपक्षी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग पर शुक्रवार को पूरे बंगाल में थानों का घेराव किया। भाजपा के राज्यव्यापी थाना घेराव अभियान के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर पुलिस की ओर से लगाए गए अवरोधकों (बैरिकेड) को तोड़कर थानों के अंदर घुस गए और जब पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उनके बीच जमकर झड़प हुई। प्रदेश भाजपा के शीर्ष नेताओं, सांसदों, विधायकों की अगुवाई में आयोजित घेराव अभियान के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने थानों का घेराव किया और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी व विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने घेराव अभियान के तहत पूर्व मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम थाने पर भी धावा बोल दिया, जहां जमकर बवाल हुआ। 100 से अधिक पार्टी समर्थक सुबह अवरोधकों को तोड़कर थाने में घुस गए।

▶ भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान नंदीग्राम सहित कई थानों पर बोला धावा

कोलकाता कांड के खिलाफ केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने भाजपा नेता ज्योतिर्मय सिंह महतो के साथ धरना दिया। एएनआइ

अधीर की सिब्बल से गुजारिश–चिकित्सक हत्याकांड की न करें पैरवी

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने चिकित्सक हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट में ममता सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे दिग्गज वकील कपिल सिब्बल से इस मामले से खुद को अलग करने की गुजारिश की है। उन्होंने कहा कि आपको अपराधियों की तरफदारी नहीं करनी चाहिए। आप कभी लोकसभा के चुने हुए जनप्रतिनिधि थे, अभी भी राज्यसभा के सदस्य हैं। इसलिए जनभावना का सम्मान करना चाहिए। अधीर ने आगे कहा कि इस मामले में पैरवी को लेकर इंटरनेट मीडिया पर लोग जिस तरह से आपके खिलाफ प्रतिक्रिया दे रहे हैं, इसे देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है।

कैंसर पीड़ितों का कारगर इलाज करना चाहती थीं दरिंदगी की शिकार डाक्टर

विशाल श्रेष्ठ ● जागरण

कोलकाता: आरजी कर मेडिकल कालेज अस्पताल में दरिंदगी की शिकार हुई जूनियर महिला डाक्टर फेफड़े के कैंसर के मरीजों का कारगर इलाज करना चाहती थीं। उन्होंने इस बाबत आंकोलाजी व रेडियोलाजी पर आनलाइन डिग्री कोर्स करना शुरू किया था।

मृतका के एक परिचित ने बताया कि वह कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को लेकर काफी जागरूक व गंभीर थीं। अपने स्वजनों, मित्रों व सहकर्मियों से अक्सर इसके बारे में चर्चा किया करती थीं। चूंकि वह आरजी कर अस्पताल के डिपार्टमेंट आफ चेस्ट मेडिसिन से जुड़ी थीं, जहां फेफड़े के कैंसर के बहुत से मामले आते हैं इसलिए फेफड़े के कैंसर को लेकर उनकी जिज्ञासा काफी बढ़ गई थी। इस तरह के कैंसर के लक्षण काफी देर से दिखते हैं इसलिए ज्यादातर मरीजों का इलाज देर से शुरू हो पाता है। वह बहुत दयालु स्वभाव की थीं इसलिए उनसे मरीजों की तकलीफ देखी नहीं जाती थीं। फेफड़े के कारगर इलाज में निपुण होने के लिए उन्होंने आंकोलाजी पर आनलाइन डिग्री कोर्स करना शुरू किया था। कैंसर के निदान के लिए वह रेडियोलाजी का कोर्स भी कर रही थीं। इसके अलावा वह इको-कार्डियोग्राफी का भी कोर्स कर रही थीं लेकिन अफसोस कि लोगों को कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से बचाने के बारे में सोचने वाली उस नेक महिला की समाज के कैंसरों ने जान ले ली। मालूम हो कि आंकोलाजी चिकित्सा विज्ञान की कैंसर के निदान, इलाज व प्रबंधन से संबंधित शाखा है। इसमें कैंसर होने, इसके बढ़ने के लक्षणों व कारणों के साथ इससे लड़ने के नए उपचारों व थेरेपी का अध्ययन शामिल है।

परिचित ने आगे बताया कि उनकी एक विशेषता यह भी थी कि वह पर्चों पर बेहद साफ तौर पर दवाओं का नाम लिखकर देती थीं ताकि मरीज, उसके स्वजन अथवा दवा विक्रेता को कोई परेशानी न हो। कलकत्ता मेडिकल रिसर्च इंस्टीच्यूट (सीएमआरआइ) के पल्मोनरी डिपार्टमेंट के प्रमुख डा. राजा धर ने बताया कि फेफड़े के कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ मामलों में आंत व थायरायड ग्लैंड से कैंसर फैलकर भी फेफड़ों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। इस वजह से वह इस क्षेत्र में काम करना चाहती थीं, ताकि बेहतर इलाज मिल सके।

- अस्पताल में आने वाले कैंसर के मरीजों की तकलीफें देखकर थीं काफी व्यथित
- आंकोलाजी व रेडियोलाजी पर शुरू किया था आनलाइन डिग्री कोर्स

कोलकाता में महिला डाक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के विरोध में झारखंड के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस तरह से किया प्रदर्शन। प्रेट्र

अस्पतालों के लचर ढांचे व डाक्टरों की सुरक्षा से डा. कर के वंशज निराश

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता

डा. राधा गोविंद कर की 172वीं जयंती पर उनके वंशजों ने बंगाल के सरकारी अस्पतालों के लचर ढांचे व वहां कार्यरत डाक्टरों की सुरक्षा पर निराशा जाहिर की है। मालूम हो कि आरजी कर मेडिकल कालेज अस्पताल डा. कर की ही देन है। उनके वंशजों की चौथी पीढ़ी कोलकाता से सटे हावड़ा जिले के रामराजातला इलाके में उसी घर में रह रही है, जहां 23 अगस्त, 1852 को डा. कर का जन्म हुआ था।

डा. कर ने 138 साल पहले बड़ी मुश्किल से इस अस्पताल की स्थापना की थी। परिवार के सदस्य व पेशे से फोटोग्राफर टीचर पार्थ कर ने कहा-'आजादी के करीब आठ दशक बाद भी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं व डाक्टरों की सुरक्षा को लेकर मैं काफी निराशा महसूस करता हूं। हम उनकी स्मृति का सम्मान करने में विफल रहे हैं।' मालूम हो कि डा. कर के परिवार के 30 से अधिक सदस्य, जो संयुक्त परिवार में रहते हैं, ने 14 अगस्त की रात आरजी कर कांड के विरोध में हुए प्रदर्शन में भी हिस्सा लिया था। परिवार के तीन सदस्य आरजी कर मेडिकल कालेज के पूर्व छात्र हैं। पार्थ ने कहा-'मुझे जूनियर डाक्टरों द्वारा किए जा रहे विरोध-प्रदर्शन में कुछ भी गलत नहीं दिखता। वे केवल अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं।'

आरजी कर मेडिकल कालेज और अस्पताल के संस्थापक राधा गोविंद कर की जयंती पर उनके चित्र को लेकर जाती हुई महिला डाक्टर। प्रेट्र

लंदन में भारतवंशियों ने निकाली रैलियां...

ब्रिटेन में भारतीय छात्रों, चैरिटी संस्थाओं और भारतवंशियों से जुड़े संगठनों ने कोलकाता में महिला डाक्टर से हुई दरिंदगी मामले में न्याय की मांग को लेकर रैलियां आयोजित कीं। महिला संगठनों ने गुरुवार को लंदन के पार्लियामेंट स्क्वायर और ब्रिटेन के कई अन्य शहरों में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास शांति सभा का आयोजन किया। वहीं, स्टूडेंट्स फेडरेशन आफ इंडिया, यूनाइटेड किंगडम (एसएफआइ-यूके) ने लिवरपूल में मार्च का आयोजन किया। लंदन के पार्लियामेंट स्क्वायर पर एकत्र सैकड़ों लोगों ने न्याय चाहिए के नारे लगाए। यहां उन्होंने कैंडल भी जलाए। एक चैरिटी से जुड़ी डा. दीप्ति जैन ने कहा कि अब लोगों को जागने और व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठने और एकजुटता दिखाने का समय आ गया है। एसएफआइ-यूके ने लंदन रोड से लिवरपूल के सिटी सेंटर तक मार्च के साथ छात्रों के नेतृत्व वाले शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों की श्रृंखला जारी रखी है। लिवरपूल विश्वविद्यालय में मास्टर के छात्र रौनक भट्टाचार्य ने कहा कि कोलकाता से लिवरपूल तक हम न्याय और महिलाओं की सुरक्षा के लिए खड़े रहेंगे। प्रेट्र

67 जिलों में कुल 1,174 परीक्षा केंद्रों में हुई उप्र पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर भर्ती की लिखित परीक्षा। परीक्षा 6,48,435 अभ्यर्थियों ने ही दी।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 24 अगस्त, 2024

पाकिस्तान में गिरा भारतीय सेना का मिनी ड्रोन

पाक सेना ने यूएवी को कब्जाया, सेना ने वापस मांगा

2022 में दुर्घटनावश फायरिंग के बाद ब्रह्मोस मिसाइल सीमा पार चली गई थी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

भारत-पाकिस्तान सीमा पर शुक्रवार को एक अप्रत्याशित घटना में भारतीय सेना का एक मिनी ड्रोन पाकिस्तान सीमा के पार उड़ता चला गया। भारतीय सेना का एक छोटा ड्रोन जिसे मानवरहित विमान (यूएवी) भी कहते हैं, तकनीकी खराबी के कारण दिशा बदलकर पाकिस्तान के निकियाल सेक्टर में चला गया। पाकिस्तानी सैनिकों ने अपने इलाके में गिरे इस भारतीय यूएवी को अपने कब्जे में ले लिया। तकनीकी गड़बड़ी से यूएवी के गैर इरादतन सीमा पार करने की घटना की भारत ने तत्काल हाटलाइन पर पाकिस्तान को सूचना देते हुए इसे वापस लौटाने को कहा है। लेकिन अभी तक पाकिस्तानी सेना ने यूएवी लौटाने का कोई संकेत नहीं दिया है।

भारत-पाकिस्तान सीमा पर तनावपूर्ण रिश्तों के बीच भारतीय सैन्य उपकरण के दुर्घटनावश सीमा पार जाने की इस घटना पर सेना की ओर जारी एक बयान में कहा गया, 'शुक्रवार सुबह 9 बजकर 25 मिनट पर भारतीय क्षेत्र में प्रशिक्षण मिशन के दौरान एक मिनी यूएवी तकनीकी खराबी के कारण नियंत्रण खो बैठा और भारत के भिंबर गली सेक्टर के सामने स्थित पाकिस्तान के निकियाल सेक्टर में चला गया।

पाकिस्तानी सेना के कब्जे में भारतीय सेना का यूएवी। सौ : इंटरनेट मीडिया

मीडिया इनपुट के अनुसार पाकिस्तानी सैनिकों ने इस यूएवी को अपने कब्जे में कर लिया है। भारतीय सेना की ओर से इस यूएवी को वापस लेने के लिए पाकिस्तानी सेना को हाटलाइन संदेश भेजा गया है।' एलओसी के आसपास के क्षेत्रों में सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ पर नजर रखने व अन्य प्रशिक्षण के लिए यूएवी उड़ते जाते हैं। हालांकि यूएवी के पाकिस्तानी इलाके में जाकर गिरने की इस घटना से पहले मार्च, 2022 में भी ब्रह्मोस मिसाइल से एक दुर्घटना हुई थी। तब अचानक एक मिसाइल फायर होकर पाकिस्तान की सीमा के करीब 125 किमी अंदर जाकर गिरी थी। हालांकि इसमें किसी तरह के जान-माल का नुकसान नहीं हुआ था। मगर पाकिस्तान ने इस पर विरोध जताते हुए इस घटना की संयुक्त जांच की मांग की थी। भारत ने संयुक्त जांच की मांग तो ठुकरा दी मगर रक्षा मंत्रालय ने इसकी उच्चस्तरीय जांच कराई और फिर इसमें दोषी पाए गए अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया था।

सैन्यी गतिविधियां भांपने के लिए घुसपैठिये ने की एलओसी पार

जागरण संवाददाता, पुंछ

- गुलाम जम्मू-कश्मीर का रहने वाला है घुसपैठिया जाहिर हुसैन
- सेना ने पूछताछ कर पुलिस को सौंपा, कई राज उगले हैं उसने

पुंछ जिले के गुलपुर सेक्टर से गुरुवार को घुसपैठ कर भारतीय क्षेत्र में पहुंचे सैयद जाहिर हुसैन शाह को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने भारतीय सेना की गतिविधियां भांपने के लिए नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास भेजा था। भारतीय सेना के जवानों की जानकारी जुटाने के लिए वह भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कर आया था, लेकिन उसे पकड़ लिया गया था। जाहिर हुसैन गुलाम जम्मू-कश्मीर का रहने वाला है। सेना ने शुक्रवार को उसे पुलिस को सौंप दिया।

सेना की पूछताछ में जाहिर हुसैन ने कई पर्दाफाश किए हैं, जिसमें पाकिस्तान की नापाक हरकत सामने आई है। सूत्रों ने बताया कि घुसपैठिये ने स्वीकारा है कि उसे पाकिस्तान की तरफ से भेजा गया था। उससे कहा गया था कि वह नियंत्रण रेखा के नजदीक भारतीय सेना की गतिविधियों की जानकारी इकट्ठा करे। उसने भारतीय सेना की तैनाती, नियंत्रण रेखा पर तारबंदी सहित कई जानकारियां हासिल करने की कोशिश की। उसने बताया कि पाकिस्तानी एजेंसियों के कहने पर वह पहले भी जानकारी लेने के लिए नियंत्रण रेखा पर आता रहा है। बता दें कि गुरुवार दोपहर को पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर स्थित गुलपुर सेक्टर में नियंत्रण रेखा के अग्रिम क्षेत्र में सरला पोस्ट पर तैनात जवानों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में कुछ संदिग्ध हरकत देखी थी। जैसे ही घुसपैठिया भारतीय क्षेत्र में घुसा तो जवानों ने उसे पकड़ लिया था।

पुंछ के गुलपुर सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर पकड़ा गया घुसपैठिया। सौजन्य : सेना

जाहिर हुसैन ने पूछताछ में बताया है कि पाकिस्तानी एजेंसियों के कहने पर उसे पहले भी जानकारी इकट्ठा करने के लिए नियंत्रण रेखा पर भेजा जाता रहा है, लेकिन तब वह पाकिस्तानी सीमा में रहकर ही सेना की गतिविधियों की जानकारी लेकर वापस लौटता रहा है।

निर्माणाधीन रिजार्ट के काटेज की छत गिरी, दबने से पांच की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर

- मप्र में इंदौर जिले का मामला, रिजार्ट के तीन मालिकों और मैनेजर पर केस
- गुणवत्ताहीन पाया गया निमार्ण कार्य, पीडब्ल्यूडी करेगा हादसे की जांच

मध्य प्रदेश में इंदौर जिले के चोरल गांव में गुरुवार रात निर्माणाधीन रिजार्ट के काटेज में सो रहे ठेकेदार और मजदूरों पर छत गिर गई। हादसे में पांच लोगों की मलबे में दबने से मौत हो गई। शुक्रवार सुबह कई घंटे चले बचाव कार्य के बाद शव मलबे से निकाले गए। प्रशासन की जांच में निर्माण कार्य गुणवत्ताहीन पाया गया है। इस पर पुलिस ने रिजार्ट के तीन मालिक और मैनेजर के खिलाफ एफआइआर दर्ज की है। प्रशासन ने हादसे की जांच पीडब्ल्यूडी को दी है।

चोरल रिवर रिजार्ट का निर्माण चार हजार वर्ग मीटर जमीन पर किया जा रहा था। इसमें छह अलग-अलग काटेज और एक अलग स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा था। इसी की एक काटेज में बुधवार को छत डाली गई थी। गुरुवार रात को ठेकेदार पवन पांचाल, वेल्डर हरिओम मालवी, हेल्पर अजय मालवी, राजा जेटलिआ उर्फ शैलेंद्र सिंह और जुड़ाई का काम करने वाला गोपाल प्रजापति खाना खाकर काटेज में सो गए। इन सभी पर देर रात पूरी छत गिर गई और उसके मलबे में सभी दब गए। सुबह साढ़े छह बजे चौकीदार विनोद यादव ने देखा तो पुलिस-प्रशासन को सूचना दी। अधिकारी पहुंचे और पोकलेन मशीनें बुलाकर मलबे को हटवाकर सभी शव निकालवाए।

> रिजार्ट मालिकों के पास निर्माण के लिए वन विभाग और पंचायत से जुड़ी सभी तरह की अनुमति पाई गई हैं, लेकिन प्रारंभिक तकनीकी जांच में निर्माण कार्य गुणवत्ताहीन पाया गया। इसके लिए रिजार्ट मालिक डा. विकास डब्करा, अनाया डेम्बला, विहाना डेम्बला और रिजार्ट मैनेजर राहुल अहिरवार के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई है।
>
> -हितिका वासल, एसपी (ग्रामीण), इंदौर

यात्रियों की चीख-पुकार के बीच शुरू हआ राहत व बचाव का कार्य

बस के गिरने के बाद घायल को बाहर लाते बचावकर्मी। रायटर

बस की फिटनेस 2026 तक है : नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त बस (यूपी 53 एफटी 7623) धर्मशाला निवासी सौरभ केसरवानी की पत्नी शालिनी केसरवानी के नाम से है। यह बस दिसंबर 2019 में खरीदी गई थी। फिटनेस 2026 और बीमा 31 मार्च 2025 तक वैध है।

प्रथम पृष्ठ से आगे

यात्रियों की चीख-पुकार के बीच स्थानीय लोगों ने राहत और बचाव का कार्य शुरू किया। इसके बाद नेपाल पुलिस और प्रहरी दल के जवान देर शाम तक राहत-बचाव कार्य में जुटे थे। समाचार एजेंसी प्रेट्र के अनुसार, सशस्त्र पुलिस बल के प्रवक्ता शैलेंद्र थापा ने बताया कि 16 यात्रियों की तो घटनास्थल पर मौत हो गई थी, जबकि 11 लोगों ने उपचार के दौरान दम तोड़ा। 15 लोगों को घायल अवस्था में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त बस से निकाला गया, इनमें 12 को नेपाल सेना के एमआइ हेलीकाप्टर से काठमांडू उपचार के लिए भेजा गया है। एक यात्री का पता नहीं चला है। नेपाल में स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारी घटना पर नजर बनाए हुए हैं।

नेपाल में रुकना था आठ दिन : महाराष्ट्र से 110 लोगों का जत्था जलगांव जिले के ग्राम भुसाल से उत्तर भारत व नेपाल की तीर्थ यात्रा और पर्यटन के लिए रवाना हुआ था। ग्रुप लीडर चारू बांडे ने गोरखपुर के केसरवानी परिवहन की तीन बसें बुक कराई थीं। यात्रा की शुरुआत 17 अगस्त को प्रयागराज से हुई थी। तीनों बसें 16 अगस्त को गोरखपुर से रवाना हुई थीं। नेपाल में इन लोगों का आठ दिन रुकने का कार्यक्रम था। इसके लिए यात्रा भंसार (परमिट) बनवाया गया था। शुक्रवार सुबह साढ़े सात बजे तीनों बसें नेपाल के पोखरा से काठमांडू के लिए रवाना हुईं। महराजगंज के जिलाधिकारी अनुनय झा ने बताया कि राहत व बचाव के लिए महराजगंज से अधिकारियों को भेजा गया है। सीमा पर छह एंबुलेंस लगाई गई हैं।

पीड़ितों को वापस लाने का प्रयास जारी : फडणवीस: प्रेट्र के मुताबिक महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बस में सवार यात्री महाराष्ट्र में जालगांव जिले के थे। पीड़ितों को वापस लाने के प्रयास जारी हैं।

न्यूज गैलरी

'एक छत के नीचे अलग कमरे में सोना पति के साथ क्रूरता'

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पत्नी के अलग कमरे में सोने को क्रूरता मानते हुए पति को विवाह विच्छेद की अनुमति दी है। तलाक की याचिका को स्वीकार करते हुए जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस संजय कुमार जायसवाल की डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में लिखा है कि एक ही छत के नीचे साथ रहने के बावजूद बिना किसी पर्याप्त कारण के पत्नी द्वारा घर के अलग कमरे में सोना पति के प्रति मानसिक क्रूरता है। बेंच ने बेमेतरा के फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। बेमेतरा के फैमिली कोर्ट ने नवंबर 2022 में पति के तर्कों से सहमत होते हुए उसके पक्ष में तलाक की डिक्री मंजूर की थी। (नईदुनिया)

16 लाख के इनामी दो नक्सलियों का आत्मसमर्पण

सुकमा: सुकमा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शुक्रवार को आठ-आठ लाख के दो इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। दोनों वर्ष 2021 में बीजापुर के टेकलगुड़ा नक्सल वारदात में शामिल थे। टेकलगुड़ा में नक्सलियों के हमले में सुरक्षा बल के 22 जवान बलिदान हुए थे। पुलिस के मुताबिक आत्मसमर्पण करने वालों में मड़कम मुया व मड़कम सन्ना शामिल है। दोनों पीएलजीए बटालियन नंबर एक से जुड़े हुए थे। कई साल से नक्सल संगठन में सक्रिय रूप से काम कर रहे थे। (नईदुनिया)

सोनिया का अनूठा अंदाज

नई दिल्ली में शुक्रवार को कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी का एक नया रूप देखने को मिला। वह अपने पालतू कुत्ते के साथ बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आईं। पालतू जानवर से उनके अनूठे लगाव का यह चित्र कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने एक्स हैंडल पर साझा किया। एएनआइ

कड़ी सुरक्षा के बीच 32.45 % अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा

उप्र सिपाही भर्ती परीक्षा

राज्य ब्यूरो, जागरण • लखनऊ

- कड़े सुरक्षा प्रबंधों और एआइ से निगरानी का दिखा असर
- दोनों पालियों में 61 संदिग्ध अभ्यर्थी आए सामने, भर्ती बोर्ड ने दस्तावेज लेकर देने दी परीक्षा

उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा में कोई भी गड़बड़ी न होने देने के पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड के प्रयास अंततः सफल रहे। शुक्रवार को भर्ती परीक्षा के पहले दिन कहीं से पेपर लीक होने की कोई सूचना नहीं आई। परीक्षा में कड़े सुरक्षा प्रबंधों और आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस (एआइ) से निगरानी का परिणाम यह रहा कि पहले दिन ही 32.45 प्रतिशत अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। इनमें 20.88 प्रतिशत तो ऐसे थे, जिन्होंने प्रवेश-पत्र डाउनलोड करने के बाद भी परीक्षा नहीं दी। परीक्षा में सेंधमारी का प्रयास करने के आरोप में पांच अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें गोरखपुर में दो, आगरा, महाराज व रायबरेली से एक-एक आरोपित पकड़े गए। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष राजीव कृष्ण के अनुसार सभी जिलों में शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा हुई है। दोनों पालियों में 61 संदिग्ध अभ्यर्थी भी सामने आए, जिनके फिंगरप्रिंट तथा आवेदनपत्र में भरे गए अन्य ब्योरे आधार कार्ड से मैच नहीं हुए। इन सभी से उनके पहचान पत्र व स्वप्रमाणित पत्र लेकर परीक्षा में शामिल कराया गया है।

> **संदिग्ध क्यों हैं अभ्यर्थी**
>
> भर्ती बोर्ड ने एआइ के माध्यम से सभी अभ्यर्थियों की पड़ताल की है। लगभग 20,500 अभ्यर्थियों के आधार कार्ड व आवेदन पत्र में दी गई जानकारियों में भिन्नता है। ऐसे अभ्यर्थी संदेह के घेरे में हैं।

प्रयागराज में एक परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों की जांच करते पुलिसकर्मी। एएनआइ

उप्र पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर भर्ती की लिखित परीक्षा 67 जिलों में कुल 1,174 परीक्षा केंद्रों में हुई। परीक्षा के पहले दिन दोनों पालियों में लगभग 9,60,000 लाख अभ्यर्थियों को शामिल होना था। इनमें 8,19,600 ने प्रवेश-पत्र डाउनलोड किए थे, किंतु परीक्षा 6,48,435 अभ्यर्थियों ने ही दी। सिपाही भर्ती की परीक्षा पूर्व में 18 व 19 फरवरी को हुई थी, जिसका पेपर लीक हो गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उक्त परीक्षा निरस्त कर इसे पुनः आयोजित कराया जा रहा है। परीक्षा का निरीक्षण करने डीजीपी प्रशांत कुमार भी निकले। डीजीपी ने कहा कि शुचितापूर्ण व नकलविहीन परीक्षा संपन्न कराने के लिए कड़े सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित कराए गए हैं। कुछ संदिग्ध पकड़े गए हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। सिपाही भर्ती परीक्षा आगे 24, 25, 30 व 31 अगस्त को भी दो-दो पालियों में होगी। परीक्षा में कुल 48,17,441 अभ्यर्थियों को हिस्सा लेना है। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष राजीव कृष्ण के अनुसार बोर्ड की मंशा किसी छोटी त्रुटि के चलते अभ्यर्थी को परीक्षा से वंचित करने की नहीं है। इसलिए सभी संदिग्ध अभ्यर्थियों के दस्तावेज की सघन जांच के बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी।

काम हलवाई का, कर रहा था नशीली दवाओं का कारोबार

जागरण संवाददाता, सोलन

- नशीली दवा तस्करी मामले में आरोपित का खाता किया फ्रीज,
- तीन आरोपित गिरफ्तार, उत्तर प्रदेश से हिमाचल आ रही थीं दवाएं

हिमाचल के सोलन जिले में पुलिस ने नशीली दवाओं की तस्करी के आरोपित के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। इन खातों में 22 लाख रुपये थे। नालागढ़ में हलवाई की दुकान चलाने वाले आरोपित की अन्य संपत्तियों की जानकारी भी जुटाई जा रही है। पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपित ने एक ही वर्ष में 10 लाख रुपये की एफडी करवाई है। पुलिस ने पूरे नेटवर्क का रहस्योद्घाटन किया है। गुजरात में निर्मित दवाओं को उत्तर प्रदेश से हिमाचल पहुंचाया जा रहा था। इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

जांच में पाया गया है कि गुजरात की कंपनी आरपीजी लाइफ साइंस में उत्पादित दवाएं उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों को भेजी जाती हैं। इसी बीच कुछ ड्रग तस्कर दवाओं को ब्लैक कर लेते हैं। पुलिस ने इसी वर्ष 18 मार्च को सुरेश कुमार निवासी सोलन को उसके वाहन के साथ पकड़ा था। वाहन से लोमोटिल नामक प्रतिबंधित दवा की 28,140 गोलियां मिली थीं। पूछताछ में आरोपित ने बताया कि वह दवाएं वीर चंद निवासी नालागढ़ को देने जा रहा था। वीर चंद को भी गिरफ्तार कर पूछताछ की तो पता चला कि महावीर निवासी गांव नगला चुचाना, तहसील व जिला आगरा (उत्तर प्रदेश) से उन्होंने यह स्टाक मंगवाया था। पुलिस ने पूछताछ के उपरांत उसे भी गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस ने अब इस मामले में मुख्य आरोपित नालागढ़ निवासी वीर चंद के बैंक खातों की जांच की है। पता चला है कि उसने इन दवाओं की डील सुरेश कुमार से की थी। 15 मार्च को 27,000 रुपये आनलाइन ट्रांसफर किए थे।

घुसपैठियों की जांच के नाम पर की गई खानापूर्ति

गणेश पांडेय • जागरण

- झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान को लेकर हाई कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग तक गंभीर
- दस्तावेज की गहन जांच के बजाय वोटर कार्ड-आधार का मिलान कर तीन दिनों में जांच बंद

पाकुड़ : झारखंड में बंगाल से सटे संताल परगना इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान को लेकर हाई कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग तक गंभीर है, लेकिन जांच के नाम पर प्रशासन खानापूरी कर रहा है। घुसपैठ की आशंका वाले इलाकों में मतदाताओं की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि को लेकर पिछले दिनों चुनाव आयोग से शिकायत की गई थी। आयोग के निर्देश के बाद पाकुड़ में मतदाता सूची के सत्यापन का काम हुआ, लेकिन इसकी जांच रिपोर्ट चौंकाने वाली है। प्रशासन की रिपोर्ट में कहा गया है कि मतदाताओं की संख्या में वृद्धि घुसपैठ के कारण नहीं हुई है, बल्कि मुस्लिम आबादी के जागरूक होने के बाद मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के कारण हुई है। खास बात यह है कि पाकुड़ जिला प्रशासन की टीम ने दस्तावेजों की गहन जांच के बजाय सैंपल के तौर पर वोटर कार्ड व आधार से कुछ वोटरों के विवरण का मिलान कर महज तीन दिनों में जांच बंद कर दी। यह हाल तब है जब पाकुड़ और साहिबगंज समेत संताल परगना प्रमंडल के सभी जिलों में बड़े पैमाने पर फर्जी आधार कार्ड और जन्म प्रमाणपत्र बनाने के मामले सामने आते रहे हैं। घुसपैठिए यहां की आदिवासी महिलाओं से विवाह कर और अन्य तरीके अपना कर जमीन पर कब्जा कर बस जाते हैं। इसके बाद घुसपैठिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, जनम प्रमाणपत्र समेत तमाम ऐसे दस्तावेज बनवा लेते हैं, जो उनकी स्थानीय नागरिकता का प्रमाण बन जाते हैं।

> **263** मतदान केंद्रों में सिर्फ नौ मतदान केंद्रों पर ही बढ़े वोटरों की कराई गई जांच

मतदाताओं की संख्या में 65 प्रतिशत तक वृद्धि : वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, पाकुड़ जिले की जनसंख्या वृद्धि दर 28 प्रतिशत है, लेकिन मुस्लिम बहुल इलाके के मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या में करीब 65 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। पाकुड़-महेशपुर विधानसभा क्षेत्र के 263 मतदान केंद्रों में सिर्फ नौ मतदान केंद्रों पर बढ़े वोटरों की जांच कराई गई है। ऐसे में प्रशासन की सैंपल जांच रिपोर्ट में यह बताना कि मुस्लिम क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि में कुछ भी गलत नहीं, कई सवाल खड़े कर रहा है। जांच दल की रिपोर्ट में मतदाताओं की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि के जो कारण बताए गए हैं, वह अल्पसंख्यक बहुल दूसरे जिलों में क्यों लागू नहीं हो रहा, यही भी एक अहम सवाल है। भाजपा ने पूछा है कि क्या निर्वाचन आयोग के जागरूकता कार्यक्रमों का असर सिर्फ पाकुड़ जिले के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों पर ही पड़ा।

पाकुड़ विधानसभा के 208 एवं महेशपुर विस के 55 मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि की शिकायत चुनाव आयोग से भाजपा ने की थी। निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी ने जांच टीम गठित कर तीन दिन में वोटरों की वृद्धि के कारणों की जांच करने का निर्देश दिया था।

रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय लखनऊ से नई दिल्ली स्थानांतरित

नई दिल्ली, प्रेट्र : नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मुख्य रेलवे सुरक्षा आयुक्त के कार्यालय को लखनऊ से नई दिल्ली स्थानांतरित कर दिया है। उप रेलवे सुरक्षा आयुक्त द्वारा हस्ताक्षरित 22 अगस्त के ज्ञापन में कहा गया है कि रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय यानि मुख्य रेलवे सुरक्षा आयुक्त का कार्यालय नई दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक, यह निर्णय विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों के साथ बेहतर और कुशल समन्वय के लिए लिया गया है। रेलवे सुरक्षा आयोग रेल यात्रा सुरक्षा, वैधानिक निरीक्षण, जांच और सलाहकार कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। सीआरएस की वेबसाइट के अनुसार, रेलवे निरीक्षणालय को रेलवे बोर्ड से अलग करने के सिद्धांत को 1940 में केंद्रीय विधानमंडल द्वारा समर्थन दिया गया था, जिन्होंने सिफारिश की थी कि रेलवे के वरिष्ठ सरकारी निरीक्षकों को रेलवे बोर्ड के अलावा भारत सरकार के किसी प्राधिकरण के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा जाना चाहिए।

योग माता केवलानंद पायलट बाबा की उत्तराधिकारी

सर्वसम्मति

> पायलट बाबा के कनखल स्थित आश्रम में जूना अखाड़ा के अंतरराष्ट्रीय संरक्षक श्रीमहंत हरि गिरि ने की घोषणा, पायलट बाबा की शिष्य महामंडलेश्वर साध्वी चेतनानंद गिरि व साध्वी श्रद्धा गिरि होंगी आश्रम ट्रस्ट की महामंत्री

जागरण संवाददाता, हरिद्वार

श्रीपंच दशनाम जूना अखाड़े के ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर महायोगी पायलट बाबा की शिष्य योग माता केवलानंद (केको आइकावा) उनकी उत्तराधिकारी होंगी। जूना अखाड़ा के अंतरराष्ट्रीय संरक्षक श्रीमहंत हरि गिरि ने शुक्रवार को पायलट बाबा के कनखल स्थित आश्रम में अखाड़े और आश्रम के श्रीमहंत, महंत और महामंडलेश्वरों के मध्य यह घोषणा की। उन्होंने सर्वसम्मति से पायलट बाबा की शिष्य महामंडलेश्वर योगमाता केवलानंद को आश्रम ट्रस्ट का अध्यक्ष घोषित किया, जबकि महामंडलेश्वर साध्वी चेतनानंद गिरि व साध्वी श्रद्धा गिरि ट्रस्ट की महामंत्री होंगी।

जूना अखाड़ा के अंतरराष्ट्रीय संरक्षक श्रीमहंत हरि गिरि ने बताया कि उत्तराधिकारी घोषित होने के बाद केको आइकावा को केवलानंद नाम दिया गया है। इससे पहले उन्हें कोकिला माता के नाम से जाना जाता था। उन्होंने कहा कि महामंडलेश्वर योग माता केवलानंद विद्वान संत हैं। अखाड़े को विश्वास है कि वह अपने गुरु पायलट बाबा के कार्यों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएंगी। जूना अखाड़े के अध्यक्ष श्रीमहंत प्रेम गिरि ने कहा कि पायलट बाबा की तीनों शिष्य उनकी योग शिक्षा को आगे बढ़ाएंगी। आवाह्न अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अरुण गिरि ने उम्मीद जताई कि आश्रम की नवनियुक्त अध्यक्ष और उनकी दोनों सहयोगी सनातन धर्म संस्कृति के प्रचार-प्रसार में अहम योगदान देंगी। महामंडलेश्वर योगमाता केवलानंद ने सभी का आभार जताते हुए कहा कि गुरु के कार्यों को पूरा करना ही उनके जीवन का ध्येय है। महामंत्री साध्वी चेतनानंद गिरि व साध्वी श्रद्धा गिरि ने कहा कि गुरु की शिक्षाएं उन्हें सदैव प्रेरणा देती रहेंगी।

हरिद्वार के पायलट बाबा आश्रम में शुक्रवार को ब्रह्मलीन पायलट बाबा की घोषित उत्तराधिकारी योगमाता केवलानंद (केको आइकावा) (मध्य में) पायलट बाबा आश्रम ट्रस्ट की अध्यक्ष बनी। ट्रस्ट की महामंत्री साध्वी चेतनानंद गिरि (दाएं) व साध्वी श्रद्धा गिरि (बाएं) को बनाया गया। इस अवसर पर जूना अखाड़ा के अंतरराष्ट्रीय संरक्षक श्रीमहंत हरि गिरि व अन्य संत उपस्थित रहे। जागरण

युवतियों को एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनने का मिल सकता है मौका

कोच्चि, प्रेट्र : 11 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के हिस्से के रूप में ब्रिटिश उच्चायोग 18 से 23 वर्ष की भारतीय महिलाओं को एक दिन के लिए ब्रिटेन के शीर्ष राजनयिकों में से एक बनने का अवसर प्रदान करेगा। ब्रिटिश उच्चायोग ने शुक्रवार को कहा कि एक दिन के लिए उच्चायुक्त प्रतियोगिता भारत की प्रतिभाशाली युवा महिलाओं को वैश्विक मंच पर अपनी ताकत और नेतृत्व क्षमता दिखाने के लिए आमंत्रित करती है।

इसमें भाग लेने को इस सवाल का जवाब देते हुए एक मिनट का वीडियो बनाना होगा कि ब्रिटेन व भारत भविष्य की पीढ़ियों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रौद्योगिकी पर कैसे सहयोग कर सकते हैं। प्रतिभागियों को वीडियो एक्स, इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पर @UKinIndia टैग करते हुए साझा करना होगा।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रोबोटिक्स व एआइ पढ़ेंगे सरकारी स्कूलों के छात्र

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया • रायपुर

- छत्तीसगढ़ में 800 स्कूलों में पहले चरण में होगा विद्यार्थियों का कौशल विकास

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर के कांकेर और कोंडागांव में स्कूली बच्चों को अब रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआइ) पढ़ाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक, राज्य के सरकारी स्कूलों में कौशल शिक्षा के विकास के लिए एकीकृत पाठ्यक्रम चलाने की योजना है। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के साथ अनुबंध किया है। इसके अंतर्गत पहले दो शैक्षणिक वर्षों में 800 स्कूलों में कौशल शिक्षा लागू की जाएगी। इस अवधि के दौरान 1,600 शिक्षक, कक्षा छठवीं से 10वीं तक के 40 हजार छात्र-छात्राओं को कौशल और जीवन कौशल की शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। कार्यक्रम शुरू में कांकेर और कोंडागांव में शुरू होगा। बाद में राज्य के सभी 33 जिलों में विस्तार किया जाएगा। मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के सीईओ जयंत रस्तोगी ने बताया कि आदिवासी बच्चों को उनकी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने और शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार के लिए प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में प्रदान की जाएगी। उनकी मातृभाषा जानने वाले स्थानीय शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी ने बताया कि पाठ्यक्रम रचनात्मक और रोजगारोन्मुखी होंगे, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि 12वीं कक्षा के बाद स्कूल से निकलने वाले छात्रों रोजगार के बेहतर अवसर मिले और वे समसामयिक जरूरतों के अनुरूप खुद को ढाल सकें।

****

40 करोड़ रुपये जारी करने को मंजूरी दी है केंद्र ने बाढ़ प्रभावित त्रिपुरा के लिए। राज्य सरकार ने भी मृतकों के परिवारों के लिए 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है।

एससी-एसटी एक्ट तभी लागू होगा जब अपमानित करने की मंशा हो : सुप्रीम कोर्ट

व्यवस्था ▶ जाति के आधार पर अपमानित करने पर ही लगेगा एसी-एसटी एक्ट

जानबूझकर किए प्रत्येक अपमान में जाति-आधारित भावना नहीं होती

▶ कहा-जानबूझकर किया गया अपमान या धमकी का परिणाम जाति-आधारित अपमान की भावना नहीं

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि एससी-एसटी एक्ट के तहत अपराध केवल इस आधार पर स्थापित नहीं होता कि शिकायतकर्ता अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदाय का सदस्य है, जब तक कि उसे अपमानित करने का इरादा न हो।

जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने यह टिप्पणी यू-ट्यूबर शाजन स्कारिया को अग्रिम जमानत प्रदान करते हुए की जो 'मरुनंदन मलयाली' नामक चैनल संचालित करते हैं। स्कारिया ने केरल हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उसने विधायक पीवी श्रीनिजिन द्वारा दर्ज कराए गए आपराधिक मामले में अग्रिम जमानत देने से इन्कार कर दिया था। श्रीनिजिन ने स्कारिया के विरुद्ध एससी-एसटी (अत्याचारों की रोकथाम) अधिनियम, 1989 के तहत एफआइआर दर्ज कराई थी। इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि स्कारिया ने अपने चैनल पर अपलोड वीडियो के जरिये उन पर झूठे आरोप लगाकर जानबूझकर अपमानित किया।

शीर्ष अदालत ने कहा कि सिर्फ इस तथ्य के आधार पर एससी-एसटी एक्ट की धारा-3(1)(आर) लागू नहीं होती कि अपमानित होने या धमकी पाने वाले व्यक्ति एससी या एसटी से ताल्लुक रखता है, जब तक कि आरोपित व्यक्ति का इरादा संबंधित व्यक्ति को जाति के आधार पर अपमानित करने का न हो या संबंधित व्यक्ति के एससी-एसटी समुदाय से ताल्लुक रखने के कारण अपमानित करने का न हो। दूसरे शब्दों में, 1989 के इस अधिनियम का तात्पर्य यह नहीं है कि गैर एससी-एसटी समुदाय के किसी व्यक्ति द्वारा एससी या एसटी से संबंधित किसी व्यक्ति का जानबूझकर किया गया अपमान या धमकी का प्रत्येक कार्य इस अधिनियम की धारा 3(1)(आर) के अंतर्गत आएगा, वह भी सिर्फ इसलिए कि यह किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किया गया है जो एससी या एसटी का है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि किसी एससी या एसटी व्यक्ति का जानबूझकर किया गया प्रत्येक अपमान या उसे दी गई धमकी का परिणाम जाति-आधारित अपमान की भावना नहीं होती।

पीठ ने कहा, 'केवल उन मामलों को 1989 के अधिनियम के मुताबिक अपमान या धमकी कहा जा सकता है जहां जानबूझकर अपमान या धमकी या तो अस्पृश्यता की प्रचलित प्रथा के कारण हो या ऐतिहासिक रूप से स्थापित विचारों जैसे उच्च जातियों की निम्न जातियों या अछूतों पर श्रेष्ठता, पवित्रता और अपवित्रता आदि की धारणाओं को मजबूत करने के लिए हो।'

मामले का उल्लेख करते हुए पीठ ने कहा कि निंदनीय आचरण और अपमानजनक बयानों की प्रकृति को देखते हुए स्कारिया के बारे में प्रथमदृष्टया कहा जा सकता है कि उन्होंने आइपीसी की धारा-500 के तहत दंडनीय मानहानि का अपराध किया है। पीठ ने कहा, "शिकायतकर्ता केवल इस आधार पर 1989 के अधिनियम के प्रविधानों का हवाला नहीं दे सकता कि वह एससी समुदाय का सदस्य है। खासकर तब, जबकि वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट और शिकायत पहली नजर में संयुक्त रूप से पढ़ने पर यह पता नहीं चलता कि अपीलकर्ता की हरकतें शिकायतकर्ता की जातिगत पहचान से प्रेरित थीं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिससे संकेत मिले कि स्कारिया ने यूट्यूब पर वीडियो जारी करके एससी या एसटी के विरुद्ध शत्रुता, घृणा या दुर्भावना की भावनाओं को बढ़ावा दिया या इसका प्रयास किया।' पीठ ने कहा, "वीडियो का एससी या एसटी के लोगों से कोई लेनादेना नहीं है। उनका निशाना सिर्फ शिकायतकर्ता था। धारा-3(1)(यू) तभी लागू होगी जब कोई व्यक्ति एससी या एसटी के सदस्यों के विरुद्ध समूह के रूप में दुर्भावना या शत्रुता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा हो, न कि व्यक्तिगत रूप से।"

सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने मणिपुर में की सुरक्षा की समीक्षा

उपेंद्र द्विवेदी। फाइल

इंफाल, आइएएनएस : सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी शुक्रवार को अपने दो दिवसीय दौरे पर मणिपुर पहुंचे। यहां उन्होंने सुरक्षा स्थितियों की समीक्षा की। सेना प्रमुख बनने के बाद जनरल द्विवेदी का यह इस पूर्वोत्तर राज्य में पहला दौरा है। इंफाल पहुंचते ही सेना प्रमुख द्विवेदी ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह से मुलाकात की है।

उन्होंने मुख्यमंत्री सिंह से बातचीत में आंतरिक सुरक्षा की स्थितियों पर चर्चा की और मणिपुर में शीघ्र शांति और स्थिरता की बहाली में सेना व असम राइफल्स की भूमिका की भी समीक्षा की। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आश्वासन दिया कि भारतीय सेना मणिपुर के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरी तरह निभाएगी। जनरल द्विवेदी ने सैन्य बलों और पूर्व सैनिकों से भी बात की और उनके योगदान को सराहा। मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह ने बाद में एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी के साथ उनकी बहुत लाभकारी बैठक हुई है।

पाकिस्तानी हैंडलरों के निर्देश पर डाक्टर तैयार कर रहा था आतंकी

राकेश कुमार सिंह ● जागरण

▶ रांची में मदरसा चलाने वाले मुफ्ती रहमतुल्ला के पास थी भर्ती की जिम्मेदारी

▶ डा. इश्तियाक देश में सीरियल बम धमाके करने की रच रहा था षड्यंत्र

नई दिल्ली : राजस्थान और झारखंड से गिरफ्तार किए गए अलकायदा के इंडियन सब कांटिनेंट (एक्यूआइएस) माड्यूल के 11 आतंकियों से पूछताछ सामने आया है कि इसका प्रमुख रांची का रेडियोलाजिस्ट डा. इश्तियाक अहमद डेढ़ वर्ष से संगठन खड़ा करने में जुटा था। इसके लिए उसे पाकिस्तान से भी मदद मिल रही थी। वह कुछ पाकिस्तानी हैंडलरों से सीधे संपर्क में था और उनके निर्देश पर माड्यूल को मजबूत कर रहा था। यह भी सामने आया है कि डा. इश्तियाक देश में सीरियल बम धमाके करने की साजिश रच रहा था। इसके लिए वह नेटवर्क बढ़ा रहा था।

सूत्रों के मुताबिक, आतंकी माड्यूल में मुस्लिम युवाओं को भर्ती करने की जिम्मेदारी डा. इश्तियाक ने अपने विश्वासपात्र मुफ्ती रहमतुल्ला मजाहिरी को दी थी। रहमतुल्ला रांची में मदरसा चलाता था और इश्तियाक उससे मिलने के लिए वहां अक्सर जाता था। इश्तियाक ने उसे निर्देश दिया था कि वह विभिन्न राज्यों का दौरा करे और वहां मदरसों में पढ़ने वाले गरीब परिवारों के मुस्लिम युवाओं को चिह्नित करे। तकरीरों के जरिये उनका ब्रेनवाश कर आतंकी माड्यूल के लिए भर्ती करे। इसमें आने वाला सारा खर्च उठाने का भरोसा भी डा. इश्तियाक ने रहमतुल्ला को दिया था। डा. इश्तियाक खुद भी रेडियोलाजी सेंटरों से होने वाली आमदनी के साथ ही चंदे के रूप में मिलने वाली सारी रकम आतंकी माड्यूल को स्थापित करने में ही लगा रहा था।

छह आतंकी 10 दिन के रिमांड पर: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बताया कि राजस्थान के भिवाड़ी में पहाड़ी क्षेत्र से गिरफ्तार आतंकियों हसन अंसारी, इनामुल अंसारी, अरशद खान, शाहबाज अंसारी और अल्ताफ अंसारी को गुरुवार की रात ही पटियाला हाउस कोर्ट में पेश कर 10 दिन के रिमांड पर लिया गया है। इनमें से अल्ताफ और बाकी रांची से हैं। इसके अलावा झारखंड के कई जिलों से गिरफ्तार आतंकी मुफ्ती रहमतुल्ला मजाहिरी, मोहम्मद मोदब्बीर, मोहम्मद रिजवान, मतिउर रहमान और डा. इश्तियाक अहमद को रांची के कोर्ट में पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लाया जा रहा है। इनके साथ ही गिरफ्तार फैजान अहमद को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश कर 10 दिन के रिमांड पर लिया गया है। पकड़े जाने से बचने के लिए ये सभी अलग-अलग एप के जरिये आपस में बात करते थे। इनमें कुछ ड्राइवर और मैकेनिक हैं। आइबी ने पिछले साल ही स्पेशल सेल को इस आतंकी माड्यूल के बारे में इनपुट दे दिया था।

वर्ष 2013 के पटना बम धमाकों में डा. इश्तियाक और डा. एजाज को हिरासत में लिया गया था: स्पेशल सेल ने बताया कि डा. इश्तियाक और उसके करीबी अलीगढ़ के डा. एजाज की गतिविधियां लंबे समय से संदिग्ध रही हैं। 2013 के पटना बम धमाकों में केंद्रीय एजेंसियों और स्पेशल सेल ने दोनों को हिरासत में लिया था। अलकायदा माड्यूल को खड़ा करने में एजाज की संलिप्तता मिलने पर गिरफ्तार किया जाएगा।

राजस्थान कनेक्शन को खंगाला जा रहा है

राजस्थान के पुलिस महानिदेशक यूआर साहू ने अजमेर में कहा कि भिवाड़ी में पकड़े गए छह संदिग्ध आतंकियों के राजस्थान कनेक्शन को खंगाला जा रहा है। राजस्थान एटीएस संदिग्ध आतंकियों के माड्यूल और उनकी योजना के बारे में जानकारी जुटा रही है।

कटकी की गिरफ्तारी के बाद माड्यूल को आगे बढ़ा रहा था

एक्यूआइएस के झारखंड माड्यूल का गठन आतंकी अब्दुल रहमान कटकी ने किया था। इश्तियाक और एजाज लंबे समय से कटकी से जुड़े थे। 2010 के बाद कटकी ने झारखंड के जमशेदपुर, रांची, लोहरदगा और हजारीबाग समेत कई शहरों का दौरा किया था। इन शहरों में तकरीर नाम के एक शख्स के जरिये वह मुस्लिम युवाओं से मिला। इस दौरान झारखंड के रहने वाले सैकड़ों मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथ के रास्ते पर लाकर उसने स्लीपर सेल बनाया था। आतंकी गतिविधियों के चलते 18 जनवरी 2016 को कटकी को स्पेशल सेल ने मेवात से गिरफ्तार किया था। उससे पूछताछ में पता चला था कि झारखंड से मुस्लिम युवाओं को वह कटक ले गया था, जहां धार्मिक पाठ के बहाने जिहाद के लिए उकसाया था।

त्रिपुरा में बाढ़ से 22 लोगों की मौत

65 हजार से अधिक राहत शिविरों में

▶ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम को दिया हरसंभव मदद का आश्वासन

▶ केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्य के लिए 40 करोड़ रुपये जारी करने को दी मंजूरी

त्रिपुरा अतिवृष्टि के बाद भीषण बाढ़ से जूझ रहा है। यहां के एक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दृश्य। एएनआइ

नई दिल्ली, प्रेट्र: त्रिपुरा में लगातार बारिश और बाढ़ के चलते स्थिति गंभीर बन गई है। बाढ़ में 22 लोगों की मौत हो गई है और दो अन्य लापता हैं। बुनियादी ढांचे, फसलों और पशुधन को भी भारी नुकसान हुआ है। राज्य में 65,400 लोगों ने 450 राहत शिविरों में शरण ली है, क्योंकि भारी बारिश के कारण उनके घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पूर्वोत्तर राज्य में बाढ़ से करीब 17 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि मृतकों के परिवारों के लिए 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित त्रिपुरा के लिए 40 करोड़ रुपये जारी करने को मंजूरी दी है।

भारी बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन के बाद शुक्रवार को भारत के पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में जीवनरक्षक नौकाओं में सवार सैनिकों ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। कारें और बसें सड़कों पर घुटनों तक पानी में फंसी हुई थीं। शुक्रवार की सुबह से स्थिति में कुछ सुधार के संकेत दिखे हैं, गुरुवार को भारी बारिश का सिलसिला थम गया है, जिससे गुमती, खोवाई, फेनी सहित प्रमुख नदियों के जल स्तर में कमी आई है, जो उफान पर थीं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुशांत चौधरी ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्य में भीषण बाढ़ के बावजूद त्रिपुरा में खाद्य पदार्थों और ईंधन का पर्याप्त भंडार है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बाढ़ राहत व बचाव कार्यों में राज्य सरकार की सहायता को केंद्र ने एनडीआरएफ की 11 टीम, सेना की तीन टुकड़ियां व हेलिकाप्टर तैनात किए हैं।

बांग्लादेश में बाढ़ से 13 लोगों की हुई मौत

बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में आई बाढ़ से 13 लोगों की मौत हो गई है। इस बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हुए और कई परिवार विस्थापित हो गए हैं। देश के कुल 64 जिलों में से 11 में बाढ़ के कारण लगभग 44 लाख प्रभावित हुए हैं। आई बाढ़ और भूस्खलन देश के कई हिस्सों में मकान, फसल, सड़क और राजमार्गों को भारी नुकसान पहुंचा है।

उत्तराखंड में भारी वर्षा का कहर जारी, पांच की गई जान

जागरण संवाददाता, रुद्रप्रयाग

▶ केदारघाटी में मलबे में दबकर चार नेपाली श्रमिकों की मौत, देहरादून में बाइक सवार खाई में गिरा

रुद्रप्रयाग के फाटा में शुक्रवार को मलबे में दबे लोगों को निकालकर लाते जिला आपदा मोचन बल के जवान। सूचना विभाग

उत्तराखंड में मानसून कहर बनकर बरस रहा है। गुरुवार रात रुद्रप्रयाग जिले की केदारघाटी में भारी वर्षा से उफनाए गदेरे के साथ आए मलबे में दबकर चार नेपाली श्रमिकों की मौत हो गई। इसी दरमियान देहरादून के विकासनगर क्षेत्र में नाले के तेज बहाव में अनियंत्रित हुई बाइक खाई में गिरने से युवक की जान चली गई। पौड़ी, टिहरी व देहरादून में एक दर्जन से अधिक घरों में मलबा भर गया और ग्रामीणों ने भागकर सुरक्षित स्थानों पर शरण ली। इससे कृषि भूमि को भी व्यापक नुकसान हुआ। टिहरी के गेवाली गांव में विद्यालय का भवन ध्वस्त हो गया। चमोली में भी एक आवासीय भवन ध्वस्त हुआ है और दो पैदल पुल बह गए। चमोली में नंदप्रयाग के पास भूस्खलन से बदरीनाथ राजमार्ग अवरुद्ध है, जिससे 700 से अधिक तीर्थयात्री विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए हैं। कोटद्वार में नजीबाबाद-बुआखाल राष्ट्रीय राजमार्ग मलबा आने से अवरुद्ध है। विभिन्न स्थानों पर सड़कों को क्षति पहुंची है। मैदानी क्षेत्रों में जलभराव परेशानी का सबब बना हुआ है। प्रदेश में पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी वर्षा के दौर हो रहे हैं। इससे दुश्वारियां बढ़ गई हैं और जनजीवन प्रभावित है।

हिमाचल के तीन पूर्व विधायकों से थाने में आठ घंटे हुई पूछताछ

जागरण संवाददाता, शिमला : हिमाचल सरकार गिराने का षड्यंत्र रचने के आरोपों के मामले में शुक्रवार को शिमला के बालूगंज थाना में तीन पूर्व विधायकों से आठ घंटे पूछताछ हुई। सुजानपुर के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा, नालागढ़ के पूर्व विधायक केएल ठाकुर और कुटलैहड़ के पूर्व विधायक देवेंद्र भुट्टो से पूछताछ हुई है। पुलिस ने फरवरी में हुए राज्यसभा चुनाव के बाद उत्तराखंड समेत कई अन्य स्थानों पर विधायकों के रहने व हवाई यात्रा के खर्च से संबंधित सवाल किए।

राजेंद्र राणा व देवेंद्र भुट्टो कांग्रेस के उन छह पूर्व विधायकों में शामिल हैं, जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन को मत दिया था। पूर्व निर्दलीय विधायक केएल ठाकुर ने भी भाजपा का साथ दिया था। इससे पहले पुलिस इस मामले में हमीरपुर से भाजपा विधायक आशीष शर्मा और उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव एवं पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा से पूछताछ कर चुकी है।

राजस्थान में भी आरएसएस की गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे सरकारी कर्मी

जासं, जयपुर

▶ राजस्थान सरकार ने वर्ष 1981 में आरएसएस सहित तीन संगठनों पर प्रतिबंध लगाया था

▶ हरियाणा, हिमाचल, मप्र व छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न सरकारें सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस से जुड़े होने पर प्रतिबंध को पहले ही हटा चुकी

राजस्थान में अब सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे। राजस्थान की भाजपा सरकार ने इस संबंध में लगी रोक को हटाने का फैसला किया है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी परिपत्र के अनुसार, 1981 के निर्देशों की समीक्षा करने के बाद आरएसएस पर लगी रोक हटाने का फैसला हुआ है।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान सरकार ने वर्ष 1981 में आरएसएस सहित तीन संगठनों पर प्रतिबंध लगाया था। राज्य के तत्कालीन मुख्य सचिव ने 18 मार्च 1981 को आदेश जारी किया था। इसके मुताबिक कोई भी सरकारी कर्मचारी आरएसएस, जमात ए इस्लामी और आनंद मार्ग संगठन के न तो सदस्य बन सकते थे और न ही उनकी गतिविधियों में शामिल हो सकते थे। विदित हो कि गत जुलाई माह में मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में एक मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने आरएसएस की गतिविधियों में अपने कर्मचारियों के शामिल होने पर 1966 में लगी रोक हटाने की जानकारी दी थी। इसके बाद अब राजस्थान सरकार ने प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। बताते चलें कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्य सरकारें सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस से जुड़े होने पर प्रतिबंध को पहले ही हटा चुकी हैं। गौरतलब है कि 30 नवंबर 1966 में केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने इंदिरा गांधी के शासन के दौरान लगाए गए प्रतिबंध को नौ जुलाई को एक आदेश के अनुसार हटा दिया।

रविवार नहीं, शुक्रवार को साप्तहिक अवकाश देने पर अड़े ग्रामीण

जागरण संवाददाता, मझगांव (प. सिंहभूम) : झारखंड में पश्चिम सिंहभूम जिले के मुस्लिम बहुल मझगांव प्रखंड अंतर्गत विद्यालय में रविवार को सार्वजनिक अवकाश दिए जाने के शिक्षा विभाग के आदेश का अभिभावकों ने विरोध किया है। पूर्व में यहां शुक्रवार को ही अवकाश रहता था और रविवार को विद्यालय खुलता था। लेकिन अवकाश के मामले में एकरूपता की बात को केंद्र में रखकर शिक्षा विभाग ने रविवार को विद्यालय बंद रखने का निर्देश पिछले दिनों जारी किया है। इससे छात्रों और अभिभावकों में नाराजगी है। नाराजगी का असर यह रहा कि शुक्रवार को कोई भी बच्चा स्कूल नहीं पहुंचा, केवल शिक्षकों की ही उपस्थिति विद्यालय में रही। इधर, इस मामले में अभिभावकों का कहना है कि 1953-54 से मझगांव और खड़पोस बीएमसी मकतब विद्यालय में साप्ताहिक सार्वजनिक अवकाश रविवार की जगह शुक्रवार ही रहा है, क्योंकि दोनों विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बच्चे मुस्लिम समुदाय के हैं।

'सीमा पर खनन देश की सुरक्षा से जुड़ा, क्या रोकने की जिम्मेदारी सेना सौंपें'

राज्य ब्यूरो, जागरण ● चंडीगढ़

▶ पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने केंद्र को हलफनामा दाखिल करने का दिया आदेश

▶ केंद्र सरकार पर लगाया 20 हजार का जुर्माना किया 5 हजार

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट। फाइल

सीमा के निकट खनन को देश की सुरक्षा से जोड़ते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि यहां खनन रोकने के लिए क्या सेना को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई पर इस संबंध में हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।

इस मामले में चंडीगढ़ निवासी गुरबीर सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि पंजाब में अवैध खनन का कार्य जोरों पर चल रहा है। पंजाब सरकार को हर वर्ष लगभग 10 हजार करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही अवैध खनन करते हुए नियमों व मानकों को ताक पर रख दिया जाता है। इससे न केवल पर्यावरण को नुकसान हो रहा है बल्कि प्राकृतिक आपदा का भय भी बढ़ जाता है। गत वर्ष इस मामले में पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाई कोर्ट को बताया था कि रक्षा मंत्रालय ने सीमावर्ती क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों व अन्य गतिविधियों को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के अनुसार समुद्र तटीय सीमा सहित सभी सीमाओं से 20 किलोमीटर के भीतर खनन से जुड़ी सभी गतिविधियों की योजना रक्षा मंत्रालय के परामर्श से ही बनाई जानी चाहिए।

केंद्र सरकार की ओर से बताया गया था कि पंजाब सरकार को कई बार सीमा पर अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से कहा गया लेकिन इस दिशा में कोई ठोस काम नहीं किया गया। बीएसएफ, सेना व केंद्र सरकार भी अवैध खनन और इसके जरिए सीमा क्षेत्र में होने वाली अवैध गतिविधियों को रोकने की दिशा में काम कर रही है। हाई कोर्ट ने तब रक्षा मंत्रालय को आदेश दिया था कि वह बताए कि सीमा के निकट कैसे वैध खनन की अनुमति दी जा सकती है। हाई कोर्ट ने इस संबंध में निर्णय लेकर अदालत को सूचित करने का आदेश दिया था। आठ माह से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद आदेश का पालन न होने को दुखद बताते हुए पिछली सुनवाई पर हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था।

यात्रा

पर्वत, सरिता और हरियाली निहारने संग पुण्यार्जन को पधारिए अमरकंटक

वर्षा की बूंदों के बाद और भी निखर उठता है तीर्थराज अमरकंटक का प्राकृतिक सौंदर्य

विनोद कुमार शुक्ला ● नईदुनिया

शहडोल: पर्वत, वन, सरिता और हरियाली के अद्भुत संगम को निहारने की उत्कंठा है तो अमरकंटक पहुंच जाएं। वर्षा ऋतु में अमरकंटक की छटा और निखर जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि पहाड़ों के बीच बादल जमीन पर उतर आए हैं। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित अमरकंटक को तीर्थराज की संज्ञा भी दी गई है। यह देश की पवित्र नदियों में से एक नर्मदा का उद्गम स्थल है। समुद्र तट से लगभग 1065 मीटर ऊंचाई पर स्थित अमरकंटक हिल स्टेशन की अनुभूति कराता है। कल्चुरी कालीन प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध अमरकंटक घने जंगल और औषधीय गुणों से भरपूर पौधों के लिए प्रसिद्ध है। अमरकंटक की यात्रा आध्यात्मिक स्पर्श कराती है।

पूर्व से पश्चिम की दिशा में बहने वाली देश की दो नदियों में एक नर्मदा का उद्गम एक छोटे से कुंड से हुआ है। पानी की झिर इस कुंड से होकर सहायक बड़े आयाताकार कुंड में एकत्र होती है। इस जलसंरचना का निर्माण कल्चुरी काल में किया गया। पत्थरों की चाहरदीवारी के अंदर पत्थर से निर्मित नर्मदा मंदिर, शिव, अन्नपूर्णा, गुरु गोरखनाथ, श्री रामजानकी और श्री राधा कृष्ण मंदिर सदियों पुरानी स्थापत्य कला को सहेजे हुए हैं। मंदिर परिसर के आस-पास परिक्रमावासियों के समूह अमरकंटक को तपस्थली के रूप में प्रतिबिंबित करते हैं। विश्व की एकमात्र सरिता जिसकी परिक्रमा की जाती है। कुंड से आगे निकलकर नर्मदा कल-कल बहने लगती है। लगभग छह किमी की यात्रा कर नर्मदा 100 फीट ऊंचा जलप्रपात बनाती है, जिसे कपिलधारा के नाम से जाना जाता है। हरे भरे वातावरण से घिरे इस झरने के आगे दूध धारा है जो छोटा जलप्रपात है। यहां पर्यटक निडर होकर स्नान करते हैं। अमरकंटक से दो और नदियों का उद्गम स्थल है। एक जोहिला है तो दूसरी सोन। गंगा की सहायक सोन अपने उद्गम स्थल से लगभग 100 मीटर आगे इस ऊंची पर्वत चोटी से कई सौ फीट नीचे गिरती है। जहां नीचे गांवों के घर छोटे-छोटे खिलौने जैसे दिखाई देते हैं।

कैसे पहुंचें और कहां ठहरें

अमरकंटक जबलपुर और बिलासपुर के निकट है। शहडोल से भी सड़क मार्ग से पहुंचा जा सकता है। निकटतम हवाईअड्डा जबलपुर में है। यहां से अमरकंटक की दूरी 220 किमी है। जबलपुर-बिलासपुर ट्रैक पर पेंड्रा रोड स्टेशन अमरकंटक के सबसे समीपस्थ रेलवे स्टेशन है। बिलासपुर, अनूपपुर और जबलपुर जंक्शन से भी अमरकंटक पहुंचा जा सकता है। यहां रुकने के लिए अच्छे होटल और सर्वसुविधा संपन्न आश्रमों के साथ-साथ होम स्टे सुविधा भी है। मध्य प्रदेश टूरिज्म कार्पोरेशन का गेस्ट हाउस भी अच्छी आवभगत करता है।

अमरकंटक स्थित नर्मदा के उद्गम स्थल पर कुंड और प्राचीन मंदिरों का समूह ● नईदुनिया

« अमरकंटक से शहडोल मार्ग पर जालेश्वर धाम मंदिर में विराजमान भगवान शिव ● नईदुनिया

अन्य प्रमुख स्थल : अमरकंटक के अन्य प्रमुख मंदिरों में भगवान शिव का त्रिमुखी मंदिर है। कल्चुरी शासक कर्ण देव महाचंद्र ने इसका निर्माण कराया था। मंदिर में कलचुरी कालीन शिल्पकारों की बनाई आकृतियां सम्मोहित करती हैं। इन मंदिरों का संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देख-रेख में हैं। माई की बगिया, जलेश्वर महादेव मंदिर और कबीर चबूतरा अन्य स्थानों को देखने के लिए लोग पहुंचते हैं।

अतिरिक्त सामग्री पढ़ने के लिए स्कैन करें।

बिहार के वीटीआर में क्षेत्र की लड़ाई में बाघ की मौत

जासं, पश्चिम चंपारण : बिहार में पश्चिम चंपारण जिले के वीटीआर (वाल्मीकि टाइगर रिजर्व) में क्षेत्र की लड़ाई में एक बाघ की मौत हो गई। उसका शव गुरुवार शाम को मिला। मृत बाघ के सिर, पैर और चेहरे पर दूसरे बाघ के पंजे के हमले से बने गंभीर जख्म के निशान मिले हैं। मृत बाघ की अवस्था करीब पांच वर्ष थी। बाघ की मौत दो-तीन दिन पूर्व होने की आशंका है। डीएफओ ने बताया कि अधिवास क्षेत्र की लड़ाई को लेकर दो बाघों के बीच संघर्ष में मौत हुई है। घटनास्थल पर एक और बाघ के पैरे के निशान मिले हैं। इस संघर्ष में उस बाघ के भी जख्मी होने की आशंका है। मृत बाघ का विसरा जांच के लिए भेजा जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट होगा।

****

निष्काम कर्म ईश्वर को ऋणी बना देता है

चिंता बढ़ाता बांग्लादेश

बांग्लादेश की स्थितियों को लेकर भारत का चिंतित होना स्वाभाविक है। एक तो वहां अस्थिरता का वातावरण दूर होने का नाम नहीं ले रहा है और दूसरे, भारत विरोधी तत्वों की सक्रियता थम नहीं रही है। बांग्लादेश में भारत विरोधी तत्व किस तरह सक्रिय हैं, इसका ताजा उदाहरण है वहां आई बाढ़ के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराना। सबसे खराब बात यह रही कि यह काम वहां की अंतरिम सरकार में शामिल एक मंत्री ने भी किया। ऐसा करके उन्होंने भारत के खिलाफ अफवाह फैला रहे तत्वों को प्रोत्साहन ही प्रदान किया। उनकी मानें तो बांग्लादेश में बाढ़ इसलिए आई, क्योंकि भारत ने त्रिपुरा में गुमती नदी पर बने एक बांध को खोल दिया। यह पूरी तरह असत्य और शरारत भरा बयान ही है, क्योंकि भारत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तथ्य यह भी है कि जिस बांध को खोलने की बात कही जा रही है, वह बांग्लादेश सीमा से 120 किलोमीटर दूर है। यह भी किसी से छिपा नहीं कि इन दिनों बांग्लादेश की तरह त्रिपुरा भी भारी बरसात के कारण बाढ़ से त्रस्त है। समझना कठिन है कि बांग्लादेश के जो लोग अपने यहां आई बाढ़ के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, वे इसकी अनदेखी कैसे कर रहे हैं कि उनके यहां भी पिछले कुछ दिनों से जोरदार बारिश हो रही है।

चिंता की बात केवल यह नहीं कि बाढ़ के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, बल्कि यह भी है कि बांग्लादेश की समस्याओं के लिए भी नई दिल्ली को दोष दिया जा रहा है। इसका एक कारण यह है कि तख्तापलट के बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत में शरण ली। नई दिल्ली को इसके प्रति सतर्क रहना होगा कि उनके कारण इस पड़ोसी देश में भारत विरोध को हवा न मिलने पाए। बांग्लादेश में मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार कार्य करने लगी है, लेकिन वह न तो हिंदुओं एवं अन्य अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न पर रोक लगा पा रही है और न ही भारत की चिंताओं को लेकर संवेदनशील दिख रही है। भले ही मुहम्मद यूनुस ने भारत को महत्वपूर्ण पड़ोसी देश बताया हो, लेकिन वह कट्टरपंथी और साथ ही भारत विरोधी तत्वों पर लगाम लगाने में सफल होते नहीं दिख रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनका उन पर कोई जोर नहीं, जो मनमानी करने में लगे हुए हैं और इसी क्रम में भारत पर बेतुके आरोप लगा रहे हैं। बांग्लादेश में भारत विरोधी माहौल को किस तरह हवा दी जा रही है, इसे इससे समझा जा सकता है कि पिछले दिनों भारतीय उच्चायुक्त को मुहम्मद यूनुस से मिलकर उच्चायोग की सुरक्षा के लिए उभरे खतरे की ओर ध्यान आकर्षित करना पड़ा। यदि बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग को खतरा है तो फिर यह कैसे मान लिया जाए कि अन्य भारतीय प्रतिष्ठानों और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।

सतर्कता जरूरी

स्वस्थ रहने के लिए सतर्कता आवश्यक है। मौसम में बदलाव के समय लोग अधिक बीमार होते हैं। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों तापमान में उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। यही कारण है कि कई लोग इन दिनों बुखार की चपेट में आ रहे हैं। अस्पतालों में चिकित्सकों की हड़ताल के कारण कम मामले सामने आए हैं, लेकिन निजी चिकित्सा संस्थानों में जुकाम एवं बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ी है। डेंगू, स्क्रब टायफस और डायरिया के मामले भी सामने आ रहे हैं। कई बार लोग बुखार को गंभीरता से नहीं लेते हैं और जब स्थिति गंभीर होती है तभी अस्पताल पहुंचते हैं। भीगने के कारण ही जुकाम एवं बुखार होता है। इसलिए लोगों को भीगने से बचना चाहिए। मानसून सीजन में पेयजल स्रोतों में दूषित पानी भी मिल जाता है। डायरिया फैलने का मुख्य कारण दूषित पेयजल और खाद्य पदार्थों का सेवन होता है। डायरिया से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इससे कई बार स्थिति गंभीर भी हो जाती है। डायरिया के लक्षण दिखने पर स्वच्छ पेयजल और ओआरएस घोल का सेवन करना चाहिए। इससे भी राहत न मिलने पर अस्पताल जाना चाहिए। सावधान रहकर ही बीमारियों से बचा जा सकता है। लोगों को इन दिनों पानी को उबाल कर पीना चाहिए और खुले में बिकने वाले और बासी खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। डेंगू एवं स्क्रब टायफस से बचाव के लिए घरों के निकट सफाई रखना भी अनिवार्य है। घरों के निकट पानी एकत्र होने से मच्छर पनपने की आशंका रहती है। खेतों एवं झाड़ियों में पाए जाने वाले चूहे घरों में घुस जाते हैं। चूहों में पाए जाने वाले पिस्सू के काटने से ही स्क्रब टायफस होता है। लोगों को खेतों में काम करते समय भी पूरी सावधानी बरतनी चाहिए।

> इन दिनों तापमान में उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। मानसून में स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है कि सावधानी बरती जाए

राजनीतिक विमर्श में गिरावट

डा. एके वर्मा

गिरते राजनीतिक विमर्श का एक कारण यह भी है कि सत्तापक्ष एवं विपक्ष में संवादहीनता आ गई है

भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक विमर्श के गिरते स्तर से देश को चिंतित होना चाहिए। संसद के अंदर-बाहर ऐसे मुद्दे उठते हैं जैसे बौद्धिक नहीं, युद्धिक विमर्श हो रहा हो। यूनेस्को के अनुसार, 'युद्ध मनुष्य के मस्तिष्क से उपजते हैं, अतः शांति का उपाय भी उसी मस्तिष्क से उपजना चाहिए।'' आज नेताओं के मस्तिष्क से जो निम्नस्तरीय विमर्श उपज रहा है, उसी से ही श्रेष्ठ विमर्श उपजेगा। नेताओं को कोसने से कुछ नहीं होगा। अच्छे लोगों को राजनीति में आना पड़ेगा, अन्यथा लोकतंत्र में लोगों की आस्था घट सकती है।

चुनाव बाद सरकार गठित होने पर विपक्ष को राजनीतिक विमर्श सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों, विधेयकीय प्रस्तावों, निर्णयों आदि की कमियों को जनता को बताने पर केंद्रित करना चाहिए, न कि सरकार को अपदस्थ करने पर। मुद्दा चाहे ओलिंपिक मेडल हो, हिंडनबर्ग जैसी विदेशी एजेंसियों की भारत विरोधी मुहिम हो, बांग्लादेश तख्तापलट, अदाणी समूह हो, जातीय-जनगणना हो, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एससी-एसटी आरक्षण में वर्गीकरण के निर्णय के विरुद्ध खड़ा होना हो या अन्य कई मुद्दा हो, विपक्ष स्वस्थ वाद-विवाद एवं बौद्धिक विमर्श से हट कर ऐसा आंदोलनात्मक रुख अपना रहा है, जैसे वह देश विरोधी बाह्यशक्तियों के मकड़जाल में हो। इसका जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड विधानसभा चुनावों और साथ ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों पर निश्चित प्रभाव पड़ेगा। क्या इस 'नैरेटिव वार' में भाजपा पिछड़ रही है? दस वर्षों तक सत्ता में रहने पर सत्तारूढ़ दल का प्रतिरक्षात्मक और विपक्ष का आक्रामक होना आसान है। जब आइएनडीआइए के अनेक दल नरेन्द्र मोदी और भाजपा विरोधी विमर्श का एक ही राग अलापते हैं तो जनमानस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भाजपा को चाहिए कि एनडीए के सहयोगी दल इस 'नैरेटिव वार' में भी उसके सहयोगी बनें। टीवी की बहसों में भी भाजपा का पक्ष कुछ ही पार्टी प्रवक्ता ठीक से रख पाते हैं।

प्रत्येक पार्टी को सत्ता और विपक्ष, दोनों में बैठने की संस्कृति सीखनी होगी। कभी दो लोकसभा सदस्यों वाली भाजपा ने लंबे समय तक विपक्ष की भूमिका का निर्वहन किया है, लेकिन संसद के अंदर-बाहर ऐसा आचरण नहीं किया, जैसा आज दिखाई देता है। कांग्रेस क्यों सत्ता के लिए इतनी उतावली हो रही है? जब जनता ने भाजपा को सत्ता सौंपी है तो कांग्रेस को जनादेश का आदर करते हुए इसे अवसर में बदलना चाहिए। वह संगठनात्मक स्तर पर पार्टी मजबूत करे, जनता को अपनी विचारधारा समझाए, नेतृत्व को परिपक्व करे और सरकारी नीतियों तथा निर्णयों की न केवल आलोचना करे, वरन जनता के समक्ष विकल्प भी रखे। यदि नेता-प्रतिपक्ष राहुल गांधी इंग्लैंड की तर्ज पर शैडो कैबिनेट यानी 'छाया-मंत्रिमंडल' बनाएं, जिसके सदस्य प्रत्येक विभाग के मंत्री पर नजर रखें, उनकी गंभीर एवं तथ्यात्मक आलोचना करें तो भविष्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर कुछ ऐसे लोग होंगे, जिनको विभिन्न मंत्रालयों और विभागों का ज्ञान और अनुभव होगा। सत्ता पर किसी दल का एकाधिकार नहीं होता। सरकारें बदलती हैं, लेकिन विपक्ष को प्रमाणित करना होता है कि जनता उसे सत्ता क्यों सौंपे? जिस प्रकार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने का भ्रामक विमर्श चला कर कुछ सीटें जीत लीं, वह आगामी चुनावों में उनके गले की हड्डी बन सकता है, क्योंकि इससे पार्टी विमर्श की विश्वसनीयता संदिग्ध हो गई है। आगे यदि वे सही मुद्दे उठाएंगे तो भी शायद जनता उसे भ्रामक मानेगी। स्वस्थ विमर्श देश, दल और लोकतंत्र तीनों के लिए जरूरी है।
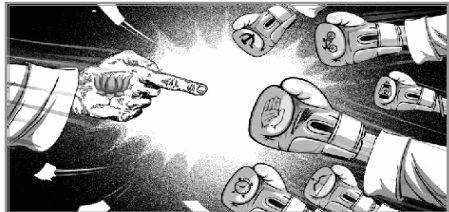
अवधेश राजपूत

विमर्श का गिरता स्तर वैचारिक खेमेबाजी तथा जातिवादी जनाधार को भावनात्मक रूप से सम्मोहित करने से भी उपजता है, जो बौद्धिकता से दूर होता है और सरकारों को देश-हित में निर्णय लेने से रोकता है। यह व्यक्तिगत और दलीय-हित को देश-हित से ऊपर रखने, सामुदायिक-मूल्यों को वस्तुनिष्ठ तथ्यों से ऊपर रखने तथा समावेशी राजनीति के ऊपर बहिर्वेशी राजनीति रखने का दुष्परिणाम है। गिरते विमर्श का एक कारण यह भी है कि राजनीतिक दलों और सत्तापक्ष एवं विपक्ष में संवादहीनता आ गई है। वे एक-दूसरे को समझना ही नहीं चाहते।

अमेरिका और इंग्लैंड भी इस बीमारी से त्रस्त हैं। वहां भी अलगाव, ध्रुवीकरण और तनाव बढ़ रहे हैं। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में यह प्रवृत्ति और घातक हो सकती है। इंटरनेट मीडिया के प्रादुर्भाव ने इसे और गहरा दिया है। संसदीय कार्यवाही के सजीव प्रसारण से भी कुछ सांसदों का व्यवहार अपने निर्वाचन क्षेत्र को दृष्टिगत रख कर होता है। प्रायः विदेश के प्रतिनिधिमंडल, विशिष्ट अतिथि और सांसदों के परिवार दर्शक दीर्घा में होते हैं। उनका भी लिहाज कुछ सांसद नहीं कर पाते। प्रयास हो कि विमर्श में तथ्य सही और तर्क कठोर, पर भाषा एवं प्रस्तुतीकरण शालीन और सम्मानजनक हो। संसद में कही गई बातों के संबंध में संवैधानिक-उन्मुक्तियों का यह अर्थ नहीं कि वहां कुछ भी कहा या किया जाए। जब सांसद संसदीय प्रक्रियाओं और नियमों का उल्लंघन करते हैं तो पीठासीन अधिकारियों की कठिनाइयां काफी बढ़ जाती हैं। संसद में नारेबाजी, बैनर और तख्तियां लटकाना, संविधान की प्रति लेकर प्रवेश करना, सदन कूप में आना आदि जनता को कितना आहत करते हैं, इसका अनुमान सांसदों को नहीं। कुछ अवसरों पर जब सांसदों में आम सहमति से कोई विधेयक पारित होता है, तो जनता को कितनी खुशी होती है, इसका भी अनुमान उन्हें नहीं। वैचारिक असहमतियों के बावजूद विभिन्न दलों के सांसदों के लिए संसद राजनीतिक परिवार जैसा है। परिवार में असहमतियों के बावजूद एक-दूसरे के प्रति आदर में कोई कमी नहीं होती। लोकतंत्र आलोचना, असहमतियों और आदर की त्रिवेणी है। 75 वर्षों के बाद भी यदि हम इस त्रिवेणी पर नहीं पहुंच सके तो वर्तमान और भावी पीढ़ी लोकतांत्रिक संगम में स्नान कैसे करेगी? यदि हम उनमें लोकतांत्रिक संस्कार नहीं भर सके, तो उन्हें लोकतंत्र की सार्थकता कैसे समझ आएगी?

(लेखक सेंटर फार द स्टडी आफ सोसायटी एंड पालिटिक्स के निदेशक एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

खुद कठिनाई में संकट का साथी

डा. ब्रजेश कुमार तिवारी

यह विचित्र है कि आज तक हम पुलिसकर्मियों की सेवा शर्तों को मानवीय नहीं बना पाए हैं

कोलकाता के आरजी कर अस्पताल की प्रशिक्षु महिला डाक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में एफआइआर दर्ज करने से सहित इसकी जांच में बरती गई लापरवाही को लेकर बंगाल पुलिस पर हर तरफ से सवाल उठ रहे हैं। देश में पुलिस के कामकाज के तौर-तरीके में आई गिरावट का यह कोई पहला प्रकरण नहीं है। ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे, जहां पुलिस का रवैया पूरी तरह से गैर-जिम्मेदाराना रहा। हालांकि यह सच है कि जब भी लोग परेशानी में फंसते हैं, तब उन्हें पुलिस से ही सहारा मिलता है। पुलिस के बिना देश और राज्य के प्रशासन की सुरक्षा की कल्पना तक नहीं की जा सकती है। कहीं पर भी जुलूस, सभा, रैली, मेले से लेकर होली-दीवाली, ईद आदि में शांति की व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी इसी के कंधों पर होती है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा भी पुलिस ही करती है। साथ ही किसी भी आपदा, दुर्घटना या अप्रिय स्थिति में पुलिस साथी की भूमिका निभाती है। यदि हम मुसीबत में हों और उसी समय पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई दे तो यह हमारा हौसला बढ़ाती है। यहां तक कि जब कोई अर्थी को कंधा देने वाला नहीं मिलता, तब पुलिस कंधा तक देती है। बावजूद इसके 24 घंटे काम करने वाली पुलिस को लेकर आम जन में अविश्वास का भाव अभी भी है। कुछ भ्रष्ट पुलिस वालों की वजह से अधिकतर लोगों की नजरों में पुलिस की छवि खराब है। इसीलिए जिस आम आदमी को पुलिस के सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत होती है, वह अक्सर पुलिस से दूर भागने का हरसंभव प्रयास करता है।

हम सबको पुलिस से बेहतर परिणाम की अपेक्षा है, मगर उस पर काम का बोझ इस कदर है कि आम आदमी अंदाजा नहीं लगा सकता। हम कभी-कभी तनाव लेते हैं, लेकिन हमको यह पता भी नहीं होता कि पुलिस रोजाना कितने तनाव में कार्य करती है। अधिकांश पुलिसकर्मी अपने परिवार के साथ त्योहार तक नहीं मना पाते। एक पुलिसकर्मी अपने परिवार का सदस्य होकर भी अपने परिवार में नहीं होता। चाहे कोई भी मौसम हो या दिन हो रात हो, थाना एवं पुलिस चौकी 24 घंटे खुली रहती है। महिला पुलिसकर्मियों के लिए कार्य करना तो और भी चुनौतीपूर्ण है। अधिकतर बीट एवं बंदोबस्त प्वाइंट पर शौचालय की सुविधा न होने के कारण उन्हें घंटों तक शौचालय उपयोग किए बिना खड़ा रहना पड़ता है। यहां तक कि पुलिस स्टेशन की संरचना और पुलिस की वर्दी भी पुरुषों के अनुसार ही बनाई गई है। पुलिस पर राजनीतिक दबाव की तो कोई सीमा ही नहीं है। जब भी किसी पहुंच वाले शख्स को पुलिस पकड़कर ले जाती है, तो उसे छुड़वाने के लिए रसूखदार नेताओं के फोन आने लगते हैं। ऐसे समय में जब अनेक नेता अपराधी प्रवृत्ति के हैं तो पुलिस से क्या ही उम्मीद की जा सकती है? ऊपर से रोज-रोज के स्थानांतरण एवं पुलिस के कामकाज में राजनीतिक दखल ने पुलिस-व्यवस्था को बहुत तोड़ा है। इसके चलते खाकी की हनक कम होती जा रही है, जिससे लोगों में कानून का डर भी कम होता जा रहा है।

पुलिस पर बढ़ता जा रहा काम का बोझ। प्रेट्र

इन सब समस्याओं को दूर कर पुलिस को प्रभावी बनाने के लिए देश में पुलिस सुधारों पर काम करीब चार दशक पहले शुरू हुआ था, पर आज तक हम पुलिसकर्मियों की सेवा शर्तों को मानवीय नहीं बना पाए। संयुक्त राष्ट्र के मानकों के अनुसार, जहां प्रति लाख आबादी पर 222 पुलिसकर्मी होने चाहिए, वहीं भारत की प्रति लाख आबादी पर 181 पुलिसकर्मी स्वीकृत हैं। वास्तव में असल संख्या इससे भी काफी कम है। इसीलिए लगभग 90 प्रतिशत पुलिसकर्मियों को हर रोज 15 घंटे से भी अधिक समय काम करना पड़ता है। तीन चौथाई कर्मी साप्ताहिक अवकाश भी नहीं ले पाते हैं। देश में लगभग 18 हजार पुलिस थाने हैं, पर ज्यादातर थानों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। जिस तेजी से महिलाओं की जरूरत पुलिस सेवा में बढ़ रही है, उसके लिए थानों में अलग से शौचालय, डिस्पेंसरी, नर्सिंग रूम, महिला पुलिसकर्मियों के लिए वैकल्पिक यूनिफार्म आदि उपलब्ध कराने होंगे। कैग आडिट में राज्य पुलिसबलों के पास हथियारों की कमी पाई गई है। पुलिस वाहनों को भी समयानुरूप करना होगा। अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप को खत्म करना और पुलिस व्यवस्था में आंतरिक पारदर्शिता एवं जवाबदेही जैसे मूल्य सुनिश्चित किया जाना भी समय की मांग है।

पुलिस सुधारों की रूपरेखा तय करते समय समाजशास्त्र के नियमों को भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि उसे जनता के साथ नियमित रूप से व्यवहार करने की आवश्यकता होती है। समाज और सिस्टम को पुलिस से अपेक्षाएं सबसे ज्यादा हैं, इसलिए विश्वास बनाना और उसे बढ़ाना आज पुलिस की अहम जिम्मेदारी है। उसे पुलिसिंग के अपने तरीकों में भी परिवर्तन करना होगा और यह तभी संभव है, जब एक तरफ समाज और दूसरी तरफ पुलिस-प्रशासन मिलकर प्रयास करें। बदलते परिवेश में पुलिस को और ज्यादा संवेदनशील बनना होगा। पुलिस को यह भी समझने की जरूरत है कि उसे मिले अधिकार जनता की सुरक्षा एवं सेवा के लिए मिले हैं, न कि लोगों पर रौब दिखाने के लिए। पुलिस की छवि अच्छी बने, इसके लिए भ्रष्ट पुलिसकर्मियों का पुरजोर विरोध भी उन्हें करना होगा। पुलिस को अपनी छवि और कार्य स्थिति में सुधार लाने के लिए नया नजरिया विकसित करना होगा। इन सभी प्रयासों के लिए प्रबुद्ध पुलिस के साथ-साथ राजनीतिक नेतृत्व और दृढ़ इच्छाशक्ति की आवश्यकता है।

(लेखक जेएनयू के अटल स्कूल आफ मैनेजमेंट में प्रोफेसर हैं)

response@jagran.com

युद्ध और अहिंसा

हिंसा, युद्ध और आतंकवाद जैसी स्थितियां असंतुलित व्यक्ति के दिमाग से उत्पन्न होती हैं। व्यक्ति समाज और राष्ट्र में जीता है। समाज और राष्ट्र के प्रश्न पर युद्ध को नकारा नहीं जा सकता, किंतु इसमें अहिंसा के लिए बड़ा क्षेत्र खुला है-जैसे स्वयं आक्रांता न बनें, निरपराध को न मारें। एक प्रश्न यह भी है कि मनुष्य कितना भी युद्ध करे, अंततः उसे समझौते की टेबल पर आना ही होता है तो फिर पहले से ही समझौते की टेबल पर क्यों नहीं आ जाता? आधुनिक युग की सभी समस्याओं का समाधान है अहिंसा। आज भी 98 प्रतिशत आदमी शांति, सहअस्तित्व एवं सहयोग के साथ रहते हैं, वे हिंसा नहीं चाहते। सिर्फ दो प्रतिशत आदमी हिंसा में सम्मिलित हैं। इन दो प्रतिशत लोगों को उकसाने के लिए कितने षड्यंत्र रचे जाते हैं, हिंसा का प्रशिक्षण दिया जाता है, शस्त्रों की बिक्री के लिए हिंसा के बीज बोए जाते हैं। सत्ता, संपदा, शक्ति का आकर्षण इतना बढ़ रहा है कि इनकी आसक्ति में हमारा दृष्टिकोण संकुचित हो रहा है। आदमी सिर्फ अर्थ और सत्ता को केंद्र मानने लगा है। अर्थ आजीविका का साधन है, उसे साध्य मानने से ही सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। अनासक्त चेतना के जागरण से आसक्ति का आवरण हट सकता है। आकांक्षाओं के अल्पीकरण अर्थात संयम की साधना को अपनाकर ही हम अपना विकास कर सकते हैं, जो अहिंसा का महत्वपूर्ण सूत्र है।

जब तक जीवन में दंभ रहेगा, क्षोभ रहेगा, तब तक शांति संभव नहीं है। इच्छाओं का विस्तार ही हिंसा का सबसे बड़ा कारण है। दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन न करना ही शांति एवं अहिंसा का मूल स्रोत है। विडंबना है कि देश और दुनिया में जितनी भी हिंसा हो रही है वह सब शांति के लिए है। यह हमारे मानसिक असंतुलन का ही एक कारण है कि बात चले विश्व शांति की और कार्य हो अशांति के तो, शांति कैसे संभव है?

ललित गर्ग

साइबर ठगी से बचाव के उपाय

सुनीता मिश्रा

पुलिस, सीबीआइ, आरबीआइ, इनकम टैक्स आदि का अधिकारी बनकर कोई फोन कर डरा-धमकाकर पैसे मांगे तो सतर्क हो जाएं

देश में साइबर अपराध के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ठग नए-नए तरीके अपनाकर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। इन दिनों साइबर ठग पढ़े-लिखे लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर उनसे आनलाइन लाखों-करोड़ों रुपये ठग रहे हैं। हाल में लखनऊ में पीजीआइ की डाक्टर रुचिका टंडन को सात दिनों तक डिजिटल अरेस्ट कर करीब तीन करोड़ की ठगी की गई। देश में इंटरनेट के बढ़ते दायरे के साथ ही आनलाइन ट्रांजेक्शन का चलन भी बहुत तेजी से बढ़ा है। इसके साथ ही आनलाइन धोखाधड़ी के मामले भी बढ़े हैं। वर्ष 2022-23 में साइबर ठगी से जुड़े 11.28 लाख मामले देशभर में सामने आए थे। तमाम अभियानों और ठगी के मामलों के बावजूद प्रतिदिन हजारों लोग इन जालसाजों का शिकार हो रहे हैं। इनमें से अधिकतर पीड़ित डर से रिपोर्ट तक नहीं कराते हैं या फिर रिपोर्ट करवाने में देरी कर देते हैं, जिससे उनका डूबा हुआ पैसा मिलने की संभावनाएं कम होती जाती हैं।

डिजिटल अरेस्ट साइबर अपराध का नया तरीका है। इसमें ठग पुलिस, सीबीआइ, आरबीआइ, इनकम टैक्स या अन्य एजेंसियों का अधिकारी बनकर काल करते हैं और पीड़ित को डरा-धमकाकर, लालच देकर या किसी दूसरे बहाने से वीडियो एवं आडियो काल पर जोड़े रखते हैं। ठगी करने से पहले अपराधी अपने शिकार से जुड़ी सभी जानकारियां एकत्रित करते हैं। ये ज्यादातर उन लोगों को अपना शिकार बनाते हैं जिनकी वित्तीय स्थिति अच्छी होती है। हाल में जितने भी मामले सामने आए हैं, उनमें कोई डाक्टर है, कोई इंजीनियर तो कोई आइआइटी की प्रोफेसर है। साइबर अपराधी वारदात को अंजाम देने से पहले एक ऐसा सेटअप बना लेते हैं, जिसमें लगता है कि वे पुलिस स्टेशन से बात कर रहे हैं। वे लोगों को काल पर गिरफ्तारी का डर दिखाकर घर पर ही कैद कर लेते हैं और उन्हें पैसे देने के लिए मजबूर कर देते हैं।

जागरूकता और थोड़ी सावधानी रखकर इस तरह की ठगी से बचा जा सकता है। ध्यान दें कि पुलिस, सीबीआइ, बैंक या फिर कोई भी जांच एजेंसी काल पर आपको डरा या धमका नहीं सकती है और न ही फोन पर आपसे जुड़ी व्यक्तिगत जानकारी और अकाउंट की डिटेल मांग सकती है। ऐसे में सतर्क हो जाएं। फोन पर किसी को कोई भी व्यक्तिगत जानकारी न दें। यदि आपको किसी भी तरह से कोई भी गतिविधि संदिग्ध लगे तो काल काट कर बिना देर किए तत्काल पुलिस को रिपोर्ट करें। ऐसा करके आप किसी बड़ी घटना का शिकार होने से बच सकते हैं। इंटरनेट मीडिया पर आने वाले शेयर ट्रेडिंग से जुड़े आकर्षक विज्ञापनों और भारी मुनाफा दिलाने का दावा करने वाले आफर से भी सावधान रहें।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

जल संबंधी बुनियादी ढांचे का हो निर्माण

''बरसात और बाढ़ से बढ़ता नुकसान'' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में अनिल प्रकाश जोशी ने अल नीनो के दुष्प्रभाव से होने वाली अतिवृष्टि के दुष्परिणामों से बचने के लिए बेहतर आधारभूत ढांचे के विकास हेतु नीति निर्माण की आवश्यकता को रेखांकित किया है। इसी विषय से मिलता-जुलता एक आलेख कुछ दिनों पूर्व प्रकाशित हुआ था जिसमें ड्रेनेज सिस्टम को उन्नत बनाने के उपाय सुझाए गए थे। इन दोनों आलेखों की निरंतरता में जोड़ना चाहता हूं कि जलवायु परिवर्तन अब सत्य है, सिद्ध है। अतः इस परिवर्तन के फलस्वरूप अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल, कभी बाढ़-कभी सूखा, बादल फटना, अल नीना, ला नीना, भूकंप के छोटे-बड़े झटके, चक्रवाती तूफान, सुनामी आदि की घटनाएं बारंबार होंगी। इनमें लगभग सभी का पूर्वानुमान और भविष्यवाणी विज्ञान के मदद से संभव है, अपवाद सिर्फ बादल फटने की घटना का है। ये सभी प्राकृतिक आपदाएं वायु और जल पर आधारित हैं। ऐसे में यदि बड़े और दीर्घकालिक जल संबंधी बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाए तो भविष्य में इन प्राकृतिक आपदाओं से मौजूदा बुनियादी ढांचों जैसे बड़े-बड़े पुल, रेल, रोड, हवाई अड्डे, विद्युत, संचार और नहर आदि नेटवर्कों को क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सकता है, अन्यथा चौगुनी हानि राष्ट्र को झेलनी पड़ सकती है। जलवायु परिवर्तन की पृष्ठभूमि में भविष्य में प्राकृतिक आपदाएं शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में और विकराल रूप ले सकती हैं। मानव सभ्यता इसे नियंत्रित नहीं कर सकती। समाज सिर्फ उसके निवारण या निदान का प्रबंध कर सकता है। इसके लिए राष्ट्र को एक इकाई मानकर जलापूर्ति और जलनिकासी तंत्र का निर्माण हो। राष्ट्रव्यापी जल संबंधी बुनियादी ढांचे का निर्माण कर भारत को आत्मनिर्भर बनाया जाए। इसी में हम सबका हित है।

प्रोफेसर मान सिंह, पूर्व परियोजना निदेशक, जल प्रौद्योगिकी केंद्र, आइएआरआइ, नई दिल्ली

शांति का पाठ

'शांति का संदेशवाहक भारत' शीर्षक आलेख में श्रीराम चौलिया ने उचित लिखा है कि बहुपक्षीयता एक रचनात्मक अवस्था है। गुटनिरपेक्षता की पुरानी जंजीर तोड़कर आज भारत बहुपक्षीयता के पथ पर चल निकला है और इसी के साथ भारत अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सकारात्मक किरदार निभाने की स्थिति में आ गया है। वैश्विक स्तर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का कद इतना ऊंचा हो चुका है कि वह आज पूरी दुनिया को राह दिखा रहे हैं। उनके विचार को शक्तिशाली देश भी पूरे ध्यान से सुन रहे हैं और उस पर अमल भी कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी को विश्व शांति दूत के रूप में देखा जाने लगा है। भारत ने विश्व भर में संयुक्त राष्ट्र मिशनों के माध्यम से सदैव वैश्विक शांति, एकता और सद्भाव में योगदान दिया है। भारत शांति के दूत के रूप में हमेशा दुनिया में शांति, एकता और सद्भाव का समर्थन करता रहा है। हमारा मानना है कि सभी को शांति और सद्भाव में रहना चाहिए और बेहतर एवं शांतिपूर्ण कल की ओर बढ़ना चाहिए। पीएम मोदी के शांति पाठ का समर्थन करते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक सत्र में कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा था कि यह युद्ध का समय नहीं है। उनकी यह बात एकदम सही थी। यह पश्चिम से बदला लेने और उसे पूर्व के खिलाफ खड़ा करने का समय नहीं है। यह वक्त है कि हम सभी संप्रभु राष्ट्र मौजूद चुनौतियों का एकजुट होकर मुकाबला करें। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का वह बयान सिद्धांतों के आधार पर दिया गया बयान था, जिसे वह सही मानते हैं। सुलिवन ने कहा कि मुझे लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा वह सही और न्यायपूर्ण है। उनकी ओर से सिद्धांतों के आधार पर दिया गया बयान है। इसका बहुत स्वागत किया गया। भारत के रूस से लंबे रिश्ते हैं, इसके बावजूद उसने इस बात पर जोर दिया कि यह जंग खत्म करने का समय है।

युगल किशोर राही, ग्रेटर नोएडा

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।
****

आजकल

प्रशासनिक सेवाओं में लेटरल एंट्री के मायने

संघ लोक सेवा आयोग ने केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 45 पदों पर नियुक्ति के लिए लेटरल एंट्री के माध्यम से भर्ती की प्रक्रिया शुरू की थी। परंतु इस मामले पर विवाद उत्पन्न होने के बाद भारत सरकार ने फिलहाल अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। यूपीएससी के इस कदम से ब्यूरोक्रेसी में लेटरल एंट्री पर फिर से बहस छिड़ गई है। इसका विरोध करने वाले लोगों का तर्क है कि इस प्रक्रिया से उच्च पदों पर अनुसूचित जाति-जनजाति और पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों का पहुंचना और मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में लेटरल एंट्री के निहितार्थ को समग्रता में समझा जाना चाहिए

कैलाश बिश्नोई
लोक नीति विश्लेषक

देश में शीर्ष प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकारियों का चयन संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से होता है। फाइल

शासन में सुधार वर्तमान सरकार का एक महत्वपूर्ण एजेंडा है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार लेटरल एंट्री पर तमाम विवादों के बीच आगे बढ़ना चाहती है। लेटरल एंट्री को सरल शब्दों में समझें तो यूपीएससी की तीन चरणों वाली सिविल सेवा परीक्षा पास किए बिना ब्यूरोक्रेसी में उच्च पद पर नियुक्ति मिल सकती है। यानी निजी क्षेत्र का वह व्यक्ति जो आइएएस नहीं है, परंतु अपने विषय क्षेत्र में विशेषज्ञ है और सरकार द्वारा निर्धारित किए गए मापदंडों को पूरा करता है तो उसे भारत सरकार में संयुक्त सचिव, विशेष सचिव या पीएसयू में डायरेक्टर आदि के पद पर नियुक्त कर सकती है। लेटरल एंट्री में कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, केवल साक्षात्कार के बाद चयन होगा। यहां यह समझना जरूरी है कि सिविल सेवा में लेटरल एंट्री देना तभी अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है, जब चयन प्रक्रिया को राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाया जा सके।

पार्श्व प्रवेश का इतिहास : भारत में पार्श्व प्रवेश यानी बैक डोर एंट्री के तहत उच्च पदों पर नियुक्तियां कोई पहली बार नहीं की जा रही है, बल्कि इस प्रकार की नियुक्तियां पहले भी की जाती रही हैं। फर्क केवल इतना है कि इस बार इनके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। विगत 30-40 वर्षों में कई बार उच्चाधिकारियों की नियुक्ति इस प्रकार लेटरल एंट्री से की गई है और अनुभव कोई बुरा नहीं रहा। यदि पहले के अनुभवों की बात करें, तो कुछ ही ऐसे लोग हैं जो यूपीएससी द्वारा चयनित होकर नहीं आए हैं, फिर भी शीर्ष स्तर पर शानदार काम किया है। जैसे रघुराम राजन और नंदन नीलेकणी। वहीं, एम. एस. स्वामीनाथन, वी. कृष्णमूर्ति, सैम पित्रोदा आदि ऐसे नाम हैं, जिन्होंने भारतीय प्रशासन की उन्नति में अहम भूमिका निभाई है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को वर्ष 1971 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया था और उन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा नहीं दी थी। वर्ष 1972 में उन्हें वित्त मंत्रालय का मुख्य आर्थिक सलाहकार भी बनाया गया था। यह पद भी संयुक्त सचिव स्तर का ही होता है।

मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री के पद पर थे, तब रघुराम राजन को अपना मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया था और वे भी यूपीएससी से चुनकर नहीं आए थे, लेकिन संयुक्त सचिव के स्तर तक पहुंचे थे। बाद में उन्हें रिजर्व बैंक का गवर्नर भी बनाया गया था। बिमल जालान आइसीआइसीआइ के बोर्ड मेंबर थे, जिन्हें सरकार में लेटरल एंट्री मिली थी और वह रिजर्व बैंक के गवर्नर बनाए गए थे। उर्जित पटेल (रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर) भी लेटरल एंट्री से इस पद पर आए थे। मनमोहन सिंह, मोंटेक सिंह अहलूवालिया, बिमल जालान, अरविंद पनगड़िया आदि ऐसे कई नाम हैं, जिन्हें विशेषज्ञता के आधार पर प्रशासन में प्रवेश दिया गया। इनमें से बहुतों ने 1991 के पश्चात हुए आर्थिक सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसके परिणाम आज हमें अर्थव्यवस्था की प्रगति के रूप में दिखाई दे रहे हैं।

लेटरल एंट्री से जुड़ी चिंताएं : एक आशंका यह है कि इस प्रक्रिया से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल सकता है। अगर बात प्रशासनिक खेमे की करें तो ब्यूरोक्रेसी ने लेटरल एंट्री का कभी भी स्वागत नहीं किया है। उसका मानना है कि आइएएस की परीक्षा को पास करना बहुत कठिन काम है। दूसरे, सिविल सेवा का अधिकारी जिला स्तर पर कार्य करते हुए प्रशासन की जमीनी वास्तविकता को अच्छे से समझता है। उसे गांव, जिला और राज्य का बेहतर अनुभव प्राप्त हो जाता है। तीसरे, ऐसा भी कहा जा रहा है निजी क्षेत्र के मैनेजर, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबंधन में अक्सर विफल हो जाते हैं। इसके लिए वायुदूत, इंडियन एयरलाइंस आदि का उदाहरण दिया जा रहा है।

इसमें कोई दोराय नहीं है कि हमें प्रशासन में विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों और संयुक्त सचिव के स्तर पर बेहतर पेशेवर दक्षता की जरूरत है, लेकिन यहां अहम सवाल यह भी है कि क्या सिविल सेवा में लेटरल एंट्री की पहल ही पेशेवरों की कमी खत्म करने का सबसे बेहतर तरीका है? दरअसल, निजी क्षेत्र का दृष्टिकोण लाभोन्मुखी होता है। दूसरी ओर, सरकार का उद्देश्य सार्वजनिक सेवा है। यह एक मौलिक या आधारभूत संक्रमण है जिसमें निजी क्षेत्र के व्यक्ति को सरकार के साथ कार्य करते समय संक्रमण से गुजरना पड़ता है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि बैक डोर एंट्री को प्रशासनिक अधिकारी और उनके संघों द्वारा प्रतिरोध झेलना पड़ सकता है।

आगे की राह : इसमें कोई दोराय नहीं कि देश में प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा करने से पहले इसे राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त करने की भी जरूरत है। निजी क्षेत्र में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। सरकार इनकी सहायता से अपने नीतिगत निर्णयों की प्रक्रिया में सुधार कर सकती है। प्रशासन में बैक डोर एंट्री के लिए सरकार यह वजह बता रही है कि राज्यों में नियुक्त वरिष्ठ अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली नहीं आना चाहते, इसलिए मंत्रालयों और सचिवालय में सचिव, संयुक्त सचिव और निदेशक जैसे पद रिक्त रह जाते हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्ष 1990-1995 के बीच भर्ती किए जाने वाले आइएएस अधिकारियों की संख्या गिरकर 55 के करीब आ गई। ये वे अफसर हैं, जो आज संयुक्त सचिव के पद के योग्य हुए होंगे। चूंकि हमने एक कठिन दौर में पर्याप्त भर्तियां नहीं कीं, इसलिए आज संयुक्त सचिव के स्तर पर अफसरों की भारी कमी है। भविष्य में ऐसे हालात बनने से रोकने के लिए सरकार को आइएएस और आइपीएस पदों की संख्या हर साल क्रमशः 180 और 200 से बढ़ाकर 250 और 230 कर देनी चाहिए। कहने का आशय यह कि केंद्र सरकार को इस रास्ते पर आगे बढ़ने से पहले यही उचित होगा कि देश की जरूरतों के मद्देनजर यूपीएससी के माध्यम से नियुक्तियों की संख्या बढ़ाई जाए। रही बात लेटरल एंट्री की, तो इसकी व्यवस्था केवल वहीं की जानी चाहिए, जहां किसी विशेष क्षेत्र में लक्ष्य आधारित परिणाम हासिल करने की जरूरत हो। अतः लेटरल एंट्री की व्यवस्था के निर्माण में उपरोक्त बातों का भी ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए, अन्यथा एक बेहतरीन उद्देश्यों वाली व्यवस्था कारगर सिद्ध होने के बजाय घातक हो सकती है।

प्रशासनिक सेवाओं में सुधार का महत्व

भारत में एक आम आदमी से सबसे अधिक रिश्वत परिवहन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और भूमि या मकान संबंधी संपत्ति की खरीद-बिक्री वाले कार्यालयों में मांगी जाती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में सार्वजनिक कार्यालय से काम कराने के लिए भारत के 62 प्रतिशत लोगों ने रिश्वत देने की बात स्वीकार की है। कुछ अर्थशास्त्रियों का तो यहां तक मानना है कि भारत के विकास में बाधा का एक बड़ा कारण यहां की नौकरशाही ही है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि लोग अक्सर नौकरशाही को सेवा प्रदाता के बजाय शोषण के एजेंट के रूप में देखते हैं। प्रशासन और आम जनता में दूरी बनी हुई है। एक तरह से नौकरशाही में मध्यकाल की सामंतशाही नजर आती है। अंतर केवल यह है कि शोषण का अंदाज बदल गया है और इसमें भ्रष्टाचार की भूमिका केंद्रीय हो गई है। आम तौर पर कहा जाता है कि सबसे बेहतरीन प्रतिभाएं सिविल सेवा के लिए चुनी जाती हैं। इसके आकर्षण पर कारपोरेट जगत की भारी भरकम पैकेज वाली नौकरी भी कोई असर नहीं डाल पाती। दुख तब होता है जब देश की सर्वोच्च प्रशासनिक परीक्षा पास कर सेवा में आने वाले एक के बाद एक अफसरों की चर्चा सकारात्मक कार्यों से अधिक रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के लिए होने लगे। इससे जाहिर होता है कि भारतीय नौकरशाही के इस्पाती ढांचे में जंग लग रहा है। ऐसे में भारत कैसे भ्रष्टाचार मुक्त हो पाएगा? लिहाजा देश के विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए वर्तमान सरकार द्वारा प्रशासनिक सेवाओं में लेटरल एंट्री की शुरुआत की गई। यह प्रशंसनीय कदम हैं, परंतु शासन में उत्पन्न खामियों को दूर करने हेतु लेटरल एंट्री कोई अंतिम विकल्प नहीं है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा से चुने हुए अधिकारियों की देश में प्रतिष्ठा है। विडंबना है कि यह महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित समूह आज अभिजात्य और यथास्थिति को बनाए रखने वाले ऐसे नौकरशाहों में परिवर्तित हो गया है, जो वास्तविकता के संपर्क से दूर, अपने विशेषाधिकारों और सामाजिक स्थिति में बढ़ोतरी करने में लगा हुआ है। यह वर्ग दृढ़ता से खड़े होने की शक्ति खो चुका है। प्रशासनिक सेवाओं में भ्रष्टाचार जिस प्रकार से रच-बस गया है, उसे देखते हुए सरकार को भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेंस नीति अपनाने की जरूरत है। समय समय पर किए गए विभिन्न अध्ययनों के अनुसार भ्रष्टाचार मानव की नैतिक दुर्बलता से इतना पैदा नहीं होता, जितना सिस्टम में उपस्थित उन अंतर्निहित प्रणालीगत कमजोरियों से होता है। ये कमजोरियां भ्रष्टाचार के अवसर पैदा करती हैं। इसलिए केवल प्रशासनिक सतर्कता से भ्रष्टाचार पर काबू पाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है जिसमें सार्वजनिक भागीदारी और प्रणालीगत आर्थिक एवं प्रशासनिक सुधार भी शामिल हों।

एक सुझाव यह है कि सार्वजनिक सेवाओं को लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंचाने के लिए जिला कलेक्टर को जिले की विकास योजनाएं लागू करने का एकमात्र जिम्मेदार बनाने के बजाय चयनित जनप्रतिनिधियों की समिति का सीईओ मात्र बनाया जाए, वैसे ही जैसे ग्राम पंचायत और ब्लाक स्तर पर लागू किया गया है। यदि हमें नए भारत का सपना साकार करना है तथा सबको न्याय व विकास का लाभ देना है तो उच्च प्रशासनिक सेवाओं में प्रशिक्षण व नियुक्ति में सुधार की दृष्टि से अलघ समिति की सिफारिशों पर गौर करने की जरूरत है। **(कैलाश बिश्नोई)**

खरी-खरी

मुर्गों की हर्ट फीलिंग

रेखा शाह आरबी

सावन खत्म होते ही धरती के सारे मुर्गों में भय का माहौल व्याप्त हो गया। सब अपनी जान की सलामती को लेकर परेशान थे। मुर्गों की सलामती को लेकर कैसे कोई आस बंधाई जाए, यहां तो आधी आबादी डरी-सहमी रहती है। पता नहीं कब, कहां से, कौन भेड़िया निकल आए। कब, कौन उनकी इज्जत तार तार कर दे। सोचने की बात है, जहां आधी आबादी डरी-सहमी रहती है, वहां पर इनकी परेशानी कौन देखेगा। जिस मनुष्य की नजर में मनुष्य की ही कीमत नहीं है, उसके नजर में भला मुर्गों की क्या कीमत होगी!

मुर्गे ऊहापोह में थे कि कल कौन रहेगा और कौन परलोक का वासी होगा। सारे मुर्गे-मुर्गियां ईश्वर से गुहार लगा रहे थे। सगे संबंधियों से मिलकर उन्हें अंतिम विदाई दे रहे थे, कह रहे थे- भाई, यदि कल जिंदा रहे तो साथ में दाना चरने चलेंगे।

दरअसल मुर्गे-मुर्गियों को पता नहीं था, इंसानों से तो ऊपर वाला भी परेशान हो चुका है।

इधर मुर्गों की जान का मसला था, जिसमें इंसान मसाला मिलाकर चटकारे लेने वाला था। इंसान तो इंसान है। उसे दूसरे की परेशानियों से क्या लेना-देना। वह चटकारे लेने के साथ-साथ मुर्गों पर जोक भी बनाकर उनका मजाक बना रहे थे। अब यह क्या बात हुई, एक तो जान भी ले रहे हो, दूसरे मजाक भी बना रहे हो। इस बात ने मुर्गों और मुर्गियों की फीलिंग को हर्ट कर दिया। बस यहीं पर बात बिगड़ गई, वरना वह सब चुपचाप कढ़ाई में जाने को तैयार थे। मुर्गे और मुर्गियां इंसानों को भला बुरा कहने लगे।

लेकिन मुर्गों-मुर्गियों के हर्ट होने से क्या होता है। जब तक आप पावरफुल नहीं हैं, तब तक आप देश में किसी को अपनी बात सुनाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। हां, आपकी बात सुनी जा सकती थी, यदि आप इंसानों की थाली में परोसे जाने के समय अपना स्वाद बदल पाते। तो शायद उन्हें कुछ फर्क पड़ता। लेकिन यदि आप कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है, तो अपनी फिलिंग्स अपने पास रखिए। जैसे जनता बर्दाश्त करना सीख रही है, आप भी सीखिए। तमाम शिकायतें और फिलिंग्स हर्ट होने के बावजूद जनता नेता से शिकायत नहीं करते हैं, वैसे ही आप भी रहिए।

पोस्ट

उम्मीद है कि जल्द ही हमें यह जानने का मौका मिलेगा कि तृणमूल कांग्रेस के लिए डा. संदीप घोष इतने विशेष क्यों हैं?
शिव अरूर@ShivAroor

बुलडोजर अपराध की सजा नहीं है। वह सजा तो कोर्ट देगा। बुलडोजर तो सिर्फ अवैध निर्माण, सरकारी भूमि पर कब्जा, बिना नक्शे के भवन बनाने जैसे मामलों में चलता है।
डा. ऋचा सिंह लोधी@doctorrichabjp

पीएम मोदी का यूक्रेन पहुंचना दुनिया की सबसे बड़ी हेडलाइंस में से एक है। इसकी वजह यह है कि पीएम मोदी मौजूदा वक्त में दुनिया के इकलौते ऐसे वैश्विक नेता हैं जिन पर रूस और यूक्रेन, दोनों ही यकीन कर सकते हैं।
अभिषेक उपाध्याय@upadhyayabhii

जिस हिसाब से बंटा हुआ यह देश है और जिस हिसाब के नागरिक भावना वाले हम लोग हैं और जैसा व्यवस्थित भ्रष्टाचार है, उस हिसाब से देश ने आजादी के बाद जितनी भी तरक्की की है, वह भी चमत्कार ही है अपने आप में।
सेलर@sailorsmoon

बिहार डायरी

सही हाथों तक लाभ पहुंचाने की योजना

सुनील राज
sunilraj@pat.jagran.com

किसी दौर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि दिल्ली से एक रुपया चलता है, मगर गांव तक पहुंचते हैं केवल 15 पैसे। लेकिन समय के साथ इस तरह की प्रक्रिया में बड़ा परिवर्तन हुआ है। आज सरकार केंद्र की हो या राज्य की, उसकी चिंता एक ही है कि देश या राज्य के जो आर्थिक रूप से कमजोर या हाशिये पर खड़े लोग हैं, यदि उनके लिए कोई योजना शुरू हो तो उसका पूरा लाभ उस व्यक्ति तक पहुंचे। बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने इस सोच में एक और अध्याय जोड़ दिया है। सरकारी सेवा और योजना का लाभ सही तरीके से सही लोगों तक पहुंचे, इसके लिए सरकार ने नागरिकों का परिवार आधारित सोशल रजिस्टर बनाने की बड़ी पहल की है।

इस योजना के दो उद्देश्य हैं। पहला, सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ जिन परिवारों को मिल रहा है, उसका कामन डेटा बनाना, ताकि बार-बार उस परिवार को किसी पुरानी या नई योजना का लाभ देने के लिए अलग से उसके सत्यापन की आवश्यकता न पड़े। दूसरा उद्देश्य है, यूनिफाइड सर्विस डिलीवरी प्लेटफार्म (बिहार-वन) का निर्माण करना। ताकि सरकारी सेवाओं या योजनाओं का लाभ लेने वाले एक पोर्टल पर जाकर देख सकें कि उनके लिए सरकार की कौन सी योजनाएं चल रही हैं और किस नई योजना की शुरुआत सरकार ने की है, जिसका लाभ वह ले सकता है। पोर्टल बनाने व इसे प्रभावी रूप से लागू करने के लिए सरकार ने 85.23 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।

वस्तुतः बिहार में लगभग साढ़े तेरह करोड़ की आबादी में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो सरकार संचालित योजनाओं और सेवाओं का लाभ लेते हैं। सरकार के स्तर पर जो योजनाएं चल रही हैं, उनमें बिहार छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, फसल सहायता योजना, बेरोजगारी भत्ता योजना, स्टूडेंट क्रेडिट योजना, विधवा पेंशन योजना, वृद्धजन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री साइकिल योजना समेत लगभग तीन सौ योजनाएं शामिल हैं, जिनसे लोग सीधे लाभ उठाते हैं। परंतु कितनी आबादी लाभ के दायरे में आती है, सरकार के पास इसका विस्तृत लेखा-जोखा नहीं है। लिहाजा बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी योजना का लाभ उठाने में सफल हो जाते हैं, जो वास्तव में इसके हकदार नहीं हैं। यही नहीं, जो योजना के पात्र लोग हैं, उन्हें सेवाओं और योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए उसके बारे में जानकारी जुटानी होती है और फिर विभागों से लेकर अधिकारियों-कर्मचारियों की परिक्रमा भी करनी होती है। क्योंकि विभागों के स्तर पर अलग-अलग योजनाएं संचालित हैं और लाभ लेने के लिए संबंधित विभागों में ही आवेदन समेत अन्य प्रक्रिया पूरी करनी होती है।

प्रदेश में सरकारी योजनाओं का लाभ सभी तक सुसंगत रूप से पहुंचाने में जुटे नीतीश कुमार। फाइल

गरीब, पिछड़ों के साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को अपना अधिकार प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो, अधिकारियों-कर्मचारियों के उसे चक्कर न लगाने पड़े, इससे मुक्ति के लिए नीतीश कुमार ने परिवार आधारित सोशल रजिस्टर की परिकल्पना की और उसे लागू भी किया। इसके तहत यूनिफाइड सर्विस डिलीवरी प्लेटफार्म (बिहार-वन) पोर्टल विकसित किया जाएगा। इस पोर्टल पर सरकार के सभी विभागों द्वारा दी जा रही सेवाओं, योजना का पूरा विवरण होगा। इस पोर्टल पर सभी योजनाओं का एकीकृत आवेदन केंद्र भी होगा। जिस पर पात्र लाभार्थी जाकर योजना का लाभ उठा सकेंगे। इसमें नागरिकों का प्रोफाइल एवं कामन दस्तावेज सहित अन्य जानकारियां उपलब्ध रहेंगी। जिससे सरकार को उनके दस्तावेज सत्यापन में आसानी होगी और समय की बचत होगी। एक बार परिवार के सत्यापन के बाद उसे आधार की तरह एक यूनिक आइडी दी जाएगी, जो वर्चुअल होगी।

सरकार स्वयं मानती है कि यूनिफाइड सर्विस डिलीवरी प्लेटफार्म (बिहार-वन) बनने से सेवाओं और योजनाओं की पात्रता एक ही डैशबोर्ड पर रहेंगी, साथ ही सोशल रजिस्टर में निबंधित परिवारों का व्यापक और विश्वसनीय डाटा तैयार होगा। जिससे सभी लोक सेवाओं एवं लाभों को आम जन तक पहुंचाने में सफलता मिलेगी। डुप्लीकेट लाभार्थियों की पहचान हो सकेगी और उन्हें हटाकर सार्वजनिक धन की हानि रोकने में भी बड़ी सफलता मिलेगी।

इस मामले में जानने वाली बात यह है कि इस पोर्टल के माध्यम से न केवल सेवाओं-योजनाओं का लाभ दिया जाएगा, बल्कि परिवारों के कितने सदस्य सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, परिवारों का कितना विकास हुआ, इसकी भी जानकारी उपलब्ध रहेगी। ताकि सरकार को यह भी जानकारी मिल सके कि योजनाओं से संबंधित परिवार के जीवन स्तर में कितने बदलाव आए। बच्चों ने क्या प्रगति की, इसका भी रिकार्ड इसमें रखा जाएगा।

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या विधानसभा चुनाव बाद जम्मू-कश्मीर का राज्य दर्जा बहाल किया जाना चाहिए?

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या देश में सभी स्कूली बोर्डों का पाठ्यक्रम समान होना चाहिए?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

अब्दुल्ला के साथ है कांग्रेस का हाथ,
थ्री सेवेंटी पर चलो साफ हो गई बात।
साफ हो गई बात साफ है अब एजेंडा,
लाल चौक पर आय पाक फहराए झंडा!
फिर पत्थर, फिर बंद, फिर वही हल्ला-गुल्ला,
चाह रही कांग्रेस चाहते जो अब्दुल्ला!!
- ओमप्रकाश तिवारी

मंथन

शिक्षा-रोजगार तक समान पहुंच

आरक्षण व्यवस्था का उद्देश्य हाशिए पर रह रहे लोगों के लिए शिक्षा एवं रोजगार में समावेश के रास्ते बनाना था। इस बीच अनेक आर्थिक-सामाजिक बदलाव हुए हैं, जिन्हें समझना होगा

राहुल पांडेय
शोधार्थी, स्कूल आफ इंटरनेशनल स्टडीज, जेएनयू

उच्चतम न्यायालय ने इसी माह के आरंभ में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया, जिसमें राज्यों को अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के भीतर उप-वर्गीकरण बनाने की अनुमति मिली, ताकि उस समाज के सबसे पिछड़े वर्गों के लिए निश्चित उप-कोटा निर्धारित किया जा सके। सामाजिक न्याय की दिशा में यह निर्णय महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक बना, जिसने 2004 के उस फैसले को पलट दिया जो इस सूची को एक समरूप समूह मानता था। इससे आरक्षण के लिए सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है, जो भारत के बदलते सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को भी दर्शाता है।

वर्ष 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण नीतियों की शुरुआत ने भारत के विकासात्मक राज्य को काफी हद तक बदल दिया, जिससे ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला। इस बदलते परिदृश्य के लिए उच्च कौशल और ज्ञान की आवश्यकता है, जिसमें कई समुदाय अभी भी सुधार करने की स्थिति में नहीं हैं। लिहाजा आरक्षण प्रणाली के लिए नई चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं। ऐसे में सरकारी नौकरियों की घटती उपलब्धता और असंगत शैक्षिक व आरक्षण प्रणाली की प्रभावशीलता का नए सिरे से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में आय समर्थित कार्यक्रमों की ओर बढ़ने से ऐसे परिवारों के लिए पारंपरिक आरक्षण नीतियों की तुलना में ये अधिक मददगार साबित हो सकते हैं। विश्व के कई देशों में ऐसा देखा गया है। सशर्त नकद हस्तांतरण कार्यक्रम, जो स्कूल उपस्थिति और स्वास्थ्य जांच जैसी जरूरी गतिविधियों से जुड़े होते हैं, आर्थिक स्थिरता व मानव पूंजी विकास को बढ़ावा देने में प्रभावी साबित हुए हैं।

ब्राजील व मेक्सिको : यह कार्यक्रम विश्वभर में विशेषकर वैश्विक दक्षिण (ग्लोबल साउथ) में सामाजिक और आर्थिक गरीबी के उन्मूलन के लिए एक प्रभावी उपाय बन चुका है। ब्राजील में 'बोल्सा फेमीलिया कार्यक्रम' निम्न-आय वाले परिवारों को नकद भत्ता प्रदान करता है, बशर्ते उनके बच्चे स्कूल जाएं और नियमित स्वास्थ्य जांच कराएं। इससे यहां स्कूल में छात्रों की उपस्थिति में सुधार होने के साथ ही स्वास्थ्य संबंधी परिणाम भी बेहतर आए। इससे गरीबी के चक्र को तोड़ने में मदद मिली है। इसी तरह, मेक्सिको के 'प्रास्पेरा कार्यक्रम' ने गरीब परिवारों को अपने बच्चों को स्कूल में रखने और उन्हें चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया है। इस पहल में भाग लेने वाले परिवारों के बच्चों में उच्च शैक्षिक उपलब्धि और बेहतर स्वास्थ्य संकेतकों में योगदान दिया है। इन कार्यक्रमों का श्रेय गरीबी दर को कम करने, स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करने और स्कूल में नामांकन एवं उपस्थिति दर को बढ़ाने में दिया जाता है। इस तरह के कार्यक्रम की सफलता इसके व्यापक दृष्टिकोण में निहित है, जो वित्तीय सहायता को अनिवार्य स्कूल उपस्थिति एवं स्वास्थ्य देखभाल से जोड़ती है और दीर्घकालिक व स्थायी लाभ सुनिश्चित करती है।

गरीबी की दशा में सुधार : भारत में इन कार्यक्रमों के माध्यम से दो बड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। पहला, देश की मानव पूंजी और दूसरा, गरीबी की दशा में सुधार किया जा सकता है। भारत में आरक्षण प्रणाली का उद्देश्य ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों को शिक्षा और रोजगार के अवसर देना है। हालांकि इस प्रणाली ने कुछ सफलता अर्जित की है, लेकिन यह गरीबी और शैक्षिक असमानताओं के मूल कारणों को पूरी तरह से नहीं सुलझा पाई है। सशर्त नकद हस्तांतरण कार्यक्रम एक नया तरीका है जो गरीब परिवारों को प्रत्यक्ष मदद करने में सक्षम साबित हो सकता है। इस कार्यक्रम से जाति की परवाह किए बिना समाज के सबसे गरीब लोगों को लाभ मिल सकता है।

स्कूल में अनिवार्य उपस्थिति और शैक्षणिक प्रदर्शन को सुधार करके ये कार्यक्रम गरीब बच्चों के बीच स्कूल बीच में छोड़ने की दर को कम कर सकते हैं और उनकी शैक्षिक उपलब्धियों में सुधार कर सकते हैं। इससे एक अधिक शिक्षित मानव पूंजी का निर्माण होगा, जो आर्थिक विकास और रचनात्मकता को बढ़ावा देगा। भारत वर्तमान में शिक्षा प्रणाली से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, जैसे स्कूल छोड़ना, शिक्षा की खराब गुणवत्ता और ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की कमी। गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता देकर और शिक्षा को बढ़ावा देने वाले व्यवहारों को प्रोत्साहित करते हुए सशर्त नकद हस्तांतरण कार्यक्रम इन समस्याओं को सुलझाने का एक प्रमुख उपाय साबित हो सकता है। यह विभिन्न क्षेत्रों में संतुलित आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में सक्षम है, जो विकसित भारत के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

गरीब बच्चों को नियमित वित्तीय लाभ मिलने से स्वास्थ्य-शिक्षा पर वे ध्यान केंद्रित करते हैं। फाइल

****

राष्ट्रीय संस्करण
शनिवार 24 अगस्त, 2024
दैनिक जागरण
बिजनेस
www.jagran.com

सूचीबद्ध एसएमई के आडिट में ज्यादा सतर्क रहें सीए

मुंबई: मार्केट रेग्युलेटर सेबी के पूर्णकालिक सदस्य अश्विनी भाटिया ने शुक्रवार को कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) सूचीबद्ध लघु एवं मध्यम उद्योगों (एसएमई) के आडिट में ज्यादा सतर्कता बरतें। एक कार्यक्रम में भाटिया ने एसएमई प्लेटफार्म की प्रगति पर संतोष जताते हुए कहा कि अब तक यह कंपनियां 14 हजार करोड़ रुपये जुटा चुकी हैं। इसमें से छह हजार करोड़ रुपये पिछले वित्त वर्ष में जुटाए गए हैं। (प्रेट्र)

उपभोक्ताओं को सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कीटनाशकों का उपयोग घटाने के लिए राज्यों को अंतर-मंत्रालयी पैनल गठित करना चाहिए।
— जी कमला वर्धन राव, सीईओ, एफएसएसएआइ

सेंसेक्स	81,086.21	▲ 33.02
निफ्टी	24,823.15	▲ 11.65
सोना प्रति दस ग्राम	₹73,800	▼ ₹350
चांदी प्रति किलोग्राम	₹87,000	▼ ₹200
डालर	₹83.90	▼ ₹0.03
क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल	$78.00	

एक नजर में

विदेशी मुद्रा भंडार में 4.5 अरब डालर की वृद्धि

मुंबई: देश के विदेशी मुद्रा भंडार में बीते सप्ताह 4.546 अरब डालर की बढ़ोतरी हुई है। आरबीआइ के आंकड़ों के अनुसार, 16 अगस्त को समाप्त सप्ताह में कुल विदेशी मुद्रा भंडार 670.119 अरब डालर हो गया है। इस दौरान विदेशी मुद्रा आस्तियां 3.609 अरब डालर बढ़कर 591.569 अरब डालर हो गई हैं। स्वर्ण भंडार 86.5 करोड़ डालर बढ़कर 60.104 अरब डालर हो गया है। (प्रेट्र)

ई-कामर्स निर्यात हब के लिए मांगे प्रस्ताव

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने देश में ई-कामर्स निर्यात हब स्थापित करने के लिए प्रस्ताव मांगे हैं। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा कि इन निर्यात हब के संचालन के लिए प्रारूप तैयार कर लिया गया है। सरकार पूरे देश में 10-15 ई-कामर्स निर्यात हब बनाने की योजना बना रही है। (प्रेट्र)

बीते वर्ष ईपीएफओ से 1.09 करोड़ नए सदस्य जुड़े

नई दिल्ली: देश में औपचारिक क्षेत्र से जुड़ने वालों की संख्या बढ़ रही है। यही कारण है कि बीते वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 1.09 करोड़ नए सदस्य कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से जुड़े हैं। सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अनुसार, इस दौरान ईएसआइसी से जुड़ने वाले नए सदस्यों की संख्या 1.67 करोड़ और एनपीएस से जुड़ने वालों की संख्या 9,73,428 रही है। (एएनआइ)

4,250 करोड़ में बेची अंबुजा सीमेंट की 2.8% हिस्सेदारी

नई दिल्ली: अदाणी समूह के प्रमोटर ने शुक्रवार को अंबुजा सीमेंट में से अपनी 2.8 प्रतिशत हिस्सेदारी 4,250 करोड़ रुपये में बेच दी। यह हिस्सेदारी 625.50 रुपये प्रति शेयर के औसत मूल्य पर बेची गई है। राजीव जैन की कंपनी जीक्यूजी पार्टनर्स ने 1.78 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है और अब अंबुजा सीमेंट में इसकी कुल हिस्सेदारी बढ़कर 3.13 प्रतिशत हो गई है। (प्रेट्र)

ई-कामर्स नीति में देरी उपभोक्ताओं के हित में नहीं

आनलाइन खरीदारी को लेकर पांच वर्ष से तैयार मसौदे को अब तक नहीं दिया जा सका अंतिम रूप

राजीव कुमार, जागरण

नई दिल्ली: दो दिन पहले वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ई-कामर्स को लेकर जो चिंता जताई थी, वह उपभोक्ता और छोटे दुकानदार दोनों के हितों के लिए जायज थी। छोटे दुकानदार ई-कामर्स कंपनियों की गैर प्रतिस्पर्धात्मक रवैये से प्रभावित तो हो ही रहे हैं। कारोबार बढ़ने के साथ उपभोक्ताओं के साथ ई-कामर्स कंपनियों की ठगी भी बढ़ रही है। हालांकि, उपभोक्ता आफलाइन व्यापारियों के यहां भी ठगे जाते हैं। लेकिन अभी तक ई-कामर्स को लेकर कोई नीति नहीं बन पाई है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर वर्ष 2018 में ई-कामर्स कंपनियों के खिलाफ 95,270 शिकायतें आईं, जो वर्ष 2023 में बढ़कर 4.44 लाख हो गई है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने ई-कामर्स कंपनियों से अपनी एक लिखित संहिता तैयार करने के लिए कहा है, ताकि यह पता लग सके कि कंपनी में क्या मान्य है और क्या अमान्य?

ई-कामर्स नीति के अभाव में उत्पाद के फेक रिव्यू, उत्पाद की कमी दिखाकर दबाव पैदा करना, उत्पाद की सही जानकारी नहीं देना, सामान लौटाने में आनाकानी करना जैसी हरकतों से उपभोक्ता प्रभावित हो रहे हैं तो सस्ते दाम पर सामान बेचकर ई-कामर्स प्लेटफार्म चलाने वाली कंपनियों की गैर-पेशेवर हरकतों से छोटे दुकानदारों की दुकानदारी खराब हो रही हैं। लेकिन ई-कामर्स कंपनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि अभी हमारे देश में नियम नहीं है। कोई नीति नहीं है। सामान पसंद नहीं आने पर ई-कामर्स कंपनियां सामान लौटा लेती हैं, लेकिन आप यह जानकार हैरान रह जाएंगे कि अभी कानूनी रूप से ये कंपनियां सामान लौटाने के लिए बाध्य नहीं है। पहल इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2024 में देश के कुल खुदरा कारोबार में ई-कामर्स की हिस्सेदारी 10.4 प्रतिशत हो जाएगी और वर्ष 2030 तक देश में ई-कामर्स का आकार 350 अरब डालर तक पहुंच जाएगा। ऐसे में पिछले चार साल से 27 प्रतिशत की दर से बढ़ने वाले ई-कामर्स के लिए लिखित कानून का होना बहुत जरूरी है।

नियम बनाने को लेकर बंटे मंत्रालय

ई-कामर्स से जुड़े नियमों को लेकर मंत्रालय लगातार एक-दूसरे के पाले में गेंद डालने की कोशिश करते रहते हैं। वर्ष 2015-16 में आनलाइन मोबाइल फोन की खरीदारी का चलन तेजी से बढ़ा और तब यह शिकायत आने लगी कि कंपनियां फोन की जगह ईंट-पत्थर भेज रही हैं। मामला सरकार के सामने पहुंचा तो शुरू में कहा गया कि उपभोक्ता मंत्रालय ई-कामर्स नियम देखेगा। जब उपभोक्ता के साथ खुदरा व्यापारी बिग बिलियन जैसी सेल के खिलाफ आवाज उठाने लगे तो तय हुआ कि ई-कामर्स व्यापार से जुड़ा है, इसलिए वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ई-कामर्स नीति को तैयार करेगा।

- उपभोक्ता हेल्पलाइन पर ई-कामर्स कंपनियों के खिलाफ शिकायतों की संख्या चार लाख के पार
- लोकसभा चुनाव से पहले वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री व अधिकारियों ने नीति तैयार होने की बात कही थी
- अभी कानूनी रूप से बेचा जा चुका सामान वापस लेने के लिए बाध्य नहीं हैं ई-कामर्स कंपनियां

2019 में जारी हुआ था मसौदा

2019 में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआइआइटी) ने नेशनल ई-कामर्स नीति के लिए मसौदा जारी किया। इसमें ई-कामर्स मार्केटप्लेस, नियामक संबंधी मामले, इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास, डाटा विकास व सुरक्षा, घरेलू डिजिटल कारोबार जैसे मुद्दों को शामिल किया गया था। लेकिन उस ड्राफ्ट को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। इसके बाद ई-कामर्स नीति पर एक नेशनल फ्रेमवर्क बनाने की कवायद शुरू हुई। इस साल लोकसभा चुनाव से पहले विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं वाणिज्य व उद्योग मंत्री सभी की तरफ से यह बताया गया था कि ई-कामर्स नीति तैयार है। छोटे कारोबारियों से लेकर उपभोक्ता तक को इस नीति का इंतजार है।

एफडीआइ नियमों का पालन नहीं कर रहे आनलाइन विक्रेता

- केंद्रीय मंत्री ने ई-कामर्स कंपनियों को लेकर फिर जताई चिंता
- कहा- इनको केवल बिजनेस-टू-बिजनेस लेनदेन की अनुमति

मुंबई, प्रेट्र: एमेजोन जैसी ई-कामर्स कंपनियों को लेकर एक बार फिर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि आनलाइन खुदरा विक्रेताओं ने देश के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) नियमों का पूरी तरह से पालन नहीं किया है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को सोचना चाहिए कि उनकी खरीद से किसे लाभ होता है और उन्होंने जो बहस शुरू की है, उससे सबक लेना चाहिए।

एक कार्यक्रम के बाद बातचीत में गोयल ने कहा कि भारतीय कानून यह निर्धारित करते हैं कि देश में विदेशी ई-कामर्स कंपनियां केवल बिजनेस-टू-बिजनेस लेनदेन कर सकती हैं। लेकिन यह दुख की बात है कि नियमों का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया। यह छोटे और खुदरा विक्रेताओं के हितों के लिए हानिकारक है। उन्होंने कहा कि एमेजोन जैसी कंपनियों की गहरी जेबें कम मूल्य निर्धारण में मदद करती हैं। यह कंपनियां उपभोक्ता की पसंद और वरीयताओं को प्रभावित करने के लिए एल्गोरिदम का उपयोग भी करती हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित देशों की तरह छोटी दुकानों के गायब होने जैसी समस्याएं नहीं झेल सकता है। हालांकि, उन्होंने दोहराया कि सरकार देश में टेक्नोलाजी आने के पक्ष में है और हर वर्ग को अपने कारोबार को बढ़ाने का अधिकार है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने गत बुधवार को कहा था कि ई-कामर्स के बढ़ते दायरे से छोटे खुदरा व्यापारियों के प्रभावित होने की आशंका रहती है। उन्होंने संकेत दिया था कि यह सुनिश्चित करने की कोशिश होगी कि खुदरा व्यापारियों का नुकसान नहीं हो।

घरों का मूल्य बढ़ने में मुंबई दुनिया में दूसरे स्थान पर

नई दिल्ली, प्रेट्र: कैलेंडर वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही के दौरान दुनिया के 44 शहरों में घरों का मूल्य बढ़ने में मुंबई दूसरे और दिल्ली तीसरे स्थान पर रहा है। रियल एस्टेट कंसल्टेंट नाइट फ्रेंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, प्राइम और लक्जरी आवासीय संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का इसमें प्रमुख योगदान रहा है।

रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल-जून 2024 के दौरान 44 शहरों में घरों के मूल्य में वृद्धि घटकर 2.6 प्रतिशत रही है जो इसी वर्ष जनवरी-मार्च के दौरान 4.1 प्रतिशत थी। घरों के मूल्य में 26 प्रतिशत की वृद्धि के साथ मनीला पहले स्थान पर रहा है। मुंबई में प्राइम आवासीय संपत्तियों के मूल्य में 13 प्रतिशत की वृद्धि रही है। पिछले वर्ष समान अवधि में मुंबई इस सूची में छठे स्थान पर था। दिल्ली में घरों के मूल्य में 10.6 प्रतिशत की वृद्धि रही है और यह पिछले वर्ष समान अवधि में 26वें स्थान पर था।

अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती का समय आया : जेरोम पावेल

जेरोम पावेल

न्यूयार्क, रायटर: अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल ने शुक्रवार को कहा कि ब्याज दरों में कटौती का समय आ गया है। इसका कारण यह है कि रोजगार बाजार में जोखिम बढ़ रहा है और महंगाई फेडरल रिजर्व के लक्ष्य दो प्रतिशत तक पहुंच गई है। यह दोनों संकेत नीति में ढील देने का स्पष्ट समर्थन करते हैं। पावेल के इस बयान के बाद अमेरिका में सितंबर में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद बढ़ गई है। इसका असर इस वर्ष के अंत तक भारत में भी दिख सकता है।

जैक्सन होल में कंसास सिटी फेड के वार्षिक आर्थिक सम्मेलन में पावेल ने कहा कि महंगाई के बढ़ने का जोखिम कम हो गया है और रोजगार के अवसरों में कमी का जोखिम बढ़ गया है। ऐसे में ब्याज दरों को समायोजित करने का समय आ गया है। हालांकि, उन्होंने कहा कि दर में कटौती का समय और मात्रा आने वाले डाटा, उभरते परिदृश्य और जोखिमों के संतुलन पर निर्भर करेगी। अमेरिकी संसद की ओर से फेडरल रिजर्व को दिए गए दो लक्ष्यों के बारे में बोलते हुए पावेल ने भरोसा जताया कि महंगाई दो प्रतिशत के टिकाऊ स्तर पर वापस आ गई है। कोरोना महामारी के दौरान यह करीब सात प्रतिशत तक पहुंच गई थी।

पावेल ने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में बेरोजगारी दर में लगभग एक प्रतिशत की वृद्धि मुख्य रूप से श्रम आपूर्ति में वृद्धि और धीमी भर्ती के कारण हुई है, न कि छंटनी बढ़ने के कारण।

पहली छमाही में अमेरिका को सबसे ज्यादा निर्यात

नई दिल्ली, प्रेट्र: कैलेंडर वर्ष 2024 की पहली छमाही के दौरान भारत ने अमेरिका को सबसे ज्यादा निर्यात किया है। इस दौरान चीन के साथ देश का व्यापार घाटा सबसे ज्यादा रहा है।

आर्थिक थिंक टैंक जीटीआरआइ के अनुसार, इस वर्ष जनवरी से जून के दौरान अमेरिका को कुल निर्यात 10.5 प्रतिशत बढ़कर 41.6 अरब डालर रहा है। जनवरी-जून 2023 के दौरान अमेरिका को भारत का निर्यात 37.7 अरब डालर रहा था। जीटीआरआइ के अनुसार, 2024 की पहली छमाही में भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा 41.6 अरब डालर रहा है। इस दौरान भारत ने चीन को केवल 8.5 अरब डालर का निर्यात किया है जबकि आयात 50.1 अरब डालर रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान चीन भारत का सबसे बड़ा कारोबारी भागीदार रहा था। लेकिन जनवरी-जून 2024 के दौरान 62.5 अरब डालर के द्विपक्षीय कारोबार के साथ अमेरिका भारत का सबसे बड़ा भागीदार बन गया है।

अनिल अंबानी पर लगा पांच वर्ष का प्रतिबंध

अनिल अंबानी

- रिलायंस होम फाइनेंस के फंड की हेरा-फेरी के मामले में सेबी ने की कार्रवाई
- अनिल अंबानी समेत 25 लोगों पर 27 करोड़ रुपये तक का जुर्माना भी लगाया गया

नई दिल्ली, प्रेट्र: कैपिटल मार्केट रेग्युलेटर सेबी ने उद्योगपति अनिल अंबानी और रिलायंस होम फाइनेंस के पूर्व अधिकारियों समेत कुल 25 लोगों को शेयर बाजारों से पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। इन लोगों पर रिलायंस होम फाइनेंस के फंड की हेरा-फेरी करने के मामले में प्रतिबंध लगाया गया है।

सेबी ने अनिल अंबानी पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है। साथ की किसी भी सूचीबद्ध कंपनी या सेबी के साथ पंजीकृत किसी भी इकाई में निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय पद (केएमपी) लेने से भी पांच साल के लिए रोका गया है। अनिल अंबानी से अलग 24 अन्य लोगों पर 21-27 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही रिलायंस होम फाइनेंस पर छह महीने का प्रतिबंध और छह लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस संबंध में अनिल अंबानी के रिलायंस समूह की कंपनी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। फंड की हेरा-फेरी संबंधी कई शिकायतों के बाद सेबी ने वित्त वर्ष 2018-19 की अवधि के लिए जांच की। सेबी ने जांच में पाया कि अनिल अंबानी ने रिलायंस होम फाइनेंस के केएमपी अमित बापना, रवींद्र सुधालकर और पिंकेश आर शाह की मदद से धन हड़पने के लिए एक योजना बनाई है, जिसमें उन्होंने खुद से जुड़ी संस्थाओं को कर्ज लेने वालों के रूप में प्रस्तुत किया। हालांकि, रिलायंस होम फाइनेंस के निदेशक मंडल ने इस तरह के कर्ज देने के तरीकों को रोकने और नियमित रूप से कारपोरेट कर्जों की समीक्षा करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए थे, लेकिन कंपनी के प्रबंधन ने इन आदेशों की अनदेखी की। सेबी ने 222 पेज के आदेश में कहा कि कंपनी प्रबंधन और प्रमोटर्स ने उन कंपनियों को सैकड़ों करोड़ की कर्ज स्वीकृति में लापरवाही बरती, जिनके पास बहुत कम या कोई संपत्ति, नकदी प्रवाह या राजस्व नहीं था।

रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर के शेयर 10 प्रतिशत तक लुढ़के

इस फैसले से अनिल अंबानी के समूह की कंपनियों के शेयरों में 10 प्रतिशत तक की गिरावट आई है। बीएसई में रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर के शेयर 10.07 प्रतिशत की गिरावट के साथ 211.70 रुपये पर बंद हुए। इसी तरह, रिलायंस होम फाइनेंस के शेयर पांच प्रतिशत गिरकर 4.46 रुपये और रिलायंस पावर के शेयर पांच प्रतिशत गिरकर 34.48 रुपये प्रति इकाई पर बंद हुए।

राष्ट्रीय फलक

न्यूज गैलरी

अग्निवीर भर्ती अभियान में शामिल हुए 25 हजार युवा

गुवाहाटी: असम के उदलगुरी जिले में एक सप्ताह तक चले अग्निवीर भर्ती अभियान में 25 हजार युवाओं ने भाग लिया। भारतीय सेना के अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि जूनियर कमीशन अधिकारियों के लिए भी भर्ती अभियान चलाया गया। इसमें सात पूर्वोत्तर राज्यों के उम्मीदवार शामिल हुए। यह अभियान 16 से 23 अगस्त तक उदलगुरी में चलाया गया। (आइएएनएस)

अगरतला में पूर्वोत्तर परिषद की बैठक स्थगित

अगरतला: पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) ने 31 अगस्त को शुरू होने वाला अपना दो दिवसीय पूर्ण सत्र स्थगित कर दिया है। इस दो दिनी कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर राज्यों के राज्यपालों व मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद थी। एनईसी ने कहा कि निर्धारित बैठक विषम परिस्थितियों के कारण स्थगित हुई है। (प्रेट्र)

महाराष्ट्र में अगले चार-पांच दिन भारी बारिश की चेतावनी

मुंबई: मौसम विभाग ने शुक्रवार को कहा कि मुंबई और महाराष्ट्र के कई अन्य हिस्सों में अगले चार से पांच दिनों में भारी बारिश होने की संभावना है। आइएमडी ने 24 अगस्त से कोंकण के पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगढ़ व रत्नागिरी जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा की भविष्यवाणी करते हुए आरेंज अलर्ट जारी किया है। (प्रेट्र)

तेलंगाना में महिला पत्रकारों ने दर्ज कराई शिकायत

हैदराबाद: महिला पत्रकार सरिता अवुला और विजया रेड्डी ने शुक्रवार को तेलंगाना राज्य महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आयोग से गुरुवार को मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के गृहनगर विकाराबाद जिले के कोंडारेड्डीपल्ले गांव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा उन पर हमला किए जाने की घटना के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया है। किसान कर्ज माफी पर ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महिला पत्रकारों पर हमला किया था। (प्रेट्र)

पंजाब में मुफ्त बस सेवा पर खर्च की भरपाई के लिए लगाए दो नए टैक्स

कैलाश नाथ • जागरण

> बसों मे महिलाओं के मुफ्त सफर से सरकार पर पड़ रहा 600 करोड़ का बोझ

चंडीगढ़: कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के बाद अब आम आदमी पार्टी के शासन वाले पंजाब में भी चुनाव जीतने के लिए मुफ्त में बांटी गई रेवड़ियों ने सरकार के मुंह स्वाद कड़वा कर दिया है। आप की दिल्ली सरकार के रास्ते पर चलते हुए पंजाब में तत्कालीन अमरिंदर सिंह सरकार ने सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी थी। सत्ता में आने के भगवंत मान सरकार ने इसके फायदे-नुकसान का आकलन करने के बजाय जारी रखने का फैसला लिया। अब यह योजना उसके गले की फांस बन गई है। इसे जारी रखने से प्रतिवर्ष 600 करोड़ रुपये का बोझ पड़ रहा है। इसके लिए उसने अतिरिक्त आय का साधन ढूंढा है। सरकार ने तीन दिन पहले पंजाब में पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाया है तथा नए वाहनों की खरीद पर लगने वाले मोटर व्हीकल टैक्स में 0.5 प्रतिशत से लेकर 2 प्रतिशत तक की वृद्धि कर दी है। अनुमान है कि इससे सरकार को 150 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

भगवंत मान। फाइल

आर्थिक तंगी का सामना कर रही पंजाब सरकार पर वर्तमान में 3.27 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है। इस कर्ज पर उसे 22,000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष ब्याज देना पड़ता है। कृषि के लिए किसानों को मुफ्त बिजली तथा घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट फ्री बिजली देने से लगभग 20,000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का बोझ उठाना पड़ रहा है। इन बड़ी वित्तीय चुनौतियों के बीच महिलाओं को मुफ्त बस सेवा ने ट्रांसपोर्ट विभाग की आय का बड़ा हिस्सा बंद करके उसका बजट बिगाड़ दिया है। भले ही सरकार मुफ्त यात्रा पर खर्च के बदले ट्रांसपोर्ट विभाग को सब्सिडी देती है परंतु इस भुगतान में लेट-लतीफी से ट्रांसपोर्ट विभाग रोजमर्रा के खर्चों में भी परेशानी झेल रहा है।

दो नए टैक्सों के अलावा सरकार मुफ्त बस सेवा में कटौती करने के लिए स्मार्ट कार्ड योजना लाने की भी योजना बना रही है। इस स्मार्ट कार्ड से मुफ्त सेवा को सीमित करने का प्रविधान किया जाएगा। अभी इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। वैसे तो ग्रीन टैक्स व मोटर व्हीकल टैक्स की दरों में वृद्धि करके सरकार ने लगभग 150 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय की व्यवस्था कर ली है, परंतु मुफ्त बस सेवा पर अब भी 450 करोड़ रुपये का अंतर कैसे पूरा होगा, यह प्रश्न अभी बाकी है।

'महिला पहलवानों की सुरक्षा वापस लेने का मुद्दा महज गलतफहमी'

जासं, नई दिल्ली: यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला पहलवानों की सुरक्षा हटाने के मुद्दे पर शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष कहा कि यह महज गलतफहमी थी और इसे सुधार लिया गया है। पुलिस ने यह जवाब भाजपा के पूर्व सांसद व भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के विरुद्ध यौन उत्पीड़न के मामले में तीन महिला पहलवानों के आवेदन पर दिया।

शुक्रवार को दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने स्पष्ट किया कि यह एक गलतफहमी थी। किसी महिला पहलवान की सुरक्षा नहीं हटाई गई थी। बृहस्पतिवार को पहलवानों के आवेदन पर अंतरिम आदेश पारित करते हुए एडिशनल चीफ मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने दिल्ली पुलिस को जवाब दाखिल करने को कहा था। तीनों महिला पहलवानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देशों के लिए तत्काल आवेदन दायर किया गया था, ताकि वे गवाही दे सकें।

इप्सोस इंडियाबस सर्वेक्षण में मोदी की लोकप्रियता बरकरार

> पीएम नरेन्द्र मोदी ने फिर हासिल की 70 प्रतिशत अप्रूवल रेटिंग

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी।

नई दिल्ली, आइएएनएस: इप्सोस इंडियाबस पीएम अप्रूवल रेटिंग सर्वे अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 70 प्रतिशत की प्रभावशाली रेटिंग हासिल की है। सर्वेक्षण में शामिल अधिकांश लोग प्रधानमंत्री के रूप में उनके प्रदर्शन से खुश हैं और उनको बेहतर नंबर दे रहे हैं। एजेंसी के सर्वेक्षण से यह स्पष्ट हो गया है कि गठबंधन सरकार के प्रमुख के रूप में पीएम मोदी की लोकप्रियता कम नहीं हुई है। इससे यह भी पता चलता है कि उनकी लोकप्रियता कुछ क्षेत्रों, विशेषकर उत्तरी भारत के राज्यों और टियर 1 शहरों में अभी भी अधिक है।

हालांकि, अभी भी मोदी 3.0 सरकार के प्रदर्शन का पूरी तरह से मूल्यांकन करना जल्दबाजी होगी, क्योंकि सरकार को सत्ता में आए केवल दो महीने हुए हैं। ऐसे में सर्वेक्षण इस बात पर प्रकाश डालता है कि इस सरकार को शिक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय रूप से उच्च रेटिंग प्राप्त हुई है। हालांकि, एजेंसी के अनुसार दक्षिण के राज्यों पीएम मोदी को कम रेटिंग मिली है। इस साल मई में एजेंसी ने अपने सर्वे में पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 70 प्रतिशत पाई थी, तब ज्यादातर उत्तरदाताओं का मानना था कि वह प्रधानमंत्री के रूप में सराहनीय काम कर रहे हैं। इप्सोस सर्वेक्षण (अगस्त) के निष्कर्षों को देखें तो, पीएम मोदी ने एक बार फिर अप्रूवल रेटिंग प्राप्त की है जो मई में दर्ज रेटिंग के बराबर है। दूसरे शब्दों में, यह हालिया सर्वेक्षण बताता है कि उनका समर्थन मजबूत था और अभी भी बना हुआ है।

इंदिरा की रिहाई के लिए विमान अगवा करने वाले भोला पांडेय नहीं रहे

जागरण संवाददाता, बलिया

भोला नाथ पांडेय (फाइल)

> वर्ष 1980 के विधानसभा चुनाव में द्वावा क्षेत्र से चुने गए थे विधायक

पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जेल से रिहाई के लिए गेंद को बम बताकर विमान को अगवा करने वाले 78 वर्षीय वरिष्ठ कांग्रेस नेता डा.भोला नाथ पांडेय का शुक्रवार को लखनऊ स्थित आवास पर निधन हो गया। मून छपरा गांव के निवासी पांडेय लंबे समय से बीमार थे। वह वर्ष 1980 में द्वाबा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस से विधायक चुने गए थे।

जब जनता पार्टी की सरकार बनी तब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री और चौधरी चरण सिंह केंद्रीय गृह मंत्री बने। उनके निर्देश पर इंदिरा गांधी को अक्टूबर, 1977 में गिरफ्तार किया गया था। कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष अवध बिहारी चौबे ने बताया कि 20 दिसंबर, 1978 को लखनऊ एयरपोर्ट से आइसी-410 विमान ने जैसे ही दिल्ली के लिए उड़ान भरी विमान में बैठे डा.भोलानाथ पांडेय और उनके साथी देवेंद्र पांडेय ने पायलट के केबिन में घुसकर गेंद को बम बताकर कैप्टन एमएन बत्तीवाला को आतंकित किया और विमान नेपाल लेकर चलने को कहा। जब पायलट ने कहा कि विमान में इतना ईंधन नहीं है तो दोनों विमान को वाराणसी में लैंड कराने पर राजी हो गए।

चीनी मूल्यों की समीक्षा करेगी सरकार

नई दिल्ली, प्रेट्र: केंद्र सरकार चीनी का मूल्य तय करने वाले छह दशक पुराने नियमों की समीक्षा करने की योजना बना रही है। इसके अलावा चीनी उत्पादन और इसके भंडारण संबंधी नियमों की समीक्षा भी की जाएगी। इस संबंध में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने चीनी नियंत्रण आदेश 2024 का मसौदा जारी किया है। मंत्रालय ने मसौदा जारी करते हुए कहा कि चीनी क्षेत्र में कई बदलाव हुए हैं। इस कारण मौजूदा चीनी (नियंत्रण) आदेश, 1966 में सुधार की आवश्यकता है। मसौदे में सरकार को चीनी के उत्पादन को विनियमित करने के साथ-साथ उत्पादकों और डीलरों द्वारा इसकी बिक्री, भंडारण और निपटान को प्रतिबंधित करने की शक्ति प्रदान की गई है। मंत्रालय ने मसौदे पर 23 सितंबर तक हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित की हैं।

'रेलवे ट्रैक की रात्रि गश्त अनिवार्य की जाए'

> अभी मैनुअल में नहीं है अनिवार्य रात्रि गश्त का प्रविधान
>
> सिर्फ बेहद खराब मौसम में की जाती है ट्रैक की रात्रि गश्त

नई दिल्ली, प्रेट्र: कानपुर के नजदीक ट्रैक पर रखे रेल पटरियों के टुकड़ों से टकराकर साबरमती एक्सप्रेस के बेपटरी होने के बाद रेलवे ने ट्रैक की गश्त बढ़ा दी है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि रेलवे ट्रैक की रात्रि गश्त को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।

रेलवे बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि आरपीएफ के साथ-साथ ट्रैक मेंटेनर पूरे वर्ष नियमित अंतराल पर दिन में और रात में गश्त करते हैं और साबरमती एक्सप्रेस दुर्घटना के बाद वे और अधिक सतर्क हो गए हैं। लेकिन ट्रैक मेंटेनर्स और डिवीजनल रेलवे के अधिकारियों से मिले फीडबैक के आधार पर तैयार ग्राउंड रिपोर्ट बताती है कि पूरे वर्ष ट्रैक की रात्रि गश्त नहीं की जाती क्योंकि इंडियन रेलवे परमानेंट वे मैनुअल में इसका प्रविधान नहीं है और ट्रैक का रखरखाव करने वाले पर्याप्त कर्मचारियों की भी कमी है। नार्थ सेंट्रल जोन के एक अधिकारी ने बताया कि साबरमती एक्सप्रेस दुर्घटना से पहले रात्रि गश्त नियमित आधार पर नहीं की जाती थी क्योंकि रात्रि गश्त का प्रविधान बेहद खराब मौसम के दौरान रेल ट्रैक के रखरखाव के उद्देश्य से किया गया है, न कि असामाजिक गतिविधियों से सुरक्षित करने के उद्देश्य से। रेलवे जोन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि रेल संपत्तियों की संरक्षा एवं सुरक्षा आरपीएफ का दायित्व है, लेकिन वे दिन या रात में ट्रैक की आकस्मिक या नियमित गश्त नहीं करते। उपद्रवी तत्वों से पटरियों की सुरक्षा के सवाल पर विशेषज्ञों के एक वर्ग का मानना है कि सामान्य मौसम की स्थिति में भी पूरे वर्ष समूचे रेल नेटवर्क पर ट्रैक मेंटेनर्स के साथ-साथ आरपीएफ द्वारा रात्रि गश्त को अनिवार्य बना दिया जाना चाहिए, जब तक रेलवे बोर्ड कोई तकनीक आधारित हल नहीं तलाश लेता।

आल इंडिया ट्रैक मेंटेनर्स यूनियन (एआइआरटीयू) के कार्यकारी अध्यक्ष चांद मोहम्मद ने आरोप लगाया कि 15 से 30 प्रतिशत ट्रैक मेंटेनर्स को रेल अधिकारियों ने अपने निजी कामों में लगा रखा है जिससे बाकी ट्रैक मेंटेनर्स पर काम का बोझ बढ़ गया है। उन ट्रैक मेंटेनर्स को रात्रि गश्त में लगाया जा सकता है। नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन रेलवेमेन के महासचिव एम. राघवैया ने कहा कि नए रेलवे ट्रैक तो बिछाये जा रहे हैं, लेकिन वित्त मंत्रालय के प्रतिबंध के कारण नए पद सृजित नहीं किए जा रहे।

****

180 देशों में म्यांमार 171वें स्थान पर है 2024 के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। फ्रांस स्थित समूह रिपोर्टर्स विदाउट बार्डर्स के अनुसार, म्यांमार पत्रकारों को जेल भेजने में आगे है।

मोदी ने जेलेंस्की को सौंपे चार भीष्म क्यूब

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- युद्ध में घायल जनता के साथ ही सैनिकों को तत्काल मिलेगी चिकित्सा सहायता
- दोनों देशों में चार समझौते हुए, इनमें एक समझौता स्वास्थ्य व ड्रग्स को लेकर

युद्धग्रस्त यूक्रेन को भारत ने शुक्रवार को वह दिया, जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। यह चीज है कि आपातकाल में इस्तेमाल होने वाली चिकित्सा सामग्रियों का किट। इस किट को भारत ने खास तौर पर विकासशील देशों को चिकित्सा क्षेत्र में मदद देने के लिए शुरू किए गए प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री के तहत तैयार किया है और इसका नाम भीष्म रखा गया है। इसके तहत दवाइयों, मरहम-पट्टी, इंजेक्शन आदि का एक छोटा 15 इंच का चिकित्सा पैकेट होता है। इस तरह के 36 छोटे चिकित्सा पैकेटों को मिलाकर एक मदर क्यूब बनाया जाता है और दो मदर क्यूब को मिलाकर एक भीष्म क्यूब बनाया जाता है। यह एक छोटा पोर्टेबल अस्पताल है, जिसे किसी आपदाग्रस्त इलाके में तत्काल पहुंचाया जा सकता है और मरीजों का इलाज शुरू किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को इस तरह के चार भीष्म क्यूब सौंपे। इनका उपयोग युद्ध में घायल आम जनता के साथ ही सैनिकों को तत्काल चिकित्सा सहायता पहुंचाने में किया जा सकता है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसके लिए भारत को धन्यवाद दिया है।

बाद में जब पीएम मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, उसमें भी चिकित्सा व मेडिकल क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ाने को लेकर बात

कीव में शुक्रवार को भीष्म क्यूब का प्रस्तुतिकरण किए जाने के दौरान पीएम नरेन्द्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की। प्रेट्र

हुई है। दोनों देशों के बीच चार समझौते हुए हैं, जिनमें एक समझौता स्वास्थ्य व ड्रग्स को लेकर है। इससे भारतीय दवाइयों व चिकित्सा उपकरणों को यूक्रेन निर्यात करने की राह आसान होगी। अन्य समझौते कृषि व खाद्य प्रसंस्करण, भारत की तरफ से सामुदायिक विकास के लिए यूक्रेन को अनुदान देने और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने को लेकर है। दोनों देशों के बीच आर्थिक व प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को लेकर भी सहमति बनी है। इस संबंध में भारत-यूक्रेन के बीच अंतर-सरकारी आयोग का गठन पहले ही हो चुका है और इसकी एक बैठक मार्च, 2024 में हुई थी। यह आयोग कारोबार, वाणिज्य, औद्योगिक, संस्कृति, विज्ञान व तकनीकी क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बनाने और उनको लागू करने का काम करता है। इसकी अगली बैठक इस साल के अंत तक होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी बताया कि दोनों नेताओं के बीच हुई बैठक में आपसी सहयोग से जुड़े मुद्दों के अलावा रूस से तेल खरीद का मुद्दा भी उठा।

यूक्रेन की संप्रभुता का समर्थन करता है भारत : जेलेंस्की

कीव, प्रेट्र : यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने शुक्रवार को कहा कि भारत उनके देश की राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नई दिल्ली का समर्थन उनके देश के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया में हर किसी को संयुक्त राष्ट्र चार्टर का समान रूप से सम्मान करना चाहिए।

- मोदी ने कहा-हम महात्मा गांधी की भूमि से आए हैं, जिन्होंने शांति का संदेश दिया था

मोदी के साथ बातचीत के बाद जेलेंस्की ने एक्स पर लिखा, आज इतिहास लिखा गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हमारे देश की स्वतंत्रता के बाद पहली बार यूक्रेन का दौरा किया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के बाद हम रणनीतिक साझेदारी, द्विपक्षीय व्यापार और निरंतर सैन्य-तकनीकी सहयोग के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक संयुक्त वक्तव्य पर भी सहमत हुए।

मोदी ने बातचीत के दौरान अपने आरंभिक वक्तव्य में कहा कि हम महात्मा गांधी की भूमि से आए हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया था। प्रधानमंत्री ने देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया। मोदी ने जेलेंस्की को सितंबर 2022 में समरकंद और पिछले महीने मास्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ हुई अपनी बातचीत से भी अवगत कराया। मोदी ने कहा, कुछ समय पहले जब मैं समरकंद में राष्ट्रपति पुतिन से मिला था, तो मैंने उनसे कहा था कि यह युद्ध का युग नहीं है। पिछले महीने जब मैं रूस गया था, तो मैंने साफ शब्दों में कहा था कि किसी भी समस्या का समाधान युद्ध के मैदान में नहीं मिलता। बातचीत, संवाद और कूटनीति से समाधान निकलता है और हमें बिना समय बर्बाद किए उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। दोनों पक्षों को एक साथ बैठकर इस संकट से बाहर निकलने का तरीका खोजना चाहिए।

गले मिलना हमारी संस्कृति का हिस्सा : जयशंकर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

ऐतिहासिक यात्रा पर कीव पहुंचे पीएम नरेन्द्र मोदी ने वहां अपने कुछ घंटे के प्रवास के दौरान राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को दो बार गले लगाया। हालांकि पश्चिमी देशों की मीडिया को अब भी जुलाई, 2024 में अपनी मास्को यात्रा के दौरान पीएम मोदी का राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गले लगाना याद था। मोदी की कीव यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर से इस बारे में एक ब्रिटिश पत्रकार ने बहुत ही चुभता हुआ सवाल पूछा कि पीएम मोदी का पुतिन को गले लगाना कई लोगों को पसंद नहीं आया है। इस पर आप क्या कहेंगे? जयशंकर का जबाव था कि दुनिया के जिस हिस्से से मैं आता हूं, वहां जब दो व्यक्ति मिलते हैं, तो वे एक-दूसरे का ऐसे ही अभिवादन करते हैं। यह हो सकता है कि आपकी संस्कृति का हिस्सा नहीं हो लेकिन हमारी संस्कृति में ऐसा होता है। आज पीएम ने राष्ट्रपति को भी लगे लगाया है और मैंने दूसरे वैश्विक नेताओं को भी लगे लगाते देखा है। मुझे लगता है कि यह सांस्कृतिक अंतर है, जो आप देख रहे हैं।

मोदी-पुतिन के गले मिलने पर ब्रिटिश पत्रकार के सवाल का विदेश मंत्री ने दिया जवाब

45 दिन... दो मुलाकातें... एक उम्मीद

वोलोदिमीर जेलेंस्की से गले मिलते पीएम नरेन्द्र मोदी ● एपी

व्लादिमीर पुतिन से गले मिलते भारत के प्रधानमंत्री ● प्रेट्र

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले 45 दिनों के भीतर दुनिया के दो ऐसे देशों के नेताओं से मुलाकात की है, जो एक दूसरे से युद्ध लड़ रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से पीएम मोदी की मुलाकात नौ जुलाई को मास्को में हुई। पीएम मोदी 22वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए रूस के दौरे पर थे। शुक्रवार को पीएम मोदी ने कीव में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की है। दोनों नेताओं से पीएम मोदी की मुलाकात पर दुनिया की टकटकी इसलिए भी लगी रही क्योंकि सभी इस जंग से प्रत्यक्ष, परोक्ष रूप से प्रभावित हैं और शांति चाहते हैं। नरेन्द्र मोदी को ऐसे नेता के रूप में देखा जा रहा है, जो रूस और यूक्रेन को संघर्ष का रास्ता छोड़ कर बातचीत के जरिये समाधान खोजने पर सहमत कर सकते हैं। पीएम मोदी व्लादिमीर पुतिन से कह चुके हैं कि यह युद्ध का समय नहीं है। वहीं, भारत ने यूक्रेन को मानवीय मदद पहुंचा कर साफ संदेश दिया है कि वह शांति और मानवता के साथ है।

हसीना का डिप्लोमैटिक पासपोर्ट रद

मुसीबत ▶ हसीना सरकार के पूर्व मंत्रियों व अफसरों के भी पासपोर्ट रद

रिपोर्ट में कहा, पूर्व पीएम का भारत में प्रवास अब अवैध

ढाका, प्रेट्र : बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शुक्रवार को अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना का डिप्लोमैटिक पासपोर्ट रद कर दिया। हसीना मंत्रिमंडल में शामिल रहे अन्य लोगों के पासपोर्ट भी सरकार ने रद कर दिए हैं। पांच अगस्त को पद और देश छोड़ने के बाद से हसीना भारत में हैं। शुक्रवार तक बांग्लादेश में हसीना के खिलाफ 51 आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं जिनमें से 42 मामले हत्या के हैं।

बांग्लादेश के गृह मंत्रालय के सिक्युरिटी सर्विसेज डिवीजन द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री के सलाहकारों, पूर्व कैबिनेट मंत्रियों, भंग की गई संसद के सदस्यों और उनके जीवनसाथियों के डिप्लोमैटिक व अन्य पासपोर्ट तत्काल प्रभाव से रद कर दिए गए हैं। पूर्व सरकार में प्रमुख पदों पर रहे अधिकारियों के डिप्लोमैटिक पासपोर्ट भी रद कर दिए गए हैं। पांच अगस्त को शेख हसीना के इस्तीफे और देश छोड़ने के बाद राष्ट्रपति मुहम्मद शहाबुद्दीन ने देश की 12 वीं संसद को भंग कर दिया था और मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार गठित कर दी थी। जिन लोगों के डिप्लोमैटिक पासपोर्ट रद हुए हैं उनके लिए आर्डिनरी (सामान्य) पासपोर्ट अब तभी जारी किए जाएंगे जब कम से कम दो जांच एजेंसियां आवेदक के बार में सकारात्मक रिपोर्ट देंगी।

डेली स्टार अखबार के अनुसार भारतीय वीजा नीति में डिप्लोमैटिक या आफीशियल पासपोर्ट धारक बांग्लादेशी नागरिकों के लिए भारत में वीजा फ्री प्रवेश की सुविधा है। ऐसे बांग्लादेशी भारत में जाकर वहां 45 दिनों तक रह सकते हैं। अखबार के अनुसार पांच अगस्त को भारत पहुंचीं हसीना की भारत में रहने की यह अवधि अभी पूरी नहीं हुई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि शेख हसीना अब पासपोर्ट धारक नहीं हैं। इसलिए कोई पासपोर्ट या वीजा न होने की वजह से भारत में उनका प्रवास अवैध है और उन पर बांग्लादेश को प्रत्यर्पित किए जाने की तलवार लटक रही है।

शेख हसीना। फाइल

बांग्लादेश के स्टार क्रिकेटर शाकिब पर हत्या का केस : बांग्लादेश में क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी शाकिब अल हसन पर भी हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया है। शाकिब के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है उससे संबंधित घटना इस महीने की शुरुआत में हिंसक आंदोलन के दौरान हुई। 37 वर्षीय शाकिब बांग्लादेश की क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके हैं। वह शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग की टिकट पर चुनाव जीतकर सांसद भी रह चुके हैं।

बांग्लादेश के बिगड़ते अंदरूनी हालात ने भारत की बढ़ाई चिंता

जयप्रकाश रंजन ● जागरण

- अभी तक पड़ोसी देश के अधिकांश क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब
- राजनीतिक अस्थिरता के माहौल में भारत के खिलाफ अफवाहों को मिल रही हवा

नई दिल्ली : बांग्लादेश का इतिहास गवाह है कि जब भी वहां गैर-अवामी लीग सरकार (सैन्य या लोकतांत्रिक) सत्ता में होती है तो भारत विरोधी गतिविधियां बढ़ जाती हैं। अब जबकि पूर्व पीएम शेख हसीना को सत्ता छोड़े 18 दिनों से ज्यादा हो गए हैं और मुहम्मद यूनुस की अगुआई में अंतरिम सरकार के गठन को भी तकरीबन दो सप्ताह होने जा रहे हैं, भारत को यह चिंता सताने लगी है कि पड़ोसी देश में फिर से भारत विरोधी ताकतों को हवा मिल सकती है। भारत सिर्फ इस बात से चिंतित नहीं है कि बांग्लादेश में उसके खिलाफ अफवाहों को हथियार बनाया जा रहा है, बल्कि जिस तरह से वहां के अधिकांश हिस्सों में कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी हुई है, वह भी चिंता का बड़ा कारण है।

जो सूचनाएं भारत को मिली हैं, उसके मुताबिक पिछले दिनों अवामी लीग के नेताओं और मीडिया पर हुए भीड़ के हमले से बचाने को लेकर सेना के स्थानीय अधिकारियों ने कोई दिलचस्पी नहीं ली। सेना का साफ तौर पर कहना है कि कानून व्यवस्था की स्थिति पुलिस को ही संभालनी पड़ेगी। दूसरी तरफ स्थिति यह है कि अंतरिम सरकार की तरफ से बार-बार निर्देश जारी करने के बावजूद ढाका व कुछ शहरों के बाहर के अधिकांश पुलिस थाने खाली पड़े हुए हैं। भीड़ का निशाना बनने के डर से पुलिसकर्मी ड्यूटी पर नहीं आ रहे। इस स्थिति में भारतीय उच्चायोग को भी अपने कार्यालय व परिसंपत्तियों की चिंता है।

भारत के प्रमुख रणनीतिक विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी ने कहा है कि सेना समर्थित अंतरिम सरकार प्रतिशोध की भावना के तहत उठाए जाने वाले कदमों या दूसरे गलत कामों को तो नहीं रोक पाई है लेकिन राजनीतिक विरोधियों, पत्रकारों, स्थानीय अधिकारियों, अधिवक्ताओं और शिक्षाविदों को जेल में डाल रही है। अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने बांग्लादेश में मानवाधिकार उल्लंघन और अल्पसंख्यकों पर हमले को लेकर अमेरिका की चुप्पी पर भी सवाल उठाया है। इस बारे में अधिकारियों का कहना है कि पहले भी जब बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता होती है तो उसका खामियाजा सिर्फ भारत को ही भुगतना पड़ा है।

डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रत्याशी बनीं भारतवंशी कमला हैरिस

शिकागो कन्वेंशन में स्वीकार की पार्टी की औपचारिक उम्मीदवारी

शिकागो, प्रेट्र: अमेरिका में आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया गुरुवार को पूरी हो गई। शिकागो में चार दिवसीय डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन (डीएनसी) के अंतिम दिन भारतवंशी कमला हैरिस ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी औपचारिक रूप से स्वीकार की। अब पांच नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में उनका मुकाबला रिपब्लिकन प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप से होगा। इस अवसर पर जनता को आश्वस्त करते हुए कहा कि अगर वह अमेरिका की कमांडर-इन-चीफ चुनी गईं तो यह सुनिश्चित करेंगी कि देश के पास दुनिया की सबसे मजबूत व सबसे घातक लड़ाकू बल हो। इसके साथ ही उन्होंने गाजा युद्ध, यूक्रेन संघर्ष समेत विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए।

- ट्रंप के विरुद्ध चुनाव जीतीं तो अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति होंगी
- गाजा बंधकों की रिहाई व फलस्तीनियों के हित में युद्धविराम जरूरी बताया

अमेरिका के शिकागो में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के दौरान भारतवंशी कमला हैरिस। रायटर

कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी में राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी बनने वाली हिलेरी क्लिंटन के बाद दूसरी महिला बन गई हैं। हिलेरी चुनाव हार गई थीं, इस तरह कमला के पास इतिहास बनाने का मौका है। वह अगर चुनाव जीतती हैं तो अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति होंगी। नेशनल कन्वेंशन में गुरुवार को अपने संबोधन में कमला हैरिस ने आतंकवाद के विरुद्ध डटकर मुकाबला करने की बात कही। कहा, वह अगर चुनाव जीतती हैं तो ईरान और ईरान समर्थित आतंकियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेंगी। कहा, आतंकवाद के विरुद्ध इजरायल अपनी रक्षा करने में सक्षम हैं। इसके साथ ही उन्होंने गाजा में बंधकों की रिहाई व फलस्तीनियों को अमानवीय स्थिति से उबारने के लिए गाजा में शीघ्र युद्धविराम का समर्थन किया। कहा, राष्ट्रपति जो बाइडन इसके लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने यूक्रेन और नाटो सहयोगियों के साथ रहने का वादा किया।

मां को याद कर कहा-उन्होंने ही हमें सिखाया अन्याय के विरुद्ध लड़ना : इस अवसर पर अपने संबोधन में कमला हैरिस ने अपनी मां व उनकी शिक्षाओं को खासतौर पर याद किया। कमला ने कहा कि वह अपनी मां श्यामला गोपालन को हर दिन याद करती हैं। उन्होंने हमें सिखाया है कि अन्याय को लेकर कभी शिकायत मत करो, बल्कि इसे खत्म करने के लिए लड़ाई लड़ो। उन्होंने यह भी शिक्षा दी कि किसी को यह कहने का मौका मत दो कि तुम कौन हो, बल्कि उसे यह एहसास हो कि तुम कौन हो। मालूम हो कि उनकी मां भारत में पैदा हुई थीं, जो बाद में अमेरिका में बस गईं।

इस बीच, कुछ हिंदुओं ने मिलकर 'हिंदूज फार कमला हैरिस' नामक ग्रुप बनाकर कमला का समर्थन करने का संकल्प लिया। कहा, राष्ट्रपति के रूप में कमला भारत, अमेरिका और दुनिया के लिए अच्छी नेता साबित होंगी। ग्रुप ने कमला हैरिस के घर के पास उनके प्रति समर्थन जताते हुए हिंदुओं से वोट करने और चंदा देने की अपील की।

न्यूज गैलरी

ईरान ने आइएस के 14 आतंकियों को गिरफ्तार किया

तेहरान : ईरान के खुफिया मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि आतंकवाद विरोधी बलों ने देश के चार प्रांतों से आइएस के 14 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। मंत्रालय ने कहा है कि आतंकवादी पिछले कुछ दिनों में अभियानों को अंजाम देने के प्रयास में अवैध रूप से ईरान में दाखिल हुए थे। आतंकि का नेतृत्व आइएस खुरासान समूह कर रहा था। इन्हें तेहरान, अल्बोर्ज, फार्स और खुजेस्तान प्रांतों में गिरफ्तार किया गया है। (आइएएनएस)

बाइक अभियान में भाग लेंगे भारत, नेपाल, श्रीलंका के जवान

काठमांडू : भारत, नेपाल और श्रीलंका के सशस्त्र बल के जवान अक्टूबर में बौद्ध सर्किट के साथ एक बाइक अभियान में हिस्सा लेंगे। तीनों देशों की सरकारों और रायल थाई मठ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित यह अभियान नेपाल के लुंबिनी से शुरू होकर श्रीलंका के कोलंबो में समाप्त होगा। यह अभियान अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में शुरू होगा और नवंबर के पहले सप्ताह तक पूरा होगा। (एएनआइ)

दक्षिणी म्यांमार में सेना ने दो पत्रकारों को मार डाला

बैंकाक : म्यांमार सेना ने दो पत्रकारों की हत्या कर दी गई। एक को कथित तौर पर पकड़ने के बाद मार दिया गया, जब सुरक्षा बलों ने दक्षिणी राज्य मोन में उनमें से एक के घर पर छापा मारा था। पत्रकारों की सुरक्षा के लिए न्यूयार्क स्थित समिति के दक्षिणपूर्व एशिया प्रतिनिधि शान क्रिस्पिन ने कहा कि दोनों पत्रकारों की हत्या स्वतंत्र प्रेस के खिलाफ अत्याचार है। (एपी)

यूएन में गाजा को लेकर प्रस्ताव पेश करने की तैयारी में फलस्तीन

- इसमें यूएन की शीर्ष अदालत के हालिया फैसलों को शामिल किया जाएगा
- फलस्तीनी क्षेत्रों में इजरायल की मौजूदगी गैरकानूनी घोषित है

संयुक्त राष्ट्र, एपी: फलस्तीनियों ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा कि वे सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक प्रस्ताव को पेश करने की योजना बना रहे हैं। इसमें संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत के हालिया व्यापक फैसले को शामिल किया जाएगा, जिसमें कब्जे वाले फलस्तीनी क्षेत्रों में इजरायल की उपस्थिति को गैरकानूनी घोषित किया गया है। इसके साथ प्रस्ताव में इसे समाप्त करने के लिए एक समय सीमा तय की गई है।

संयुक्त राष्ट्र में फलस्तीन के राजदूत रियाद मंसूर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव को लेकर कहा कि यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होगा, इजरायल के कब्जे को समाप्त करने के लिए आवश्यक है। हम लोग इंतजार करते करते थक गए हैं। अब यह समय समाप्त हो चुका है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने 19 जुलाई को 57 साल पहले कब्जा की गई भूमि पर इजरायल के शासन की अभूतपूर्व व्यापक निंदा की। इसमें कब्जा खत्म करने और बस्ती निर्माण तुरंत रोकने का आह्वान किया गया। इजरायल ने वेस्ट बैंक, ईस्ट यरुशलम और गाजा पट्टी पर 1967 के युद्ध में कब्जा कर लिया था। फलस्तीनी राजदूत के बाद बोलने के लिए खड़े इजरायल के राजदूत डेनी डैनन ने फलस्तीनियों की योजना या अदालत के फैसले का कोई उल्लेख नहीं किया।

अमेरिका सेना ने हाउती विद्रोहियों के तीन ड्रोन मार गिराए : अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने शुक्रवार को कहा कि उसकी नौसेना ने 24 घंटे के अंदर लाल सागर में यमन के हाउती विद्रोहियों द्वारा लांच तीन बम लदे ड्रोन नष्ट कर दिए। आइएएनएस के अनुसार, इंटरनेट प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि लाल सागर के ऊपर दो ईरान समर्थित यूएवी और एक ड्रोन को यमन के हाउती नियंत्रित क्षेत्र में नष्ट किया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि जैसे ही यह स्पष्ट हुआ कि ये यूएवी अमेरिका और उसके नेतृत्व वाली सेना के लिए खतरा हैं, तुरंत कार्रवाई की गई।

हाउती समूह लाल सागर और इसके आसपास लगातार मालवाहक पोतों को निशाना बना रहा है। वहीं, इजरायली सुरक्षा सूत्रों का कहना है कि दक्षिणी लेबनान पर इजरायली हमलों में हिजबुल्ला के छह लड़ाके और एक बच्चा मारा गया है। यह कार्रवाई सीमा पर हिजबुल्ला के हमलों के जवाब में है।

यूएन ने कहा, गाजा में 90 प्रतिशत लोग हुए विस्थापित : फलस्तीनी क्षेत्र के एक शीर्ष मानवीय सहायता अधिकारी ने कहा कि गाजा में पिछले वर्ष अक्टूबर में शुरू युद्ध के बाद से 12 अगस्त तक फलस्तीन की 21 लाख आबादी में से 90 प्रतिशत को विस्थापन का सामना करना पड़ा है। वहीं, अंतरराष्ट्रीय राहत कमेटी ने कहा कि 24 वर्ष में गाजा क्षेत्र में पहली बार पोलियो के मामले सामने आए हैं। गाजा में बुनियादी ढांचे तबाह हो चुके हैं।

इजरायल-हमास लड़ाई के मध्य शुक्रवार को गाजा में एक विस्फोट के बाद उठता धुआं। रायटर

****

संभावित खतरे के कारण जर्मनी में नाटो हवाई अड्डे पर बढ़ाई गई सुरक्षा

बर्लिन, एपी : नाटो ने कहा कि खुफिया जानकारी में संभावित खतरे की आशंका जताए जाने के बाद पश्चिमी जर्मनी में नाटो हवाई अड्डे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उन सभी कर्मचारियों को एहतियात के तौर पर घर भेज दिया गया है, जो वर्तमान में मिशन के लिए जरूरी नहीं हैं। गीलेनकिर्चेन हवाई अड्डा में बेस के पास पूछताछ के लिए एक व्यक्ति को कुछ देर के लिए हिरासत में लिया गया था।

गुरुवार देर रात एक्स पर नाटो अवाक्स बेड़े के खाते पर एक पोस्ट में घोषणा की गई कि हमने सुरक्षा स्तर बढ़ा दिया है। हालांकि, संभावित खतरे की प्रकृति के बारे में नहीं बताया गया। इसमें कहा गया है कि आपरेशन योजना के अनुसार जारी है। गीलेनकिर्चेन बेस की ओर से शुक्रवार को कहा कि उसके पास कोई नई जानकारी नहीं है। पुलिस तैनाती की पुष्टि की गई है। पिछले हफ्ते, कोलोन के पास स्थित एक प्रमुख जर्मन वायु सेना को इस आशंका के कारण कई घंटों के लिए बंद कर दिया गया था कि इसकी जल आपूर्ति के साथ छेड़छाड़ की गई है।

यूक्रेनी सेना ने कहा, कुर्स्क में अमेरिकी ग्लाइड बमों का किया इस्तेमाल

- खार्कीव के पूर्वी क्षेत्र में कुछ क्षेत्रों पर फिर से कब्जे का किया दावा
- रूस ने कावकाज बंदरगाह पर यूक्रेनी हमले के बाद 17 लोगों को बचाया

कीव, एपी: रूस के कुर्स्क क्षेत्र में घुसपैठ के बीच यूक्रेनी सेना ने कहा है कि उसने यहां हमले के लिए अमेरिका के दिए उच्च परिष्कृत ग्लाइड बमों का इस्तेमाल किया। ये लंबी दूरी के लक्ष्य पर सटीक निशाना बनाने में सक्षम होते हैं। इसके साथ ही खार्कीव के पूर्वी क्षेत्र में कुछ क्षेत्रों पर फिर से कब्जा करने का भी दावा किया है, जहां रूस ने वसंत में आक्रामक हमला किया था। वहीं, रूसी अधिकारियों ने कहा कि उसके काला सागर स्थित बंदरगाह कावकाज पर खड़ी एक नौका पर यूक्रेन के हमले के बाद सत्रह लोगों को बचाया गया। यूक्रेनी वायु सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मायकोला ओलेशुक ने गुरुवार रात एक वीडियो जारी किया, जिसमें कुर्स्क क्षेत्र में एक रूसी प्लाटून बेस पर हमला होते हुए दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि जीबीयू-39 बमों से किए गए हमले में रूसी हताहत हुए और उपकरण नष्ट हो गए। यूक्रेन की तीसरी सेपरेट असाल्ट ब्रिगेड ने कहा कि उसकी सेना खार्कीव क्षेत्र में लगभग दो वर्ग किमी आगे बढ़ गई है।

रूस के रोस्तोव क्षेत्र स्थित प्रोलेटार्स्क में यूक्रेनी ड्रोन हमले में एक डीजल डिपो में लगी आग। वीडियोग्रैब/रायटर

रूस में कमांडो ने चार आतंकियों को मारकर जेल संकट खत्म किया

मास्को, एपी : रूस में शुक्रवार को सुरक्षाकर्मियों को बंधक बनाकर कुछ बंदियों ने जेल पर आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (आइएस) का शासन घोषित कर दिया। इससे कई घंटे तक जेल के आसपास अफरातफरी मची रही। अंततः रूस के नेशनल गार्ड के निशानेबाजों ने चार बंदियों को मारकर स्थिति को नियंत्रण में लिया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार रूस की राजधानी मास्को से करीब 860 किलोमीटर दूर सुरोवकिनो की जेल में शुक्रवार प्रातः हिंसा हुई। इस हिंसा में घायल हुए चार लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इन घायलों में दो की हालत गंभीर है। बताया गया है कि जेल में बंद कुछ कैदियों ने धारदार हथियारों और हथौड़ों का इंतजाम कर लिया था। इसके बाद उन्होंने मौका देखकर सुरक्षाकर्मियों पर हमला बोला और उनमें से कुछ को घायल कर दिया। इसके बाद सुरक्षाकर्मियों के हथियारों पर कब्जा कर उन्होंने बाकी सुरक्षाकर्मियों को बंधक बना लिया और जेल पर नियंत्रण स्थापित कर लिया।

जिन कैदियों ने सुरक्षाकर्मियों पर हमला किया और उन्हें बंधक बनाया वे आइएस के सदस्य थे। इन कैदियों को आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने के चलते जेल में रखा गया था।

मैं अपनी तकनीक में परिपक्व हूं। जब मैं शूटिंग रेंज में जाती हूं तो भावनाओं को पीछे छोड़ देती हूं। मैं वहां अपनी प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करती हूं।

— अवनी लेखरा, पैरालिंपिक स्वर्ण विजेता

ध्रुव श्योराण ने चेन्नई प्रो चैंपियनशिप खिताब जीता

चेन्नई, प्रेट्र : गुरुग्राम के स्टार गोल्फर ध्रुव श्योराण ने शुक्रवार को यहां 50 लाख रुपये की चेन्नई प्रो चैंपियनशिप के अंतिम दौर में तीन अंडर-69 का शानदार कार्ड खेलकर पीजीटीआइ टूर पर पहला खिताब अपनी झोली में डाल लिया। दो बार के पीजीटीआइ फीडर टूर विजेता ध्रुव श्योराण ने कुल 16 अंडर 272 का स्कोर बनाकर तीन स्ट्रोक के अंतर से खिताब अपने नाम किया।

नीरज और प्रथम स्थान के बीच 90 मी. की बाधा

भारतीय एथलीट दो सप्ताह के भीतर तीसरी बार 89 मीटर से आगे निकले, पर नहीं मिला शीर्ष स्थान

सुकांत सौरभ ● जागरण

नई दिल्ली: नीरज चोपड़ा, वह नाम है जिससे शायद ही अब देश में कोई परिचित नहीं होगा। भारतीय एथलेटिक्स का वह सितारा जो जब हाथ में भाला लेकर दौड़ता है पूरे देश की निगाहें उस पर टिक जाती है। अब चाहे वह रात 1.30 बजे पेरिस ओलिंपिक का फाइनल हो या गुरुवार रात डायमंड लीग के लुसाने चरण की भाला फेंक स्पर्धा। नीरज चोपड़ा ने देश में एथलेटिक्स को एक नई पहचान दे दी है। हालांकि, यह नीरज का दुर्भाग्य कहें या चोट के कारण असमर्थता 90 मीटर की बाधा ने उनके और प्रथम स्थान के बीच एक दीवार खींच दी है। दो सप्ताह के भीतर 89 मीटर से अधिक के तीन सर्वश्रेष्ठ थ्रो फेंकने वाले दो बार के ओलिंपिक पदक विजेता की गुरुवार रात निराशा ने भी यह दर्शा दिया।

90 मीटर का आंकड़ा कर रहा परेशान : गुरुवार को स्विट्जरलैंड के लुसाने में सत्र का सर्वश्रेष्ठ 89.49 मीटर का थ्रो फेंकने के बाद नीरज में चिर परिचित उत्साह नहीं देखने को मिला। दिखी तो केवल एक बार फिर लगभग आधे फीट से 90 मीटर चूकने की निराशा। आखिर ये 90 मीटर का आंकड़ा क्यों इतना महत्वपूर्ण बन गया है कि सत्र का सर्वश्रेष्ठ थ्रो भी इस स्टार एथलीट को उत्साहित नहीं कर रहा। इसका कारण है उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले सभी शीर्ष एथलीट का कम से कम एक बार 90 मीटर तक पहुंचना। लुसाने चरण से पहले हुई विशेष बातचीत में भी उन्होंने कहा था कि 90 मीटर का थ्रो उन्होंने भगवान पर छोड़ दिया है। उन्हें ओलिंपिक में भरोसा था कि वह पहली बार 90 मीटर की बाधा तोड़ देंगे पर चोट के कारण उनका ध्यान भटका हुआ था और वह ये नहीं कर सके।

चौथी बार 89 मीटर से निकले आगे : यह चौथा अवसर था जब नीरज 89 मीटर से आगे निकले पर 90 मीटर के पीछे रह गए। कमाल की बात यह है कि तीन बार फाइनल में उन्होंने 89 मीटर से आगे के अपने सर्वश्रेष्ठ तीन थ्रो फेंके हैं और हर बार उन्हें दूसरे स्थान से संतोष करना पड़ा है। सर्वप्रथम वह 2022 में डायमंड लीग के ही स्टाकहोम चरण में 90 मीटर की बाधा पार करने से केवल छह सेंटीमीटर से चूक गए थे, परंतु यही उनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो भी है। 89.94 मीटर के इस शानदार थ्रो के साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय रिकार्ड भी बनाया था, परंतु तब भी एंडरसन पीटर्स ने 90.31 मीटर के थ्रो के साथ उन्हें पछाड़ दिया था। यही गुरुवार को भी हुआ। शुरुआती थ्रो में जूझते दिखे नीरज ने पांचवें थ्रो में 85.58 मीटर के थ्रो के साथ शीर्ष तीन में वापसी कर ली। हालांकि, अंतिम थ्रो में ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स ने 90.61 मीटर के थ्रो के साथ न केवल सत्र का सर्वश्रेष्ठ थ्रो फेंक दिया, बल्कि 2015 में जमैका के केशोर्न वालकट के मीटिंग रिकार्ड को तोड़कर इसे अपने नाम कर लिया। अब बारी थी नीरज की। उन्होंने अंतिम थ्रो में पूरी जान झोंक दी, पर एक बार फिर वह 0.51 मीटर से 90 मीटर की बाधा को पार करने से चूक गए। नीरज ने सत्र का सर्वश्रेष्ठ 89.49 मीटर का थ्रो फेंका पर यह एक बार फिर प्रथम स्थान के लिए पर्याप्त साबित नहीं हुआ। दो सप्ताह पहले नीरज ने पेरिस ओलिंपिक क्वालीफिकेशन में भी 89.37 मीटर का थ्रो फेंका तो उनसे स्वर्ण की रक्षा की उम्मीद बढ़ गई, पर फाइनल में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 मीटर का थ्रो फेंककर स्वर्ण जीता तो नीरज का 89.45 मीटर का थ्रो उन्हें रजत तक ही पहुंचा सका।

मैंने शुरुआती प्रयास में ही अच्छा करने का सोचा था लेकिन यह थ्रो सही नहीं रहा। जूलियस येगो ने मुझे कहा 'धैर्य बनाये रखो' तुम दूर तक भाला फेंकोगे। मैं शांतचित रहने की कोशिश कर रहा था। पीटर्स ने जब 90 मीटर थ्रो किया, मेरा शरीर अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, लेकिन अंदर से संघर्ष करने की पूरी भावना थी। आखिरी थ्रो में मैंने अधिक नहीं सोचा, बस अपना सर्वश्रेष्ठ दिया।

– नीरज चोपड़ा

89.49 मीटर के सत्र के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ डायमंड लीग के लुसाने चरण में दूसरे पर रहे नीरज, 90.61 मीटर की दूरी तय कर एंडरसन पीटर्स निकले आगे

89.45 मीटर का थ्रो फेंककर नीरज ने पेरिस ओलिंपिक में जीता था रजत, पर पाक के नदीम ने 92.97 मीटर की दूरी तय कर बना दिया था ओलिंपिक रिकार्ड

अब तक 24 एथलीटों ने तय की है 90 मीटर की दूरी

भाला फेंक में 90 मीटर की बाधा पार करने वाले 24 एथलीटों में अरशद नदीम एकमात्र एशियाई एथलीट हैं। उन्होंने यह कारनामा तीन बार किया है, जिसमें से दो बार उन्होंने पेरिस ओलिंपिक फाइनल में ही यह करके दिखाया। सर्वाधिक बार यह दूरी तय करने वाले एथलीट को नीरज अपना आदर्श मानते हैं। वह हैं चेक गणराज्य के जेन जेलेज्नी, जिन्हें भाला फेंक का सबसे सफल एथलीट कहना भी गलत नहीं होगा। तीन बार के ओलिंपिक चैंपियन और 98.48 मीटर के थ्रो के साथ 28 वर्ष पूर्व विश्व रिकार्ड बनाने वाले इस दिग्गज एथलीट ने आठ बार यह कारनामा किया था। इतने ही बार जर्मनी के जोहानिस वेटर ने भी यह दूरी तय की है और 97.76 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ वह दूसरे स्थान पर हैं। वहीं, अगर अब तक के भाला फेंक इतिहास की बात करें तो 127 बार एथलीटों ने 90 मीटर से अधिक की दूरी तय की है।

लुसाने में भाला फेंकते नीरज चोपड़ा ● रायटर

टेस्ट बचाने के लिए कोष तैयार कर रहा आइसीसी

सिडनी, प्रेट्र: आइसीसी टेस्ट क्रिकेट के लिए कम से कम 125.74 करोड़ रुपये (15 मिलियन अमेरिकी डालर) का अलग से कोष तैयार करने पर विचार कर रहा है जिससे खिलाड़ियों की मैच फीस बढ़ाने में मदद मिलेगी और उन्हें केवल आकर्षक टी20 फ्रेंचाइजी लीग पर ध्यान केंद्रित करने से रोका जा सकेगा। सिडनी मार्निंग हेराल्ड की रिपोर्ट के अनुसार क्रिकेट आस्ट्रेलिया ने इस तरह का प्रस्ताव रखा है जिसे बीसीसीआइ के सचिव जय शाह और इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड का समर्थन हासिल है। शाह अभी

इससे टेस्ट क्रिकेटरों की न्यूनतम मैच फीस में बढ़ोतरी होगी और यह विदेशी दौरों पर टीमों को भेजने की लागत को कवर करेगा। इससे वेस्टइंडीज जैसे क्रिकेट बोर्ड को मदद मिलेगी जिसके खिलाड़ी टेस्ट के बजाय वैश्विक टी20 प्रतियोगिताओं में खेलने को प्राथमिकता दे रहे हैं।

छह दिन का होगा एक टेस्ट

दुबई, प्रेट्र : अगले महीने गाल में न्यूजीलैंड के विरुद्ध श्रीलंका का शुरुआती टेस्ट मैच छह दिन का होगा। यहां राष्ट्रपति चुनाव के कारण एक दिन विश्राम का प्रविधान है। आइसीसी के अनुसार 18 सितंबर को शुरू होने वाले टेस्ट में श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव के कारण 21 सितंबर को विश्राम का दिन होगा। दो दशकों से अधिक समय में यह पहली बार होगा कि श्रीलंका छह दिनों के टेस्ट मैच की मेजबानी करेगा। इससे पहले 2001 में कोलंबो में जिंबाब्वे के विरुद्ध खेले गए मैच में पोया डे (पूर्णिमा) के कारण एक दिन का विश्राम रखा गया था।

जय बनेंगे आइसीसी चेयरमैन तो कौन संभालेगा बीसीसीआइ

नई दिल्ली, प्रेट्र : आंकड़े जय शाह को अगले आइसीसी चेयरमैन के रूप में चुनने के पक्ष में होंगे लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वह विश्व संचालन संस्था में शामिल होने का निर्णय करेंगे या नहीं और इसके बाद बीसीसीआइ सचिव के रूप में उनकी जगह कौन लेगा।

माना जा रहा है कि शाह को आइसीसी बोर्ड के 16 में से 15 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है लेकिन वह इस पद पर आना चाहते हैं या नहीं, इसे तय करने के लिए उनके पास 96 घंटे से भी कम समय है। वहीं उनके पास बीसीसीआइ सचिव के रूप में लगातार दूसरे कार्यकाल में अभी एक वर्ष शेष है। नया आइसीसी चेयरमैन एक दिसंबर को कार्यभार संभालेगा और नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 27 अगस्त है।

सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड में वापसी के लिए अनिवार्य तीन वर्ष का 'कूलिंग आफ पीरियड' शाह के लिए अक्टूबर 2025 में अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद शुरू होगा। लेकिन इस बात पर बड़ा सवालिया निशान है कि बीसीसीआइ में शाह की जगह कौन लेगा क्योंकि उन्होंने और उनके करीबी लोगों ने अभी तक तत्काल योजनाओं को साझा नहीं किया है।

जय शाह

शाह के पास नामांकन करने का अंतिम निर्णय लेने के लिए केवल 27 अगस्त तक समय

ये हो सकते हैं दावेदार

राजीव शुक्ला : ऐसी संभावना है कि बीसीसीआइ पदों में फेरबदल करे और वर्तमान उपाध्यक्ष और राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद शुक्ला को एक वर्ष के लिए यह काम करने के लिए कहे। शुक्ला को निश्चित रूप से सचिव बनने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

आशीष शेलार : महाराष्ट्र भाजपा के दिग्गज शेलार बीसीसीआइ के कोषाध्यक्ष हैं और मुंबई क्रिकेट संघ (एमसीए) प्रशासन में बड़ा नाम हैं। शेलार हालांकि एक कुशल राजनीतिज्ञ हैं और बीसीसीआइ सचिव पद के लिए उन्हें अपना समय देना होगा, पर वह भी इस दौड़ में शामिल हो सकते हैं।

अरुण धूमल: इंडियन प्रीमियर लीग चेयरमैन के पास बोर्ड चलाने के लिए अनुभव है। वह कोषाध्यक्ष रह चुके हैं और लुभावनी क्रिकेट लीग के प्रमुख हैं।

संयुक्त सचिव देवजीत शाक्या : वह हालांकि लोकप्रिय नाम नहीं हैं, लेकिन वर्तमान बीसीसीआइ प्रशासन में एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं जिन्हें भी पदोन्नत किया जा सकता है।

कुछ युवा भी हैं दावेदार : युवा प्रशासकों में दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ अध्यक्ष रोहन जेटली या बंगाल क्रिकेट संघ के पूर्व अध्यक्ष अविषेक डालमिया के नाम पर चर्चा हो सकती है। अन्य राज्य इकाई के अधिकारियों में पंजाब के दिलशेर, गोवा के विपुल फड़के और छत्तीसगढ़ के प्रभतेज भाटिया शामिल हैं।

एक नजर में

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं मिली अच्छी रकम

कराची : पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) को अगस्त 2024 से दिसंबर 2026 की अवधि के बीच अंतरराष्ट्रीय घरेलू मैचों के प्रसारण अधिकार बेचने के लिए रखे गए अपने आरक्षित मूल्य से लगभग आधी रकम ही मिली है। पाकिस्तान क्षेत्र के प्रसारण अधिकार 1.72 अरब पाकिस्तानी रुपये में बेचे गए हैं जो बोर्ड द्वारा अधिकार बेचने के लिए रखे गए शुरुआती आरक्षित मूल्य 3.2 अरब पीकेआर से लगभग 1.48 अरब पीकेआर कम है। पीसीबी ने प्रसारण अधिकार 28 महीने की अवधि के लिए एआरवाई और टावर स्पोर्ट्स के गठजोड़ को बेचा है। यह प्रसारण अधिकार 11 टेस्ट के लिए हैं, जिनमें 2024-25 सत्र के सात टेस्ट के अलावा 26 वनडे और 24 टी-20 अंतरराष्ट्रीय शामिल हैं। (प्रेट्र)

यूएस मास्टर्स में शिकागो प्लेयर्स का पदार्पण

नई दिल्ली : अमेरिका के ह्यूस्टन में शुरू हो रही आगामी यूएस मास्टर्स टी-10 लीग के दूसरे सत्र में शिकागो प्लेयर्स ने नवीनतम फ्रेंचाइजी के रूप में पदार्पण किया है। यूएस मास्टर्स टी-10 का दूसरा सत्र आठ नवंबर से 17 नवंबर तक टेक्सास के ह्यूस्टन में खेला जाएगा। शिकागो प्लेयर्स उन छह फ्रेंचाइजी में से एक है जो यूएस मास्टर्स टी10 के दूसरे सत्र में भाग लेगी। भारतीय मूल के अमेरिकी व्यवसाई विशाल पटेल के पास इस टीम का स्वामित्व है। (एएनआइ)

वार्न के निधन से लगा अपना खोया : कुलदीप

आस्ट्रेलिया की पारिवारिक यात्रा पर हैं भारतीय स्पिनर

मेलबर्न, प्रेट्र : भारत के कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव ने बताया कि दो वर्ष पहले आस्ट्रेलियाई दिग्गज शेन वार्न के निधन से उन्हें लगा कि जैसे उन्होंने अपने परिवार का कोई सदस्य खो दिया क्योंकि उनका हमेशा मानना था कि उनके बीच एक मजबूत रिश्ता था।

आस्ट्रेलिया की संक्षिप्त पारिवारिक यात्रा पर आए कुलदीप ने अपने आदर्श क्रिकेटर के घरेलू मैदान प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) का दौरा किया, जहां उन्होंने स्टेडियम के बाहर वार्न की प्रतिमा के साथ फोटो खिंचवाई। कुलदीप ने कहा, 'शेन वार्न मेरे आदर्श थे और मेरा उनके साथ बहुत गहरा रिश्ता था। जब भी मैं वार्न के बारे में सोचता हूं तो मैं भावुक हो जाता हूं। ऐसा लगता है जैसे मैंने अपने परिवार से किसी को खो दिया है।' उन्होंने हालांकि आस्ट्रेलिया के दिग्गज लेग स्पिनर के साथ अपने संबंधों के बारे में विस्तार से नहीं बताया। वार्न का 2022 में थाइलैंड में छुट्टियां बिताने के दौरान दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। कुलदीप की यह यात्रा 22 नवंबर को पर्थ में शुरू होने वाली बार्डर गावस्कर ट्राफी से कुछ महीने पहले हो रही है। उन्होंने कहा, 'मैं बार्डर-गावस्कर ट्राफी की प्रतीक्षा कर रहा हूं और हम इस वर्ष आस्ट्रेलिया और भारत के बीच शानदार क्रिकेट प्रतियोगिता की आशा कर रहे हैं।'

मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड परिसर में लगी शेन वार्न की प्रतिमा के साथ फोटो खिंचवाते कुलदीप यादव ● एक्स

स्मिथ के शतक से इंग्लैंड की स्थिति मजबूत

मैनचेस्टर, प्रेट्र: विकेटकीपर बल्लेबाज जैमी स्मिथ के टेस्ट करियर की पहली शतकीय पारी के दम पर इंग्लैंड ने दो मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन शुक्रवार को यहां श्रीलंका पर 122 रन की बढ़त बना ली। स्मिथ ने 148 गेंद की पारी में एक छक्का और आठ चौके की मदद से 111 रन बनाए जिससे श्रीलंका के 236 रन के जवाब में इंग्लैंड की पहली पारी 358 रन पर सिमटी।

इंग्लैंड की टीम लंच से कुछ देर पहले आउट हुई, जिसके बाद उनके गेंदबाजों ने 10 रन पर दो विकेट चटकाकर श्रीलंका की मुश्किलें बढ़ा दीं। श्रीलंका की टीम अब भी इंग्लैंड से 112 रन पीछे है। क्रिस वोक्स ने निशान मदुशंका को खाता खोले बिना बोल्ड किया जबकि कुसल मेंडिस भी बिना कोई योगदान दिए गट एटकिंसन की गेंद पर विकेट के पीछे स्मिथ को कैच थमा बैठे। बेन फाक्स और जानी बेयरस्टो जैसे अनुभवी नामों की जगह टीम में जगह पाने वाले 24 वर्ष के स्मिथ ने अपने चयन को सही साबित किया।

उन्होंने विकेट के पीछे अपने काम से प्रभावित करने के साथ बल्ले से भी बेहतरीन योगदान दिया।

शतक लगाने के बाद जैमी स्मिथ ● एएनआइ

बांग्लादेश ने की वापसी

रावलपिंडी: प्रारंभिक बल्लेबाज शादमन इस्लाम (93 रन) के शतक से चूकने के बावजूद बांग्लादेश ने यहां पाकिस्तान के विरुद्ध पहले टेस्ट के तीसरे दिन स्टंप्स तक पहली पारी में पांच विकेट पर 316 रन बना लिए। शादमन साढ़े पांच घंटे तक क्रीज पर डटे रहे जिन्हें चाय से पहले मोहम्मद अली (42 रन देकर एक विकेट) ने बोल्ड किया। बांग्लादेश अब भी पाकिस्तान से 132 रन से पिछड़ रहा है। घरेलू टीम ने मोहम्मद रिजवान और सउद शकील के शतकों की बदौलत अपनी पहली पारी छह विकेट पर 448 रन बनाकर घोषित की थी। मुशफिकुर रहीम 55 रन और लिटन दास 52 रन बनाकर क्रीज पर डटे हैं।

न्यूयार्क में इतिहास रचने उतरेंगे जोकोविक, गफ पर भी होगी नजर

नई दिल्ली, जेएनएन : सर्बिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविक पुरुष सिंगल्स में सर्वाधिक खिताब जीतने से केवल एक ग्रैंडस्लैम दूर हैं। गत यूएस ओपन चैंपियन सोमवार से शुरू हो रहे वर्ष के अंतिम ग्रैंडस्लैम में एक बार फिर प्रबल दावेदार होंगे। वहीं, महिलाओं में भी गत चैंपियन अमेरिकी युवा खिलाड़ी कोको गफ पर सबकी नजरें टिकी होंगी।

us open

सर्बियाई दिग्गज जोकोविक पहले ही पुरुष सिंगल्स में सर्वाधिक ग्रैंडस्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। न्यूयार्क में अगर वह खिताब की रक्षा करते हैं तो वह ओपन युग इतिहास में सर्वाधिक 25 ग्रैंडस्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन जाएंगे।

नोवाक जोकोविक : मार्गरेट कोर्ट के बाद संयुक्त रूप से 24 ग्रैंडस्लैम जीतने वाले जोकोविक ने पेरिस ओलिंपिक में स्वर्ण जीतकर शीर्ष फार्म प्राप्त कर ली है। 2017 से अब तक ऐसा कोई भी वर्ष नहीं रहा जब इस दिग्गज खिलाड़ी ने कोई ग्रैंडस्लैम नहीं जीता हो। वह यूएस ओपन में जीत के साथ अपने रिकार्ड को कायम रखना का पूरा प्रयास करेंगे। इससे पहले वह विंबलडन फाइनल में भी पहुंचे थे।

पुरुषों में ये हैं प्रबल दावेदार

कार्लोस अलकराज : स्पेनिश युवा खिलाड़ी इस वर्ष शानदार फार्म में हैं। वह तीन में से दो ग्रैंडस्लैम जीत चुके हैं और न्यूयार्क में तीसरे ग्रैंडस्लैम पर नजरें लगा रखी है। 21 वर्षीय खिलाड़ी अपनी फुर्ती और दमदार ग्राउंडस्ट्रोक से सभी को परेशान कर सकते हैं।

जानिक सिनर : इटली के स्टार टेनिस खिलाड़ी जानिक सिनर ने वर्ष का पहला ग्रैंडस्लैम जीतकर अपनी काबिलियत दर्शा दी थी, अब वह वर्ष का अंत भी इसी अंदाज में करना चाहेंगे। हालांकि, उनके लिए यह नोवाक और अलकराज के रहते आसान नहीं होगा।

नोवाक जोकोविक

महिलाओं में ये हैं दावेदार

कोको गफ : अमेरिका की युवा गत चैंपियन ने पिछले वर्ष अपनी क्षमता से सबको चौंका दिया था। इस बार भी न्यूयार्क में वह प्रबल दावेदार के रूप में उतरेंगी। उनका आक्रामक खेल और गति हार्ड कोर्ट पर उन्हें दावेदारों में सबसे आगे करता है। अगर वह खिताब की रक्षा करने में सफल होती हैं तो स्टार खिलाड़ी के रूप में पहचान बना लेंगी।

इगा स्वियातेक : पोलैंड की विश्व नंबर एक महिला खिलाड़ी अपने ग्रैंडस्लैम का छक्का लगाने के लिए पूरा जोर लगाएंगी। चौथी बार रोलां गैरो जीतने वाली इस पोलिश खिलाड़ी ने ओलिंपिक में भी कांस्य पदक जीता था। 2022 में वह यूएस ओपन चैंपियन रही थीं।

अरीना सबालेंका : 2023 की फाइनलिस्ट पिछली बार कोको गफ से हार गई थीं। हालांकि, वह अपनी हार का बदला लेने के इरादे से इस बार न्यूयार्क में उतरेंगी। हार्ड कोर्ट पर उनका आक्रामक खेल उन्हें दावेदार बनाता है। बेलारूस की खिलाड़ी यूएस ओपन जीतकर वर्ष का सुखद अंत करना चाहेंगी।

भारतीय अंडर-17 महिला पहलवान टीम बनी चैंपियन

अदिति, नेहा, मानसी और पुलकित के बाद काजल ने जीता स्वर्ण, श्रुतिका ने रजत तो मुस्कान व राज ने जीता कांसा

नई दिल्ली, जेएनएन: जोर्डन के अम्मान में भारत की महिला पहलवानों ने पांच स्वर्ण, एक रजत और तीन कांस्य पदक जीतकर टीम ट्राफी जीत ली। हालांकि, पुरुष पहलवानों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। गुरुवार को अदिति, नेहा, मानसी और पुलकित के अपने-अपने वर्ग में जीतने के बाद शुक्रवार को काजल (69 किग्रा) ने फाइनल में जीत दर्ज करते हुए अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में खिताब जीत लिए। वहीं, श्रुतिका शिवाजी पाटिल (46 किग्रा) को रजत पदक से संतोष करना पड़ा, जबकि मुस्कान (53 किग्रा) और 40 किग्रा वर्ग में राज बाला ने कांस्य पदक जीत लिया।

गुरुवार को अदिति ने 43 किग्रा, नेहा ने 57 किग्रा, 65 किग्रा में पुलकित, जबकि मानसी ने 73 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। शुक्रवार को 69 किग्रा वर्ग में काजल ने यूक्रेन की रीबाक को हराकर स्वर्ण, 53 किग्रा वर्ग में मुस्कान ने अमेरिका की इसाबेला को और 40 किग्रा वर्ग में राज बाला ने जापान की मोनाका को हराकर कांस्य जीता। वहीं, 46 किग्रा वर्ग में श्रुतिका जापान की यू कात्सुमे से फाइनल में हार गईं।

राष्ट्रीय फलक

पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप में रूस के पायलट किए गए प्रतिबंधित

- यूक्रेन युद्ध के विरोध में खेल संघ ने लगाया है प्रतिबंध
- एयरो क्लब को शुल्क न देने पर नेपाल के पायलट भी नहीं ले सकेंगे भाग

मुनीष दीक्षित ● जागरण

बैजनाथ : हिमाचल के कांगड़ा जिले के बीड़ बिलिंग में दो से नौ नवंबर तक होने जा रहे पैराग्लाइडिंग विश्व कप में रूस और नेपाल के पायलट भाग नहीं ले पाएंगे। अभी तक रूस के करीब 10 पायलटों ने आवेदन किया है, जबकि नेपाल से भी कुछ पायलट के आवेदन पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप एसोसिएशन के पास पहुंचे हैं। ओलिंपिक संघ और यूरोप के अधिकतर खेल संघ अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में यूक्रेन-रूस युद्ध के विरोध में हैं। इस कारण रूस के खिलाड़ियों को अनुमति नहीं दी जा रही है। पैराग्लाइडिंग विश्व कप का आयोजन करने वाली पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप एसोसिएशन पर यूरोप के देशों का दबदबा है। हालांकि इजरायल भी युद्ध का सामना कर रहा है, लेकिन फिलहाल इजरायल के लिए ऐसे कोई प्रतिबंध नहीं हैं। इसके अलावा नेपाल के पायलटों को भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। नेपाल के पायलटों को वहां के एयरो क्लब को फेडरेशन आफ एरोमेटिक इंटरनेशनल द्वारा शुल्क नहीं भरे जाने के कारण निलंबित किया गया है। बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन का कहना है कि नेपाल और रूस के पायलटों को कुछ पाबंदियों के कारण विश्व कप में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।

सीमावर्ती गांवों और वनवासी क्षेत्रों को सशक्त करेगा एकल ग्रामोत्थान

- प्रति वर्ष 2.50 लाख ग्रामीण युवाओं को कंप्यूटर का देगा प्रशिक्षण
- फाउंडेशन की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में लिया गया निर्णय

जागरण संवाददाता, रांची : किसानों और जरूरतमंद महिलाओं व पुरुषों को आर्थिक रूप से सशक्त करने का कार्य कर रहा एकल अभियान का एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन अब सीमावर्ती गांवों को आर्थिक रूप से मजबूत करने का कार्य करेगा। जनजाति क्षेत्रों पर भी विशेष ध्यान देगा। शुक्रवार से झारखंड की राजधानी रांची के होटल ग्रीन होराइजन में प्रारंभ दो दिवसीय एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन के चेयरमैन लक्ष्मी नारायण गोयल ने कहा कि अबतक 12 लाख किसानों को जैविक खेती के साथ-साथ विभिन्न तरह के उत्पादों का उपज बढ़ाने का प्रशिक्षण दिया गया है।

11.50 लाख ग्रामीण युवक एवं युवतियों को स्कील डेवलपमेंट का प्रशिक्षण दिया गया है। अगले वर्ष से प्रति वर्ष 2.50 लाख ग्रामीण युवक एवं युवतियों को कंप्यूटर का प्रशिक्षण देने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए अब तक 47 कंप्यूटर आन व्हील देश के अलग-अलग प्रांतों में चल रहे हैं। इसकी संख्या प्रति वर्ष 15 से 20 बढ़ाने की है।

एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन के चेयरमैन लक्ष्मी नारायण गोयल ने कहा कि एकल अभियान के पांच आयामों में से एक एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन का मुख्य लक्ष्य गांवों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। इसके लिए गांव की महिलाओं को विभिन्न तरह के प्रशिक्षण देकर जहां स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है वहीं जरूरतमंत युवाओं को मोबाइल, गाड़ी, टीवी आदि बनाने का प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वावलंबी बनाने का कार्य जारी है। इसके लिए पूरे देश में 218 प्रशिक्षण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं।

****

अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई स्थगित

नई दिल्ली, एएनआइ : चित्रकूट की जेल में गैरकानूनी रूप से पत्नी से मुलाकात करने से जुड़े मामले में माफिया मुख्तार अंसारी के पुत्र अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई स्थगित कर दी। मामले में अगली सुनवाई सितंबर में होगी।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने अब्बास की जमानत याचिका पर जवाब देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को एक हफ्ते का समय दिया है। अब्बास की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा, आरोप लगाया गया है कि लोगों ने बिना सत्यापन जेल में प्रवेश किया। लेकिन उनके पास सभी दस्तावेज हैं जो बताते हैं कि लोगों के जेल में प्रवेश करने पर हर बार सत्यापन किया गया था। अब्बास ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक मई के फैसले को चुनौती दी है जिसने इस मामले में उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। चित्रकूट की जेल में पत्नी से कथित गैरकानूनी मुलाकात के बाद अब्बास को फरवरी, 2023 में कासगंज की जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। इस मामले में अब्बास की पत्नी समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया गया था। बाद में अब्बास की पत्नी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी।

चित्रकूट जेल में पत्नी से गैरकानूनी रूप से मुलाकात का मामला

एक्स्ट्रा शाट

इन दिनों जहां कोलकाता में मेडिकल छात्रा के साथ दुष्कर्म और हत्या को लेकर पूरा देश आक्रोशित है, वहीं पढ़ाई में बेटियों के जोरदार प्रदर्शन को लेकर हाल में प्रकाशित अध्ययन से समाज के दृष्टिकोण में आ रहा सकारात्मक बदलाव भी परिलक्षित होता है। चर्चा कर रहे हैं अरुण श्रीवास्तव...

फोटोः इमेजेज बाजार

86.9 प्रतिशत बेटियां उत्तीर्ण हुईं 2023 में 10वीं की बोर्ड परीक्षा में, जबकि 83 प्रतिशत लड़कों को मिली थी सफलता।

86.3 प्रतिशत बेटियां पास हुईं 2023 में 12वीं की बोर्ड परीक्षा में। उनकी तुलना में 78.9 प्रतिशत लड़के हुए थे उत्तीर्ण।

43 प्रतिशत हो गया देशभर में विज्ञान वर्ग से पढ़ाई करने वाली लड़कियों का औसत, जो 2022 में 42 प्रतिशत था।

● सरकारी, निजी और सरकारी सहायता प्राप्त सभी स्कूलों में बेटों की तुलना में बेटियों का प्रदर्शन दिखा बेहतर।

सकारात्मक दृष्टिकोण का सुफल

कोलकाता की घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बंगाल सरकार और वहां की पुलिस की फजीहत के बीच पूरा देश विरोध में एकजुट दिख रहा है, पर निर्भया कांड के बाद तमाम कदम उठाए जाने के बावजूद एक के बाद एक ऐसी घटनाओं का सामने आना दुखद भी है और बेहद चिंताजनक भी। ऐसे मामलों में सरकारों व पुलिस का उदासीन और लापरवाह रवैया भी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि ऐसे मामलों पर अंकुश लगाने और बेटियों को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार की पहल पर जल्द ही कोई ठोस कदम उठाया जाएगा।

बेटियां बढ़ रहीं आगे: केंद्र सरकार की ओर से देश के सभी शिक्षा बोर्डों की दसवीं और बारहवीं के परीक्षा परिणामों को लेकर हाल में सामने आए अध्ययन में जो सबसे उल्लेखनीय बात सामने आई है, वह है बेटियों का लगातार बेहतर हो रहा प्रदर्शन। यह प्रदर्शन दसवीं और बारहवीं दोनों के परिणामों में दिखता है। 2023 में दसवीं की बोर्ड परीक्षा में जहां 83 प्रतिशत लड़के उत्तीर्ण हुए, वहीं लड़कियों के उत्तीर्ण होने का अनुपात 86.9 प्रतिशत रहा। यदि बारहवीं के परिणामों को देखा जाए, तो 2023 की बोर्ड परीक्षा में 78.9 प्रतिशत लड़कों की तुलना में 86.3 प्रतिशत लड़कियां उत्तीर्ण हुईं। विशेष बात यह भी है कि बेटों की अपेक्षा बेटियों का यह बेहतर प्रदर्शन सरकारी, निजी और सरकारी सहायता प्राप्त सभी स्कूलों में दिखा। एक और खास बात यह है कि पहले जहां बेटियों का रुझान मानविकी विषयों में ही अधिक देखा जाता था, वहीं अब उनका रुझान विज्ञान विषयों की ओर भी बढ़ता देखा जा रहा है।

सोच में आ रहा बदलाव: बेटियों के अच्छे प्रदर्शन के लिए उनके प्रति समाज के दृष्टिकोण में तेजी से आ रहे बदलाव को श्रेय दिया जाना चाहिए। अब ज्यादातर माता-पिता बेटे व बेटी में कोई भेद न करते हुए उन्हें समान रूप से आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। दृष्टिकोण बदलने का ही यह सुफल है कि अब गांवों, कस्बों और छोटे शहरों की लड़कियां भी पढ़ाई और अपनी रुचि के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए बेहिचक बाहर निकल रही हैं। इस बदलाव का ही परिणाम है कि हाल के वर्षों में बेटियां न केवल हर क्षेत्र में आगे आकर चमकदार करियर बना रही हैं, बल्कि वे नेतृत्व की भूमिका में भी जोरदार प्रदर्शन कर रही हैं। चाहे वह शिक्षा हो या करियर या फिर खेल जगत ही क्यों न हो।

थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है: भले ही हाल के दशकों-वर्षों में बेटियों-महिलाओं के साथ खड़े होने और उन्हें उनकी पसंद के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने में माता-पिता के सोच में सकारात्मक व सुखद बदलाव देखने को मिल रहा है, पर अब भी समूचे समाज को उन्हें आगे बढ़ाने के प्रति अपने नजरिए को और अधिक मजबूत करने की जरूरत है। यदि समाज के हर वर्ग के लोग उनके प्रति स्नेह व सम्मान का भाव रखेंगे, तभी सही मायने में हमारी-आपकी बेटियां निर्भय होकर अपने सपने पूरे करने की राह पर आगे बढ़ सकेंगी।

लाइफ स्किल

सद्भावपूर्ण हों संबंध

कार्यस्थल पर आपसी खींचतान, मतभेद होने पर इन्हें संभालें। भावुकता में काम न बिगाड़ें। कामकाज ही नहीं, आपके प्रदर्शन पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है...

सहयोगी से विचार नहीं मिलता। छोटी-सी बात पर बन जाता है बतंगड़। टीम में कैसे रहें, कैसे चलें, जब सब अपनी-अपनी चलाते हैं। ये कुछ ऐसे सवाल हैं, जिसका हम सभी सामना करते हैं। कार्यस्थल पर ये कोई नई बात नहीं है। ऐसे कई मौके होते हैं, जब बात बहुत बढ़ जाती है और विवाद के कारण आपसी रिश्ते भी खराब होने लगते हैं। स्वाभाविक है परिवार की तरह यहां भी खराब रिश्ता आपके प्रदर्शन व संस्थान के कामकाज पर असर डालता है। ऐसे में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए।

संवाद है कुंजी: संवाद वह कुंजी है, जिससे बड़ी से बड़ी समस्या का निदान संभव है। यदि आप खुलकर अपनी बात नहीं कर पाते तो संभव है वह विवाद बना रहेगा। विषय को समझकर ही आगे बढ़ा जा सकता है और आगे बढ़ने के लिए सबसे अधिक जरूरी है कि आप संवाद करें। विनम्र होकर बात करें। असरकारक संवाद का लाभ अवश्य मिलता है, भरोसा रखें। पूर्वधारणा से उबरें, विविध प्रकार की संस्कृति व विचारों के बीच एक टीम में काम करना तभी संभव है, जब आपके विचारों में खुलापन हो। यह स्वीकार करें कि सब अलग-अलग पृष्ठभूमि से आए लोग हैं। उनके साथ तालमेल बिठाकर ही आप सहजता से चल सकते हैं। ऐसे में जब कभी विवाद सामने आए तो आपको सबसे पहले पूर्वधारणाओं से बचना होगा। नकारात्मक बातों को देखना सही नहीं है, कुछ अच्छी बातें भी होंगी आपके सहयोगियों में, उन्हें स्वीकारें और आगे बढ़ें।

सकारात्मक हो व्यवहार: विभिन्न मत वाले लोगों के साथ काम करते हैं तो आपको झल्लाने या बहस करने के बजाय अपना व्यवहार सकारात्मक रखना चाहिए। किसी सहयोगी के नकारात्मक व्यवहार को अपने ऊपर हावी न होने दें। हालांकि कामकाज के दौरान ऐसी चुनौतियां कई बार आती हैं लेकिन यहीं पर होती है आपकी भावनात्मक बुद्धि की परीक्षा। आप नकारात्मक परिस्थितियों को कैसे संभालते हैं, भावुक पलों में कैसे उबरकर सही निर्णय लेते हैं, यही आपकी पहचान होती है।

लचीलापन कितना है: कामकाज के दौरान ऐसी स्थिति कई बार बनती है, जब आपको अपने तय किए मानदंडों के विरुद्ध चलना होता है। कई बार लचीलापन अपनाना होता है। ऐसा करना आपको गलत लग सकता है, पर सहयोगियों से बेहतर रिश्ता हो और आपका कामकाज भी सही तरीके से आगे बढ़ता रहे, इसके लिए यह आवश्यक हो जाता है।

सीमा झा

जाब स्किल

करें करियर की प्लानिंग

बढ़ती प्रतिस्पर्धा को देखते हुए पढ़ाई के साथ-साथ ही करियर की भी प्लानिंग करने की जरूरत होती है। इससे आप अपने लक्ष्य को लेकर फोकस्ड रहते हैं और सही रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। आखिर क्यों इतनी महत्वपूर्ण है करियर की प्लानिंग और इसे हमें कब से शुरू कर देना चाहिए, ताकि अपने सपनों की नौकरी हासिल करने में आसानी हो...

करियर प्लानिंग का मतलब यहां भविष्य की तैयारी से है। इसके मायने हर किसी के लिए अलग हो सकते हैं। हालांकि आज जिस तरह से करियर की चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में स्पर्धा का स्तर जिस तरह से कठिन होता जा रहा है, उसे देखते हुए अब समय आ गया है कि हमें इसका महत्व पढ़ाई के समय से ही समझना शुरू कर देना चाहिए। इससे आपको न सिर्फ सपनों की नौकरी हासिल करने में आसानी होगी, बल्कि आप जाब मार्केट में औरों से अलग भी दिखेंगे। लेकिन इसके लिए कुछ पहलुओं पर गंभीरता से ध्यान देना होगा, जैसे किः

लक्ष्य हो स्पष्ट: आज का समय पहले जैसा नहीं है, जब लोगों को बहुत से करियर के बारे में पता नहीं होता था। लोगों का पूरा ध्यान केवल पढ़ाई पूरी करने पर होता था। आज स्मार्टफोन और इंटरनेट की उपलब्धता होने से सब कुछ आसान हो गया है। बस एक क्लिक पर हर जानकारी हमें अपने फोन पर ही मिल जाती है। ऐसे में सवाल यह है कि करियर की प्लानिंग हमें कब से शुरू कर देनी चाहिए? इसका आसान सा जवाब है, आपको यह प्लानिंग नौवीं से ग्यारहवीं के बीच शुरू कर देनी चाहिए। वैसे तो देखा जा रहा है कि जिन बच्चों के अभिभावक जागरूक हैं, वे बचपन से ही अपने बच्चों की मेंटरिंग इस तरह करना शुरू कर देते हैं कि बच्चा जब तक छठी में पहुंचता है, उसमें करियर को लेकर काफी स्पष्टता आ चुकी होती है, लेकिन हमारे करियर का सबसे अहम पड़ाव शुरू होता है कक्षा नौवीं से, जब हमें अपने करियर को लेकर सजग हो जाने की जरूरत होती है। क्योंकि कक्षा नौंवी के स्ट्रीम और विषय से ही आगे चलकर काफी हद तक आपके करियर की दिशा तय होती है। उदाहरण के लिए, यदि आप स्टेम (साइंस, टेक्नोलाजी, इंजीनियरिंग व मैथमैटिक्स) से जुड़े क्षेत्रों में करियर बनाने का सोच रहे हैं, तो यही वह समय है, जब आपको अपने करियर लक्ष्यों के बारे में सही से पता हो जाना चाहिए। इसके बाद करियर की प्लानिंग का दूसरा पड़ाव शुरू होता है 10वीं के बाद। जब आप ग्यारहवीं में पहुंचते हैं, तो यह जीवन का दूसरा ऐसा अवसर होता है, जब करियर को लेकर अधिक एकाग्र होने की जरूरत होती है।

पहचानें अपना जुनून: यहां जुनून से मतलब उस काम से है, जिसे करने में आपको खुशी मिलती है, जिसके लिए हम अपना भूख-प्यास सब भूल जाते हैं। जरूरी नहीं कि यह किसी विषय की पढ़ाई ही हो। यह जुनून किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हो सकता है। बस जरूरत यह है कि अपने उस जुनून को पहचानकर उसी दिशा में खुद को आगे बढ़ाएं।

कौशल विकास पर दें ध्यान

करियर प्लानिंग करते समय नए और जरूरी कौशल सीखने की तरफ भी हमारा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि आज के दौर में सिर्फ डिग्री हासिल कर लेने से कुछ नहीं होने वाला है, जब तक कि आपके पास जाब लायक कोई स्किल नहीं है। हार्ड स्किल से इतर यह कोई तकनीकी स्किल भी हो सकती है या फिर साफ्ट स्किल भी, जिसकी नौकरियों में जरूरत पड़ती है।

धीरेंद्र पाठक

वर्ग पहेली-2730

बाएं से दाएं
1. शैतानी, दुष्टता (4)।
3. दक्षिण भारत की एक भाषा (5)।
6. छल, धूर्तता, तिकड़म (3)।
7. स्वीकृति (4)।
8. दूसरे के भरोसे रहने वाला (4)।
10. लिहाफ (3)।
12. प्रेम और सौंदर्य की देवी (3)।
14. उदास, संतप्त, दुखी (4)।
18. जिसमें समझ की कमी हो (4)।
19. अंगूठी (3)। 20. इन्हें मिली विद्यासागर की उपाधि (3,2)।
21. नीला वस्त्र पहनने वाला (4)।

ऊपर से नीचे
1. भारत के एक प्रसिद्ध शायर (5)।
2. भाग्य, किस्मत (4)। 3. घड़ा, गगरी (3)।
4. खानाबदोश, घुमंतू (4)। 5. लिखकर अपनी जीविका चलाने वाला (4)।
9. जिंदगी (3)। 11. दुष्ट, जुल्मी (3)।
13. समझ रखने वाला (5)।
14. गहरापन, गंभीरता (4)।
15. गीत रचने वाला (4)।
16. टालमटोल (2,2)।
17. समंदर, सागर (3)।

कल का हल

स	मा	नां	त	र		श	ह	ना	ई
ह				म	ह	क			मा
दे		का		झो		ट	न		न
ब	द	न		ला					दा
	बा					द	र	का	र
स	ना	त	न					य	
म					प		हे	ल	न
झ		खा	स		थ		ली		र
दा			ब	क	री				मा
र	म	गी	क		लो	ज	ब	चा	ना

जागरण सुडोकू-2730

4		5		6		7		3
			8		9			
9		2		4		6		8
3	6		9		7		4	
				5				1
	5			2		9		
7		6		9		1		4
			4		3		7	
	4			7				9

कल का हल

8	3	9	4	2	6	5	7	1
1	6	2	7	5	3	4	9	8
7	4	5	8	1	9	2	6	3
5	1	8	3	9	4	7	2	6
2	9	4	1	6	7	8	3	5
6	7	3	5	8	2	1	4	9
9	8	7	6	4	5	3	1	2
4	5	6	2	3	1	9	8	7
3	2	1	9	7	8	6	5	4

आज का भविष्यफल-24 अगस्त, 2024 शनिवार
के. ए. दुबे पद्मेश

आज की ग्रह स्थिति : भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष पंचमी।
आज का राहुकाल : प्रातः 09 बजे से 10 बजकर 30 मिनट तक। आज का दिशाशूल : पूर्व।
आज का पर्व एवं त्योहार : हल षष्ठी व्रत। विशेष : षष्ठी तिथि की क्षय, शुक्र कन्या में।

कल 25 अगस्त, 2024 का पंचांग
कल का दिशाशूल : पश्चिम
कल का पर्व एवं त्योहार : शीतला सप्तमी
कल की भद्रा : प्रातः 05 बजकर 31 मिनट से सायं 04 बजकर 35 मिनट तक।
विशेष : बुधउदय, षष्ठी तिथि की क्षय
वर्षा ऋतु भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी तत्पश्चात अष्टमी, भरणी नक्षत्र तत्पश्चात कृतिका नक्षत्र, ध्रुव योग तत्पश्चात व्याघात योग, मेष में चंद्रमा तत्पश्चात वृष में।

6 के. शु. | 4 बु. | 7 | 5 सू. | 3 | 8 | 2 गु. मं. | 9 | 11 श. | 1 चं. | 10 | 12 रा.

मेष : स्नान करते समय सावधानी बरतें। शिक्षा में सफलता मिलेगी।
वृष : व्यावसायिक प्रयास फलीभूत होगा, फिर भी मन अशांत रहेगा।
मिथुन : झगड़ा विवाद से बचें। विरोधी सक्रिय रहेगा। स्वास्थ्य से सचेत रहें।
कर्क : घर के मुखिया का सहयोग मिलेगा। रिश्तों में निकटता आएगी।
सिंह : आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें।
कन्या : तनाव मिल सकता है। व्यक्ति विशेष का सहयोग रहेगा।
तुला : रचनात्मक प्रयास फलीभूत होंगे। जीवन सुखमय होगा।
वृश्चिक : व्यावसायिक कार्य फलीभूत होगा। व्यर्थ की उलझनें रहेंगी।
धनु : उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
मकर : रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। व्यावसायिक कार्य हल होंगे।
कुंभ : अधीनस्थ कर्मचारी से तनाव मिल सकता है। भागदौड़ रहेगी।
मीन : आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें।

मथुरा में जन्माष्टमी पर 25 लाख से अधिक श्रद्धालु आने की संभावना, भीड़ संभालना चुनौती

जागरण संवाददाता, मथुरा

भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव पर श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर ठाकुरजी पद्मकांति पुष्प बंगले में विराजमान होंगे। सोम चंद्रिका पोशाक धारण करेंगे। जन्मस्थान पर 5251 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। जन्मोत्सव 26 अगस्त को होगा, लेकिन ठाकुरजी को पोशाक 25 अगस्त को अर्पित की जाएगी। शाम को शोभायात्रा निकलेगी। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर 25 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 25 अगस्त की शाम को आएंगे। वह डैंपियर नगर में नवनिर्मित पांचजन्य प्रेक्षागृह का लोकार्पण करने के साथ नौ अरब से अधिक की विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे।

अगले दिन सुबह योगी श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर दर्शन करेंगे। ऐसे में भीड़ को नियंत्रित करना और दोनों दिन रूट डायवर्जन करना, पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगी। हालांकि, इस बार ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में वर्ष में एक बार होने वाली मंगला आरती 27 अगस्त को रात दो बजे होगी। डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह का कहना है कि जन्मोत्सव में सीएम के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर भी तैयारियां तेज हैं, श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी।

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व निकट है। हर ओर इस संबंध में विविध आयोजन हो रहे हैं। शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित कमानी आडिटोरियम में नृत्य नाटिका 'कृष्ण' का आयोजन किया गया। इस दौरान कलाकारों ने श्रीकृष्ण के विभिन्न स्वरूपों की अद्भुत प्रस्तुति से दर्शकों का मन मोह लिया। प्रेट्र

श्रीराम मंदिर ट्रस्ट ने भूमि की खरीदारी पर खर्च किए 280 करोड़

प्रवीण तिवारी, जागरण ● अयोध्या : श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की गुरुवार को संपन्न हुई बैठक में दान का विवरण देने के साथ ही खर्च का पूरा लेखा-जोखा भी प्रस्तुत किया गया। बैठक में जमीन के क्रय का विवरण दिया गया। इसमें उल्लेख है कि चार वर्ष यानी जुलाई 2020 से अगस्त 2024 तक 35.29 एकड़ भूमि की खरीद पर 280 करोड़ रुपये खर्च हुए। खरीदे गए भूखंड मंदिर के निटकवर्ती क्षेत्र के साथ नगर में अन्य स्थानों पर हैं। 64 परिवारों ने इन जमीनें का ट्रस्ट को बैनामा किया है। ट्रस्ट के एक सदस्य के अनुसार ट्रस्ट की ओर से श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं के साथ मंदिर परिसर के विस्तार के लिए व्यापक स्तर पर जमीनों की खरीदारी की जा रही है। इसमें श्रद्धालुओं के ठहरने को विश्राम स्थल के निर्माण सहित कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं शामिल हैं। भूमि की खरीद के अतिरिक्त भूमि व भवनों की अदला-बदली पर भी कई करोड़ रुपये खर्च हुए।

फिर खुला पुरी में महाप्रभु का रत्न भंडार, अलमारियां और संदूक स्थानांतरित

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर

पुरी जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को पूर्व निर्धारित तिथि के अनुसार शुक्रवार को पुनः खोला गया। इस दौरान जगन्नाथ मंदिर के आंतरिक एवं बाहरी रत्नभंडार में मौजूद लकड़ी और स्टील की चार अलमारियों व तीन संदूकों को नीलाद्री म्यूजियम के पास मौजूद कक्ष में स्थानांतरित किया गया है। इन अलमारियों व बक्सों से रत्न-आभूषणों को निकाल कर पहले ही नए बक्सों में सुरक्षित रखा जा चुका है।

इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जगन्नाथ मंदिर परिसर में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए थे। जगन्नाथ मंदिर जांच कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस विश्वनाथ रथ, मंदिर के मुख्य प्रशासक के अलावा टेक्निकल टीम, दमकल एवं स्नेक हेल्पलाइन के सदस्य मंदिर परिसर में तैनात रहे। बताते चलें कि इससे पहले 14 जुलाई को बाहरी एवं 18 जुलाई को आंतरिक रत्न भंडार खोला गया था। उसी समय रत्न भंडार में मौजूद मूल्यवान आभूषणों एवं रत्नों को अस्थायी रत्न भंडार में स्थानांतरित किया गया था। अब जबकि रत्न भंडार से खाली संदूकों और बक्सों को हटाया जा चुका है, पूर्व निर्धारित योजना के तहत अब रत्न भंडार की दीवारों व अन्य हिस्सों की मरम्मत का कार्य शुरू होगा।

मंदिर में प्रवेश करते रत्न भंडार जांच कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस विश्वनाथ रथ। जागरण

'दुखद है कि अदालतें विश्वासघात व धोखाधड़ी में अंतर नहीं समझतीं '

- शीर्ष अदालत ने कहा, दोनों अपराध स्वतंत्र और अलग हैं
- समय आ गया है कि पुलिस को कानून का उचित प्रशिक्षण दिया जाए

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि यह बहुत दुखद है कि अदालतें आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी के बीच सूक्ष्म अंतर को नहीं समझ पाई हैं, जबकि यह दंडात्मक कानून 162 सालों से अधिक समय से लागू है। शीर्ष अदालत ने कहा कि दुर्भाग्य से पुलिस के लिए यह एक आम चलन है कि किसी तरह की बेईमानी या धोखाधड़ी के केवल आरोप पर दोनों अपराधों के लिए बिना किसी उचित समझ-बूझ के नियमित और यंत्रवत प्राथमिकी दर्ज की जाती है।

जस्टिस जेबी पार्डीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि अब समय आ गया है कि देशभर के पुलिस अधिकारियों को कानून का उचित प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के अपराधों के बीच के बारीक अंतर को समझा जा सके। पीठ ने कहा, दोनों अपराध स्वतंत्र और अलग हैं। दोनों अपराध एक तरह के तथ्यों की स्थिति में साथ-साथ नहीं हो सकते। वे एक-दूसरे के विपरीत हैं।

शीर्ष अदालत ने इस साल अप्रैल में इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। हाई कोर्ट ने दिल्ली रेस क्लब लिमिटेड और अन्य के खिलाफ शिकायत को लेकर उत्तर प्रदेश की एक ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित समन आदेश को रद करने से इन्कार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निजी शिकायत पर विचार करते समय कानून मजिस्ट्रेट को सावधानीपूर्वक जांच करने की जिम्मेदारी देता है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या बयान के आधार पर धोखाधड़ी या आपराधिक विश्वासघात का अपराध बनता है।

सुप्रीम कोर्ट। फाइल

जहरीली शराब से मौत के मुद्दे पर ओडिशा विस में हंगामा, माइक को तोड़ने का प्रयास

- प्रश्न काल के दौरान आबकारी मंत्री के इस्तीफे की मांग
- विधानसभा अध्यक्ष के पोडियम पर चढ़े बीजद विधायक

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर

ओडिशा के गंजाम जिले में जहरीली शराब से हुई मौत के मामले को लेकर ओडिशा विधानसभा में शुक्रवार को जमकर हंगामा हुआ। प्रश्न काल के दौरान आबकारी मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए विरोधी दल बीजद एवं कांग्रेस के विधायकों ने जमकर बवाल काटा। बीजद के विधायक विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी के पोडियम पर चढ़ गए और उनके माइक को तोड़ने का प्रयास किया। सदन में हंगामा जारी रहने से विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को पहले 11:30 बजे तक एवं फिर चार बजे तक के लिए स्थगित कर दिया।

सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजद के सदस्य सदन के मध्य भाग में आ गए और हल्ला करने लगे। इस दौरान सोर विधायक माधव धड़ा एवं देवगढ़ विधायक रोमांच बिश्वाल की वहां तैनात मार्शल के साथ धक्का-मुक्की भी हुई। बाद में पत्रकारों से मुखातिब विधायक माधव धड़ा ने कहा कि जनतांत्रिक तरीके से हमने विराध प्रदर्शन किया। हमने किसी सीमा का उल्लंघन नहीं किया है। इधर, सत्तर पक्ष के चिकिटी विधायक मनोरंजन ज्ञान सामंतराय ने कहा कि विरोधी दल को विधानसभा अध्यक्ष को सम्मान देना नहीं आता। पोडियम पर चढ़कर विपक्ष के विधायक ने जिस प्रकार का आचरण किया, वह निंदनीय है। सत्य का सामना करने से विरोधी दल के विधायक डर रहे हैं। 24 वर्ष के शासन में भ्रष्टाचार व्याप्त था। उसका पर्दाफाश हो रहा है तो चर्चा करने से विरोधी डर रहे हैं। आबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा कि शराब से हुई मृत्यु के मामले में सरकार तथ्य नहीं छिपा रही है। विरोधी दल का आरोप आधारहीन एवं मनगढ़ंत है।

विधानसभा अध्यक्ष के पोडियम पर चढ़ने का प्रयास करते बीजद विधायक।

एडीआरडीई ने सैनिकों के लिए तैयार की नई पैराशूट प्रणाली

- 30 हजार फीट की ऊंचाई से लगाई जा सकती है छलांग
- डीआरडीओ-इसरो के विज्ञानियों की मौजूदगी में परीक्षण

जागरण संवाददाता, आगरा

हवाई वितरण अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान (एडीआरडीई) के विज्ञानियों ने सैनिकों के लिए नई पैराशूट प्रणाली तैयार की है। युद्ध के समय यह प्रणाली जवानों के लिए अहम साबित होगी। इसकी मदद से सैनिक 30 हजार फीट की ऊंचाई से भी छलांग लगा सकेंगे। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में उतर सकेंगे। यह प्रणाली अभी अमेरिका सहित कई विकसित देशों के पास है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के विज्ञानियों की मौजूदगी में गुरुवार को इसका सफल परीक्षण किया गया।

देश में केवल एडीआरडीई में ही पैराशूट का डिजाइन और उसके परीक्षण किए जाते हैं। तीन वर्ष पहले विज्ञानियों ने सैन्य लड़ाकू पैराशूट प्रणाली (एमसीपीएस) और हाई एल्टीट्यूड पैराशूट विद नेविगेशन एंड एडवांस सब असेंबलीज (हंस) पर कार्य शुरू किया था। इसमें जंपर के लिए एक विशेष तरीके का सूट तैयार किया गया है। इस सूट में ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, पैरा कंप्यूटर, इंटर पर्सनल रेडियो, मैग्नेटिक कंपास और हेलमेट लगे हैं। इस सूट के साथ एक विशेष पैराशूट जोड़ा गया है। दोनों को मिलाकर सैन्य लड़ाकू पैराशूट प्रणाली तैयार की गई है। इस प्रणाली के अब तक कई परीक्षण किए जा चुके हैं। प्रारंभिक डिजाइन में कुछ बदलाव भी किया गया है। गुरुवार को चीफ टेस्ट जंपर विंग कमांडर विशाल लाकेश ने सैन्य लड़ाकू पैराशूट प्रणाली का अंतिम परीक्षण किया।

यह है विशेषता

यह प्रणाली 15 वर्ष तक कार्य करेगी। अधिकतम 200 किग्रा का वजन उठाने में कारगर है। 30 हजार फीट की अधिकतम ऊंचाई से कूदा जा सकता है। इसके साथ 80 लीटर का आक्सीजन सिलेंडर भी लगा है। नीचे उतरने की गति 280 किमी प्रति घंटा होती है।

****

भारत आया ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज

ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज हेक्टर 1608 में आज ही के दिन व्यापार के लिए गुजरात के सूरत के तट पर पहुंचा था। इस जहाज के कैप्टन विलियम्स हाकिन्स थे। उस समय यह कोई नहीं जानता था कि व्यापार के लिए आई ये कंपनी करीब 200 वर्ष तक पूरे भारत पर राज करेगी।

माइक्रोसाफ्ट ने जारी किया आपरेटिंग सिस्टम विंडोज 95

टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने 1995 में आज ही के दिन आपरेटिंग सिस्टम विंडोज 95 आम लोगों के लिए जारी किया था। ये इतना ज्यादा लोकप्रिय हुआ कि पांच हफ्ते में ही इसकी 70 लाख से ज्यादा कापियां बिक गई थीं। इसे माइक्रोसाफ्ट का सबसे सफल आपरेटिंग सिस्टम भी माना जाता है।

उग्र राष्ट्रवाद में विश्वास करते थे महान क्रांतिकारी राजगुरु

महान क्रांतिकारी शिवराम राजगुरु का जन्म 1908 में आज ही के दिन महाराष्ट्र में पुणे के खेड़ में हुआ था। बचपन में भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचार को देखा। आगे चल कर भगत सिंह और चंद्रशेखर के साथ क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए। राजगुरु को ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जेपी सांडर्स की हत्या में उनकी भूमिका के लिए याद किया जाता है। इस मामले में राजगुरु को गिरफ्तार किया गया और क्रांतिकारी साथियों के साथ 23 मार्च, 1931 को लाहौर में फांसी दी गई।

आम की गुठली बनाएगी कपड़ों को बैक्टीरिया रोधी

शोध ▶ उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान (यूपीटीटीआइ) की डा. नीलू कांबो के अनुसंधान को मिला पेटेंट

स्वास्थ्य कर्मियों के कपड़े सुरक्षित बनाना हो सकेगा आसान

जागरण संवाददाता, कानपुर

आम के आम और गुठलियों के दाम, इसे आपने मुहावरे में ही सुना होगा लेकिन अब वहीं आम की गुठली बाजार में अपनी अहमियत बताने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान (यूपीटीटीआइ) की विज्ञानी डा. नीलू कांबो और उनके सहयोगी डा. सौरभ दुबे ने अपने शोध से आम की गुठली से कपड़ों और खाद्य पदार्थों को बैक्टीरिया व फंगस रोधी बनाने की विधि विकसित की है। उनके अनुसंधान को भारत सरकार का पेटेंट भी मिल गया है। अब विधि को बाजार में उतारने की तैयारी है।

डा. नीलू कांबो ने बताया कि आम की गुठली को अभी तक बेकार समझकर फेंक दिया जाता है। आम के अचार, जैम और जूस बनाने वाले उद्योगों से बड़े पैमाने पर गुठली का कचरा बाहर फेंका जाता है। अब इस गुठली का प्रयोग बैक्टीरिया और फंगस रोधी पदार्थ बनाने में किया जा सकेगा। इसके लिए आम की गुठली और खाद्य उद्योगों में प्रयोग होने वाले पदार्थों का प्रयोग किया गया है। इससे एक नैनो इमल्शन (निरंतर चरण में नैनो आकार की बूंदों का फैलाव) प्राप्त हुआ है, जो पूरी तरह जैविक है। इसे तैयार करने में रसायन का प्रयोग नहीं किया गया है। इसका प्रयोगशाला में परीक्षण किया गया तो पता चला कि इसमें एंटी माइक्रोबियल तत्व मौजूद हैं, जो विभिन्न तरह के बैक्टीरिया को रोकने में सक्षम हैं। बैक्टीरिया के बाद फंगस पर भी प्रयोग किया गया तो परिणाम सकारात्मक रहे। आठ तरह के फंगस को भी यह पदार्थ नष्ट कर देता है।

अनुसंधान के दौरान आम की गुठली से प्राप्त एंटीमाइक्रोबियल संरचना। संस्थान

प्रोजेक्ट में सहयोगी डा. सौरभ दुबे। संस्थान

कपड़ों और मांस पर किया जा सकेगा प्रयोग

डा. नीलू कांबो ने बताया कि इस तरल पदार्थ का स्प्रे करने से कपड़ों पर बैक्टीरिया का असर नहीं हुआ। इस तरह से कपड़ों को सुरक्षित रखा जा सकता है। स्वास्थ्य कर्मियों के प्रयोग वाले कपड़ों पर इसकी कोटिंग की जा सकेगी। इससे कपड़ों को अधिक समय के लिए सुरक्षित किया जा सकेगा। खाद्य पदार्थों में मांस पर बैक्टीरिया का हमला सबसे तेजी के साथ होता है। मांस की पैकिंग पर अगर इसका स्प्रे किया जाए तो पैकेट पर बैक्टीरिया का असर नहीं होगा। घरों और कार्यालयों के फर्श की सफाई के लिए भी प्रयोग किया गया है। डा. नीलू ने बताया कि आम की गुठलियों से तैयार स्प्रे का उपयोग अलग-अलग फंगस व माइक्रोब पर किया गया, जो सफल रहा। ग्राम (प्लस) और ग्राम (माइनस) स्ट्रेन के माइक्रोब के साथ आठ प्रकार के फंगस (जियोट्रिचमकैन डिडम, राइजोक्टोनिया बटाटिकोला, स्क्लेरोटियम राल्फसी, एक्सिइयसप, फाइटोफ्थोरा कासेसी, पेस्टलोटिप्सिस पी, राइजोक्टोनिया सोलानी व कोलेटोट्राइकम कैप्सिसी) पर रिसर्च की गई है।

बैक्टीरिया रोधी पदार्थ विकसित करने वाली यूपीटीटीआइ की डा. नीलू कांबो। संस्थान

अंतरिक्ष यात्रियों को निजी स्पेसवाक पर भेज सकता है स्पेसएक्स

वाशिंगटन, रायटर : एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स अब तक के सबसे जोखिम भरे मिशनों में से एक पोलारिस मिशन को अगले हफ्ते मंगलवार को भेजने को तैयार है। इसमें स्पेसवाक के साथ ही स्लिम स्पेससूट और बिना एयरलाक वाले केबिन सहित अन्य परीक्षण किए जाएंगे। यह पहली बार होगा, जब किसी निजी कंपनी के अभियान में स्पेसवाक शामिल है। यह परीक्षण भविष्य के चंद्रमा, मंगल मिशन को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। इस मिशन पर जाने वाले चार सदस्य अन्ना मेनन, स्काट पोटेट, सारा गिलिस और अरबपति जेरेड इसाकमैन हैं।

ये सभी अंतरिक्ष में 700 किमी की ऊंचाई पर 20 मिनट की स्पेसवाक करेंगे। अब तक, अंतरिक्ष में स्पेसवाक प्रयास केवल सरकारी अभियानों में अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पृथ्वी से 400 किमी ऊपर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किया गया है। स्पेसएक्स का पांच दिवसीय मिशन पोलारिस डान अंडाकार आकार की कक्षा में घूमेगा, जो पृथ्वी के करीब 190 किमी और 1,400 किमी दूर से गुजरेगा। 1972 में अमेरिका के अपोलो चंद्रमा कार्यक्रम की समाप्ति के बाद से किसी भी इंसान द्वारा की गई सबसे दूर की यात्रा होगी।

पृथ्वी के वायुमंडल के सुरक्षात्मक आवरण से बहुत दूर क्रू ड्रैगन और स्पेससूट और अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरणों का परीक्षण किया जाएगा, क्योंकि वे सभी वैन एलन बेल्ट के कुछ हिस्सों से गुजरेंगे। यह एक ऐसा क्षेत्र है, जहां मुख्य रूप से सूर्य से आने वाले आवेशित कण उपग्रहों के इलेक्ट्रानिक्स को बाधित कर सकते हैं और मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। यह एक अतिरिक्त जोखिम है, जिसका सामना तब नहीं करना पड़ता जब आप पृथ्वी की निचली कक्षा में रहते हैं और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक जाते हैं।

- पहली बार किसी निजी कंपनी के अभियान में स्पेसवाक को शामिल किया गया है
- स्लिम स्पेससूट और बिना एयरलाक वाले केबिन सहित अन्य परीक्षण भी होंगे

मिशन पर जाने वाले चार सदस्य, बाएं से, अन्ना मेनन, स्काट पोटेट, जेरेड इसाकमैन तथा सारा गिलिस। फाइल/एपी

स्टारलाइनर या ड्रैगन कैप्सूल किससे लौटेंगी सुनीता विलियम्स आज तय होगा

केप केनावेरल, एपी : सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर को बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान या स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल से पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा इस पर नासा शनिवार को अंतिम निर्णय ले सकता है। इसे लेकर प्रशासक बिल नेल्सन और अन्य शीर्ष अधिकारी शनिवार को बैठक करेंगे। अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स ने पांच जून को बोइंग के स्टारलाइनर से उड़ान भरी थी। उन्हें अंतरिक्ष स्टेशन से लगभग एक सप्ताह बाद ही लौटना था। लेकिन इस परीक्षण उड़ान में थ्रस्टर विफलताओं का सामना करना पड़ा था और हीलियम का रिसाव इतना गंभीर हो गया कि नासा ने स्टारलाइनर को अंतरिक्ष स्टेशन पर डाक कर दिया।

तीसरी बार भी अबू धाबी करेगा आइफा की मेजबानी

एंटरटेनमेंट ब्यूरो, मुंबई : संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में लगातार तीसरी बार इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी (आइफा) अवार्ड्स 2024 का आयोजन होगा। आइफा का 24वां संस्करण 27 सितंबर से 29 सितंबर तक अबू धाबी के यास आइलैंड में स्थित इतिहाद अरीना में होगा।

इस साल मुख्य आइफा अवार्ड्स की मेजबानी अभिनेता शाह रुख खान और निर्देशक-निर्माता करण जौहर मिलकर करेंगे। शाह रुख ने कहा कि आइफा भारतीय सिनेमा का एक ऐसा उत्सव है, जिसकी गूंज दुनिया भर में है।

मैं इस अवार्ड की ऊर्जा और भव्यता को फिर से जीवंत करने के लिए उत्सुक हूं। इस बार पांच फिल्म इंडस्ट्री एक साथ अबू धाबी में जमा होंगी। हिंदी सिनेमा के साथ दक्षिण भारतीय सिनेमा की तमिल, तेलुगु, मलयालम व कन्नड़ फिल्मों के सितारों संग आइफा उत्सवम मनाया जाएगा।

तिकड़म ★★★

फिल्म रिव्यू मुख्य कलाकार : अमित सियाल, दिव्यांश द्विवेदी, आरोही साउद, अरिष्ट जैन, नयन भट्ट, अजीत खातम केलकर, निर्देशक : विवेक अंचलिया, अवधि : एक घंटे 58 मिनट, प्रसारण प्लेटफार्म : जियो सिनेमा

बच्चों संग हर कलाकार की दमदार एक्टिंग

जागरण फिल्म फेस्टिवल 2023 में स्पेशल मेंशन फिल्म का अवार्ड पाने वाली तिकड़म जियो सिनेमा पर रिलीज हो गई है।

कहानी शुरू होती है पर्यटन स्थल माने जाने वाले सुखताल में एक होटल में काम कर रहे प्रकाश (अमित सियाल) से, जो कम वेतन में भी अपने बच्चों के साथ खुश है। सुखताल में कई साल से बर्फ नहीं पड़ रही है, इसलिए वहां के होटल बंद हो रहे हैं। प्रकाश की नौकरी भी जाने वाली है। प्रकाश अपने बच्चों की ख्वाहिशों को भी पूरा नहीं कर पा रहा। उसे होटल की ओर से मुंबई में काम मिल जाता है। जब उसके बच्चों चीनी (आरोही साउद) और समय (अरिष्ट जैन) को पता चलता है कि पिता शहर जाने की तैयारी में हैं, तो वे अपने स्कूल के दोस्त भानु (दिव्यांश द्विवेदी) के साथ मिलकर सुखताल में बर्फ गिरवाने की तिकड़में करते हैं, ताकि जो लोग नौकरी खोकर दूर शहरों में गए हैं, वे वापस आ सकें। उनका नारा होता है बर्फ गिराओ, पापा लाओ। फिल्म की कहानी अनिमेश वर्मा की है, जबकि इसकी पटकथा और संवाद पंकज निहलानी और विवेक ने लिखे हैं। फिल्म की सबसे सुंदर बात इसकी सादगी है, जो बिना किसी शोरशराबे के बच्चों के जरिए अहम संदेश देती है। पिता और बच्चे के बीच के अटूट बंधन को भावनाओं की चाशनी में डुबोकर दिखाती है। विवेक की यह पहली फीचर फिल्म है, उनकी पकड़ निर्देशन पर मजबूत है। पेड़ बचाओ, प्लास्टिक पर प्रतिबंध, प्रदूषण नियंत्रण जैसे कई मुद्दों पर बात करते हुए फिल्म हल्के-फुल्के तरीके से आगे बढ़ती है।

पिता कहता है कि चिड़िया खाना लाने के लिए बाहर जाती है, वैसे मुझे भी जाना पड़ेगा। इस पर बच्चों का कहना कि चिड़िया हर रात वापस आती है, आप आओगे? या चीनी का अपने पिता को कपड़े सूटकेस में रखने से रोकना... मासूमियत से भरपूर ये दृश्य भावुक करते हैं। सुखताल की सुंदरता को सिनेमैटोग्राफर पार्थ सयानी ने कैमरे में कैद करने में कोई कमी नहीं रखी है। कुछ चीजें खटकती भी हैं, जैसे चीनी जैसे बात करती है, वह उसके भाई के सिवा किसी की समझ नहीं आती।

अभिनय में अमित सियाल पूरे नंबर पाने के हकदार हैं। एकल पिता की जिम्मेदारियों, अच्छे बेटे, पेशेवर जीवन में ईमानदार, हर रूप में वह फिट लगे हैं। तीनों बच्चे आरोही साउद, समय और दिव्यांश द्विवेदी छोटा पैकेट बड़ा धमाका हैं। नयन भट्ट का काम बेहतरीन है। दादू की भूमिका में अजीत सर्वोत्तम केलकर जब पोते-पोती को कहानियां सुनाते-सुनाते जीवन की असल बात समझा जाते हैं, उससे बुजुर्गों की अहमियत समझ आती है।

बादल के आगे चल जाकर झांके, चंदा के ऊपर एक झूला बांधे..., जिंदगी है ये खेल एक प्यारे..., क्या ना उठा ले चींटी जो झुंड हो साथ इकट्ठा... ये सभी गाने न केवल फिल्म को दिलचस्प बनाते हैं, बल्कि कहानी को भी आगे बढ़ाते हैं।

अमित सियाल एकल पिता की जिम्मेदारियां निभाने के साथ हर रूप में फिट लगे हैं।

चित्र सौ. : फिल्मटीम

प्रियंका सिंह

★★★★★ उत्कृष्ट ★★★★ बहुत अच्छी ★★★ अच्छी ★★ औसत ★ औसत से कम

अपनी राय हमें जरूर बताएं : feature@jagran.com

इधर-उधर की

...ऐसे दरियादिल भी होते हैं मकान मालिक

पांच वर्ष से नहीं बढ़ाया किराया, डिनर भी कराया। इंटरनेट मीडिया

बेंगलुरु, एजेंसी: आम तौर मेट्रो शहरों में किराए के घर में रहने वालों की शिकायत होती है। लेकिन कुछ मकान मालिक दयालु भी होते हैं। ऐसे ही एक मकान मालिक के अच्छे व्यवहार के बारे में एक किराएदार ने इंटरनेट मीडिया पर अनुभव साझा किया है। किराएदार ने लिखा है कि उनके मकान मालिक ने पिछले पांच वर्ष से किराया नहीं बढ़ाया है और वे कभी-कभी उनके लिए डिनर भी खरीदते हैं। किराएदार ने रेडिट पर लिखा है कि हाल में 65 वर्षीय मकान मालिक मेरे लिए डिनर का पैकेट लेकर आए। उनके इस व्यवहार से मैं भावुक हो गया। किराएदार का कहना है कि वे 2018 से इस घर में रह रहे हैं और आज भी उतना ही किराया दे रहे हैं, जिस किराए पर घर लिया था।

एचपीवी संक्रमण पुरुषों को पिता बनने में कर सकता है अक्षम

अनुसंधान

एक आम यौन संचारित वायरस ह्यूमन पेपिलोमावायरस (एचपीवी) पुरुषों में शुक्राणु की मात्रा और गुणवत्ता को कम कर सकता है। इससे पुरुष पिता बनने में अक्षम हो सकता है। एक ताजा अध्ययन में इसकी पुष्टि की गई है। शोध का निष्कर्ष फ्रंटियर्स इन सेलुलर एंड इन्फेक्शन माइक्रोबायोलाजी में प्रकाशित हुआ है।

अर्जेंटीना में यूनिवर्सिडैड नैशनल डी कार्डोबा के शोधकर्ताओं ने पाया कि पुरुष एचपीवी संक्रमणों के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं, इससे उनमें जननांग मस्सा और मुंह, गले, लिंग व गुदा में विकृति होने का जोखिम बढ़ने जैसी समस्याएं होती हैं। इसके कारण परेशानी कभी बढ़ जाती है, लेकिन सबसे प्रमुख समस्या पिता बनने में अक्षम होना है। माना जाता है कि संक्रमण के कारण शुक्राणुओं की क्षमता काफी कमजोर हो जाती है। शोध में उच्च जोखिम वाले एचपीवी जीनोटाइप से संक्रमित पुरुषों में आक्सीडेटिव तनाव और कमजोर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया से शुक्राणुओं के नष्ट होने के प्रमाण मिले।

यूनिवर्सिडैड नैशनल डी कार्डोबा में प्रोफेसर डा. वर्जीनिया रिवेरो ने कहा कि उच्च जोखिम वाले एचपीवी जीनोटाइप संक्रमण पुरुष के प्रजनन क्षमता और प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करते हैं। एचपीवी संक्रमण महिलाओं में आमतौर पर पाया जाता है, 95 प्रतिशत मामलों में सर्वाइकल कैंसर का खतरा होता है।

हालांकि, लैंसेट में हाल में प्रकाशित अध्ययन में पाया गया कि 15 वर्ष की आयु से ऊपर वाले तीन पुरुष जननांग एचपीवी से आंशिक रूप से संक्रमित होते हैं और पांच में एक पुरुष उच्च जोखिम वाले एचपीवी से संक्रमित होते हैं। ताजा अध्ययन अर्जेंटीना के 205 पुरुषों पर किया गया है, जो प्रजनन और मूत्र मार्ग संबंधी समस्याओं को लेकर 2018 से 2021 के बीच यूरोलाजी क्लिनिक पहुंचे थे। इनमें से किसी ने भी एचपीवी टीकाकरण नहीं करवाया था। 19 प्रतिशत लोग एचपीवी पाजिटिव पाए गए, 20 पुरुषों को एचपीवी का उच्च जोखिम और सात को कम जोखिम का एचपीवी था। (आइएएनएस)

स्क्रीन शाट

...तो यह था सायरा बानो का सबसे कीमती तोहफा

जन्मदिन पर पति दिलीप कुमार को सायरा ने किया याद। इंस्टाग्राम - @sairabanu

इंटरनेट मीडिया पर अभिनेत्री सायरा बानो अक्सर अपनी पुरानी यादों को साझा करती हैं। शुक्रवार को अपनी 80वीं जन्मतिथि के मौके पर सायरा ने अपनी कुछ तस्वीरें साझा कर बताया कि उनके लिए सबसे कीमती तोहफा दिवंगत अभिनेता और उनके पति दिलीप कुमार ने दिया था। सायरा ने लिखा कि एक शाम दिलीप कुमार मेरे पास आए। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि अरे तुम बड़ी होकर बेहद खूबसूरत हो गई हो। समय मेरे लिए वहीं थम गया था। हालांकि मुझे नहीं पता था कि वह हमारी सुंदर प्रेम कहानी की शुरुआत थी। 23 अगस्त, 1966 के दिन मैंने अपना जन्मदिन मनाया फिर अपने नए घर में गृह प्रवेश किया। उस घर को बड़ा सोच-समझकर चुना गया था, क्योंकि वह दिलीप साहब के घर के पास था। कई विकल्पों में से मैंने उनके करीब रहने के लिए उस घर को चुना था। मद्रास (अब चेन्नई) से फ्लाइट लेकर वह मेरे पास आए थे, मुझे आश्चर्य हुआ। उनके कहे शब्दों ने एक ऐसे बंधन की शुरुआत की जो जीवनभर के लिए बना। एक प्रशंसक से समर्पित पत्नी तक, मैं भाग्यशाली रही कि उनके व्यक्तित्व के अलग-अलग पहलुओं का अनुभव किया। उनकी शालीनता और सुंदरता ने मेरे दिल को ऐसे छुआ, जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आगे सायरा ने लिखा कि जन्मदिन की खुशी के बीच मेरा दिल दिलीप साहब के लिए तरस रहा है, उन्होंने हर एक दिन को उत्सव जैसा महसूस कराया था। काश वह इस दिन को खास बनाने के लिए यहां होते। खैर, भले ही वह शारीरिक रूप से मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनका प्यार मेरे दिल में जीवित है। उनकी यादों को संजोकर रखा है।

अरशद वारसी का पूरा वीडियो देखकर नानी ने दी सफाई

मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म अभिनेता अरशद वारसी द्वारा फिल्म कल्कि 2898 एडी में अभिनेता प्रभास को जोकर कहे जाने पर दक्षिण भारतीय अभिनेता नानी ने तीखी आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि जिस व्यक्ति का आप जिक्र कर रहे हैं, उसे अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्रचार मिला होगा। आप बेवजह एक महत्वहीन मामले का महिमामंडन कर रहे हैं। इस पर विवाद होने पर तेलुगु स्टार नानी ने सफाई दी है। उन्होंने इसे अनुवाद का मामला बताया है। बाद में, जब उन्होंने वारसी के उस वीडियो को देखा तो उनका नजरिया बदला। नानी के मुताबिक मैंने सिर्फ वही टिप्पणी सुनी थी, क्योंकि कट क्लिप सोशल मीडिया पर हर जगह थे। जब मैंने पूरा वीडियो देखा तब उनकी बात समझ सका। अरशद वारसी जी बहुत अच्छे अभिनेता हैं और हम सभी ने मुन्ना भाई में उन्हें बहुत पसंद किया, न केवल उत्तर या दक्षिण में, बल्कि पूरे भारत में। अभिनेता होने के नाते, हमें अपने शब्दों के चयन में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए।

सूर्याज सैटरडे में एक्शन अवतार में दिखेंगे नानी। इंस्टाग्राम - @nameisnani

नेशनल अवार्ड के बाद भी मार्केट से सब्जियां खरीद रहा हूं : राहुल चित्तेला

सफलता मिलने पर कई बार अहंकार आ जाता है। हालांकि गुलमोहर फिल्म के निर्देशक राहुल चित्तेला की जिंदगी में तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बाद भी कुछ नहीं बदला है। पिछले दिनों गुलमोहर को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, सर्वश्रेष्ठ स्क्रीनप्ले- संवाद और अभिनेता मनोज बाजपेयी को स्पेशल मेंशन मिला। क्या राहुल आगे फिल्मों को उसी ईमानदारी के साथ बना पाएंगे? इस पर वह कहते हैं कि हां, सच्चाई बरकरार रहेगी। अगर कहीं भटका, तो चाबुक मारकर खुद को रास्ते पर ले आऊंगा। सच्चाई बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप ईमानदार लोगों के बीच में रहें। एक किस्सा सुनाता हूं। शुक्रवार को इस अवार्ड की घोषणा हुई। शनिवार सुबह को मेरे बचपन के दोस्त का थाईलैंड से फोन आया कि अभी क्या कर रहा है। मैंने कहा कि सब्जी मार्केट में हूं, सब्जियां खरीद रहा हूं। जीवन में बदला कुछ नहीं है। जो करना है, वह कर रहा हूं। अवार्ड्स की घोषणा हुई, तब मैं बच्चे को खाना खिला रहा था। मनोज जी ने फोन किया कि टीवी नहीं देख रहे, हमें तीन राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। अवार्ड लेने कौन से डिजाइनर कपड़े पहनेंगे? राहुल हंसते हुए कहते हैं मेरी पत्नी इसमें मेरी मदद करेंगी।

राहुल निर्देशित फिल्म गुलमोहर को मिले हैं तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। फाइल

आइसलैंड में ज्वालामुखी में विस्फोट

आइसलैंड में रेक्जेनस प्रायद्वीप में फिर ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। गत वर्ष दिसंबर के बाद यह छठी बार है, जब इस क्षेत्र में ज्वालामुखी फटा है। भूकंप के तगड़े झटकों के क्रम में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद व्यापक पैमाने पर लावा तथा धुआं निकल रहा है। लगभग चार हजार निवासियों वाला निकट का ग्रिंडाविक कस्बा सुरक्षा के दृष्टिगत पिछले वर्ष के अंत में ही खाली करा लिया गया था। एएफपी

आठ दिन में तीन सौ करोड़ रुपये पार कर गई फिल्म स्त्री 2

फिल्म स्त्री 2 में एक संवाद था कि स्त्री कुछ भी कर सकती है। फिलहाल बाक्स आफिस की कमाई देखकर लग रहा है कि वाकई स्त्री कुछ भी कर सकती है। कमाई के मामले में फिल्म तेजी से आगे बढ़ते हुए मजह आठ दिनों में घरेलू बाक्स आफिस पर तीन सौ करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर गई है और 308 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। वहीं वर्ल्डवाइड चार सौ करोड़ का आंकड़ा पार करते हुए फिल्म ने 428 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। पहले सात दिनों में फिल्म ने घरेलू बाक्स आफिस पर 289.6 करोड़ रुपये कमाए थे। वहीं आठवें दिन स्त्री 2 में 18.2 करोड़ रुपये और जुड़ गए। वहीं खेल खेल में फिल्म ने आठ दिनों में 19.35 करोड़ रुपये और वेदा ने 17.6 करोड़ रुपये की कमाई की है। इसी बीच साल 2018 के बाद अब दोबारा रिलीज हुई फिल्म लैला मजनू ने 13 दिनों में 5.38 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। लैला मजनू को स्त्री, वेदा और खेल खेल में की रिलीज के कारण सिनेमाघरों से हटा दिया गया था। अब उसे फिर जगह मिल गई है। साल 2018 में लैला मजनू ने 2.20 करोड़ रुपये ही कमाए थे, जबकि अब युवाओं के बीच फिल्म को अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। आगामी दिनों में अब सीधे छह फिल्में और कंगना रनौत अभिनीत फिल्म इमरजेंसी रिलीज होगी। तब तक स्त्री, वेदा, खेल खेल में और लैला मजनू के लिए खुला मैदान है।

स्त्री 2 की कमाई जारी, वर्ल्डवाइड पांच सौ करोड़ की ओर बढ़ रही है फिल्म। फाइल